



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 3, 1940

No. 191]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 3, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

अंतिम जांच परिणाम

(केस संख्या: OI 19/2017)

**विषय – चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।**

**फा. सं. 6/12/2017-डीजीएडी.**— यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

2. मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने अनुरोध किया है, ताकि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया जा सके।

3. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 6/12/2017-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरु की गई थी, ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।
4. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को गलती से बिना किसी बहिष्करण से “हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न” के रूप में अभिज्ञात किया गया था, हालांकि स्वतः याचिका में कुछ उत्पादों को बहिष्कृत किया गया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से संबंधित दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना पर दिनांक 22 सितंबर, 2017 की अधिसूचना फाइल संख्या 6/12/2017-डीजीएडी द्वारा एक शुद्धिपत्र जारी किया था, जिसमें प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को “1000 डेनियर से कम, रंगीन यार्न और ट्विस्टेड यार्न को अपवर्जित करते हुए हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न” के बतौर अभिज्ञात किया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 को निर्धारित विचाराधीन उत्पाद और जांच की अवधि के साथ संशोधित याचिका दायर की गई थी।

#### ख. क्रिया-विधि

5. इस जांच में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (क) उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग की ओर से याचिकाकर्ताओं से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन होने और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाया गया है तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।
- (ख) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में सूचित किया था।
- (ग) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार प्राधिकारी ने जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की प्रति भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/संघों को प्रेषित की थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने लिखित विचारों से उन्हें अवगत करा दें।
- (घ) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों को उपलब्ध कराई गई थी। आवेदन-पत्र की एक प्रति ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने उसके लिए अनुरोध किया था।
- (ङ) भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश से उत्पादकों और निर्यातकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
- (च) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

1. झेजियांग गुक्सिआनडाओ न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
2. झेजियांग यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाईबर कंपनी लिमिटेड
3. जिआंगसू हैंगली केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड
4. हैंगझाऊ हुआचुन केमिकल फाईबर ड्राईंग एंड बीविंग कंपनी लिमिटेड
5. ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड
6. ह्योसंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड

7. झेजियांग हेलिडे न्यू मेटेरियल कंपनी लिमिटेड  
(छ) निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. झेजियांग गुक्सिआनडाओ इंडस्ट्रियल फाईबर कंपनी लिमिटेड
2. झेजियांग गुक्सिआनडाओ पॉलिस्टर डोप डाईड कंपनी लिमिटेड
3. ह्योसंग केमिकल फाईबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड
4. ह्योसंग कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य
5. जिआंगसू हैंगली केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड
6. जिआंगसू तैजी न्यू मेटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
7. झेजियांग यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाईबर कंपनी लिमिटेड
8. हुझोऊ यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाईबर लिमिटेड
9. ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (मुझोउ) लिमिटेड
10. ऑरियंटल टेक्सटाइल (होलिंडंग) लिमिटेड

- (ज) मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य और उसके व्यापारी मैसर्स ह्योसंग कार्पोरेशन, कोरिया और मैसर्स जिआंगसू तैजी इंडस्ट्री न्यू मेटेरियल्स कंपनी लिमिटेड को छोड़कर चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए वर्तमान जांच में अन्य सहयोगी निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने अपने व्यापारी मैसर्स ह्योसंग कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और मैसर्स जिआंगसू तैजी इंडस्ट्री न्यू मेटेरियल्स कं. लि., चीन जन. गण. के साथ मिलकर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है और उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

- (झ) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:-

1. शक्ति कॉर्ड्स
2. टफरॉप्स
3. इंडिया नेट्स
4. फेरेटेरो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5. गारवारे वॉल रोप्स लिमिटेड
6. ऑटोलिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
7. मेक्केफेरी एन्वायरमेंट सालूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
8. पॉली होज इंडिया
9. स्ट्रेटा जिओसिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
10. मारूती रब प्लास्ट
11. एक्जिओम रोप्स
12. खोसला प्रोफाईल
13. टेकफैब इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- (ञ) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्धारित प्रपत्र में आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. शक्ति कॉर्ड्स
2. गारवारे वॉल रोप्स लिमिटेड
3. स्ट्रेटा जिओसिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
4. टेकफैब इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
5. ऑटोलिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
6. मधुराम फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7. मधुरा कोट्स प्राईवेट लिमिटेड
8. मेहतर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

## 9. वर्धमान यार्नस एंड थ्रेड्स लिमिटेड

- (ट) समय-समय पर ऐसे पक्षकारों से भी निवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए थे। ऐसे पक्षकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित पक्षकारों से भी टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और उन पर भी विचार किया गया है:-
1. चाईना चेम्बर ऑफ कामर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाईल्स
  2. झेझियांग हेलिडे न्यू मेटेरियल कंपनी लिमिटेड
  3. ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड
  4. सनरिहा टेक्निकल टेक्सटाईल्स लिमिटेड
- (ठ) वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान समय-समय पर भेजे गए पत्रों पर भी विचार किया गया है, जिनमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के मुद्दों पर की गई टिप्पणियां, पीसीएन पर टिप्पणियां, उत्पाद के बहिष्करण के दावे आदि शामिल हैं।
- (ड) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध कराया था। वर्तमान प्रकटन विवरण में सभी पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को शामिल किया गया है।
- (ढ) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (ण) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मंगवाई गई थी।
- (त) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।
- (थ) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उन्हें निर्मित करने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे “एनआईपी” कहा गया है) का आंकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क, घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (द) इस जांच के प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक समझा गया है, प्राधिकारी द्वारा 29-31 जनवरी, 2018 को घरेलू उद्योग और निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया गया था। इसी प्रकार, कुछ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और सूचनाओं का सत्यापन, प्राधिकारी द्वारा 02-07 अप्रैल, 2018 को चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया में स्थल पर किया गया था। जहां कहीं भी लागू होता है, वहां आवश्यक संशोधन के साथ केवल सत्यापित सूचना पर विश्वास किया गया है।
- (ध) यह जांच 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक (12 महीनों) की अवधि के लिए की गई थी (जिसे आगे “जांच की अवधि” अथवा “पीओआई” कहा गया है)। क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि भी शामिल है।
- (न) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने की व्यवस्था करें और डीजीसीआईएंडएस से ऐसी सूचना प्राप्त हो गई थी और उसे वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अपनाया गया है।

- (प) जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क और दी गई सूचना, जहां तक वे साक्ष्यों के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच में संगत मानी गई हैं, प्राधिकारी द्वारा उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (फ) याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों और उन पर प्राप्त हुई टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने पीसीएन वर्गीकरण संरचित किया था और उसे 20 मार्च, 2018 को परिचालित कर दिया था। पीसीएन वर्गीकरण के आधार पर निर्यातकों से संशोधित प्रश्नावली के उत्तर 27 मार्च, 2018 तक प्राप्त किए गए थे।
- (ब) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए 13 मार्च, 2018 को सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले जिन पक्षकारों ने अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त किया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में 20 मार्च, 2018 तक प्रस्तुत कर दें। पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और उन पर अपने प्रत्युत्तर 26 मार्च, 2018 तक प्रस्तुत कर दें।
- (भ) लिखित निवेदनों और प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों के साथ-साथ हितबद्ध पक्षकारों से समय-समय पर प्राप्त हुए पत्रों में दिए गए सुझावों पर वर्तमान जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- (म) नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने 4 मई, 2018 को जारी प्रकटन विवरण द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के अनिवार्य तथ्य भी प्रकट किए और उन्हें सलाह दी कि वे 14 मई, 2018 तक प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां दायर करें। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों को संगत मानी गई सीमा तक इस जांच परिणाम में हल कर दिया गया है।
- (य) अमरीकी डालर को भारतीय रूपयों में परिवर्तन करने के लिए जांच की अवधि के दौरान प्रचलित विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 67.95 रूपए है और प्राधिकारी द्वारा उसे अपनाया गया है।
- (कक) इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकार द्वारा \*\*\* सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।

#### **ग. विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र और "समान वस्तु"**

##### **उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन**

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के बारे में निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) एडहेसिव एक्टिवेटिड यार्न, 6000 से अधिक डेनियर और हाई माँड्यूलस लो थ्रिंकेज (एचएमएलएस) यार्न जैसे कुछ उत्पादों को अपवर्जित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद में संशोधन किया जाना चाहिए।
- (ख) 6000 से अधिक डेनियर वाले यार्न के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (ग) एडहेसिव एक्टिवेटिड यार्न के संबंध में यह निवेदन किया गया था कि घरेलू उद्योग 1000 से अधिक डेनियर वाले एचटीवीपी एडहेसिव एक्टिवेटिड यार्न की आपूर्ति करने में असमर्थ है।
- (घ) याचिकाकर्ता संपूर्ण श्रृंखला में एडहेसिव एक्टिवेटिड यार्न का स्थिर उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। यदि इन वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाते हैं, तो वे आरएफएल डिप्ड फैब्रिकों के उत्पादकों को अनावश्यक रूप से अप्रतिस्पर्धी बना देंगे।
- (ङ) याचिकाकर्ता ट्विस्टिड यार्न का उत्पादन नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें भी बाहर रखा जाना चाहिए।
- (च) एचएमएलएस यार्न के संबंध में यह निवेदन किया गया था कि एचएमएलएस यार्न अपने गुणधर्मों के कारण विशिष्ट हैं। यह दावा किया गया था कि घरेलू उद्योग उनकी आपूर्ति नहीं करता है। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता आरआईएल ने मौखिक सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया था कि उसने हाल ही में एचएमएलएस सुविधाओं को शुरू किया है। इसलिए जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता आरआईएल एचएमएलएस यार्न का उत्पादन और आपूर्ति नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य

याचिकाकर्ता – एसआरएफ उसके समग्र एचएमएलएस यार्न उत्पादन की कैप्टिवली खपत करता है और इसलिए एसआरएफ भी घरेलू बाजार में एचएमएलएस यार्न की आपूर्ति नहीं करता है।

- (छ) रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड नामक एक उत्पादक ने यह स्वीकार किया है कि उसके पास एचएमएलएस का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है और एसआरएफ लिमिटेड ने उसकी आपूर्ति नहीं की है जिसके लिए यह कारण बताया गया है कि वे केवल प्रयोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण विनिर्देशन वाले आर्डर पर ही उसका उत्पादन कर सकते हैं। वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान एचएमएलएस की आपूर्ति नहीं की है और इसके फलस्वरूप एचएमएलएस को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए और हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा किए जाने की प्रार्थना की है।
- (ज) उत्पादकों को एचएमएलएस यार्न के नमूने देने चाहिए जिसका प्रयोक्ता द्वारा परीक्षण किया जाएगा और उसे प्रयोक्ता की आवश्यकता के अनुसार अधिक परिष्कृत किया जाएगा। इसके लिए संयंत्र की प्रक्रिया में व्यापक विश्लेषण किया जाना और उत्पाद की सुसंगतता निहित है। उसके बाद उपभोक्ता के अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में न्यूनतम 2 वर्ष लगते हैं। अनुमोदन करने की लंबी अवधि को याचिकाकर्ताओं द्वारा लिखित निवेदनों और मौखिक सुनवाई में अच्छी तरह से स्वीकार किया है।
- (झ) 6000 से अधिक डेनियर्स, 1000 से अधिक डेनियर्स के एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न और एचएमएलएस गुणक्षमताओं से युक्त यार्न के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने का कोई मामला नहीं है।

#### **घरेलू उद्योग के विचार**

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
  - (क) विचाराधीन उत्पाद “हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न” है, जिसमें 1000 से कम डेनियर युक्त यार्न, ट्विस्टेड यार्न और रंगीन यार्न शामिल नहीं हैं।
  - (ख) एचएमएलएस यार्न के अपवर्जन के दावे के संबंध में यह निवेदन किया गया था कि घरेलू उद्योग के प्रत्येक संघटक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह समान वस्तु का उत्पादन करे। जांच की अवधि के दौरान एसआरएफ ने एचएमएलएस यार्न का उत्पादन और बिक्री दोनों कार्य किए हैं। उक्त उत्पाद का उपयोग केवल कैप्टिव खपत के लिए नहीं किया जा रहा है। एसआरएफ ने मैसर्स शक्ति कोर्ड्स नामक एक हितबद्ध पक्षकार को ऐसे यार्न को बेचने की पेशकश की है और इसलिए ऐसे तर्क का कोई औचित्य नहीं है कि ऐसे यार्न का उत्पादन नहीं किया जा रहा है और उसे बेचा नहीं जा रहा है।
  - (ग) यहां तक कि आरआईएल के पास एचएमएलएस यार्न का उत्पादन करने और बेचने की क्षमता है। तथापि, उत्पाद के अनुमोदन और विनिर्देशन की कमी के कारण उसकी आपूर्ति नहीं की गई है। मैसर्स शक्ति कोर्ड्स को उत्पाद की पेशकश करने के बावजूद बिक्री नहीं हो सकी है क्योंकि मैसर्स शक्ति कोर्ड्स उत्पाद के सही विनिर्देशन का पता लगाने के लिए यार्न का नमूना प्रदान करने में असमर्थ था।
  - (घ) रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान एचएमएलएस यार्न का उत्पादन किया गया था और उसकी बिक्री की गई थी।
  - (ङ) एचएमएलएस यार्न को अन्य श्रेणी के साथ मिलाने के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा विस्तृत पीसीएन वार वर्गीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है और इसलिए यह मुद्दा अवैध है।
  - (च) इसके अतिरिक्त नियम 2(ख) के अंतर्गत विधि में ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जांच की अवधि के दौरान संबंधित घरेलू उद्योग समान वस्तु की आपूर्ति करने में लगा हो। इसके बजाए इसे नियम 2(घ) के साथ पढ़ा जाए जिसमें यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को समान वस्तु का विनिर्माण करने के कार्य में लगे होने की आवश्यकता है।
  - (छ) 1000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न के अपवर्जन के अनुरोध के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के प्रत्येक संघटक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जांच की अवधि के दौरान वह समान वस्तु का उत्पादन करने में लगा हो। एसआरएफ ने 1000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न का उत्पादन किया है और उसकी बिक्री की है।

- (ज) कुछ किस्मों के यार्न का उत्पादन नहीं करना अथवा कम उत्पादन करने का कारण घरेलू उपभोक्ताओं की घरेलू उद्योग से खरीद करने में रुचि का नहीं होना था, न कि घरेलू उद्योग द्वारा उनका उत्पादन करने में असमर्थता था। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अपनी खपत के लिए आयात को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण ऐसे किस्म के उत्पाद की पाटित कीमतें थीं, न कि गुणवत्ता का मुद्दा था अथवा अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता थी।
- (झ) 1000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटिड यार्न का अपवर्जन करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, ऐसे दावों के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। विगत मामलों में प्राधिकारी ने यह माना है कि अपवर्जन का दावा करने के लिए ऐसे किस्म के उत्पाद के आयात होने चाहिए जिसके लिए अपवर्जन की मांग की गई है अथवा घरेलू उद्योग उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने में विफल रहा होना चाहिए। जहां ऐसा मामला नहीं बनता है, वहां विचाराधीन उत्पाद से अपवर्जन का दावा करना अनुचित है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद *“हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न है, जिसमें 1000 डेनियर से कम, रंगीन यार्न और ट्विस्टिड यार्न शामिल नहीं हैं”*, जिसे बाजार की शब्दावली में पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के नाम से जाना जाता है। हाई टेनेसिटी इंडस्ट्रियल ग्रेड यार्न के विभिन्न ग्रेड होते हैं, जो कि अंत अनुप्रयोग की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं, जैसे कि रेगुलर एडहेसिव एक्टिवेटिड (एए), रेगुलर एडहेसिव नॉन-एक्टिवेटिड (एनएए), हाई मॉड्यूलस लो थ्रिक्ज एडहेसिव एक्टिवेटिड (एचएमएलएसएए), हाई मॉड्यूलस लो थ्रिक्ज एडहेसिव नॉन-एक्टिवेटिड (एचएमएलएस एनएए), लो थ्रिक्ज (एलएस), सुपर लो थ्रिक्ज (एसएलएस), अल्ट्रा लो थ्रिक्ज (यूएलएस) और डोप डाईड यार्न।
9. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग व्यापक किस्मों के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टॉयर कोर फैब्रिक, सीट बेल्ट बेविंग, जिओ ग्रिड्स, जिओ स्ट्रिप्स, स्लिंग्स, रोप्स, सिंगल कोर्ड, कोटिड फैब्रिक, कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक, फायर होज, ऑटोमेटिक होज आदि। विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 में सीमा-शुल्क शीर्ष 5402 2090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित प्रावधान इस प्रकार है:- *“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।*
11. हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक किस्मों के उत्पादों को इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की मांग की है कि घरेलू उद्योग बांछित किस्म के उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है और/अथवा ऐसे उत्पाद की नियमित रूप से आपूर्ति नहीं करता है अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अथवा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता प्रयोक्ताओं को संतुष्ट नहीं करती है। याचिकाकर्ताओं की कंपनियों के परिसरों में स्थल पर सत्यापन करके और हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध सूचना मंगाकर हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच की गई है।
12. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में पीसीएन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों से आंकड़े प्राप्त किए गए थे। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 12 मार्च, 2018 के अपने पत्र द्वारा पीसीएन को स्पष्ट किया था। प्राधिकारी ने उसे हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया था और उस पर उनकी टिप्पणियां मांगीं थीं। पीसीएन के वर्गीकरण के संबंध में और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए अपनाए गए परीक्षण मानदंड के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। तदनुसार और साथ ही घरेलू उद्योग के साथ परिचर्चा करने के बाद प्राधिकारी ने 16 मार्च, 2018 को पीसीएन का वर्गीकरण जारी किया था और संशोधित प्रश्नावली के उत्तर 27 मार्च, 2018 तक अवश्यक प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तदनुसार, घरेलू उद्योग से भी संशोधित आंकड़े मंगाए गए थे और वे प्राप्त हो गए थे।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के आधार पर कुछ किस्मों के यार्न के अपवर्जन के निम्नलिखित चार दावों की जांच करने की आवश्यकता है:-

- (क) ट्विस्टिड यार्न;

- (ख) 6000 से अधिक डेनियर युक्त यार्न;
- (ग) 1000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड कोटिंग वाले यार्न और
- (घ) हाई मॉड्यूलस लो थ्रिंकेज (एचएमएलएस) गुणक्षमताओं युक्त यार्न

14. अपवर्जन के दावों की जांच करने से पहले प्राधिकारी यह उल्लेख करना चाहेंगे कि दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक तकनीकी यार्न है। ऐसे यार्न का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के तकनीकी रूप से विनिश्चित फैब्रिक्स/वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए इस तथ्य से मनाही नहीं की जा सकती है कि इन यार्न के बड़े भाग के लिए खरीद करने के निर्णय में तकनीकी विशिष्टता अथवा निष्पादन की अपेक्षा के कुछ स्तर का सत्यापन करना/पता लगाया जाना शामिल होगा। खरीद करने का निर्णय, केवल कीमत आधारित नहीं हो सकता है। जबकि प्राधिकारी इसके कारण का पता नहीं लगा सकते हैं कि किसी विशिष्ट उत्पादक/आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की पेशकश को क्यों स्वीकार अथवा अस्वीकृत किया गया था, उन्हें ऐसा विश्वास है कि वास्तविक उत्पादन/विक्री निष्पादन पर आधारित कोई भी निर्णय दोनों पक्षकारों के लिए उचित है।
15. ट्विस्टेड यार्न के अपवर्जन के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ट्विस्टेड यार्न शामिल नहीं है। इस प्रकार कोई भी एचटीपीवाई ट्विस्टेड यार्न वर्तमान जांच के दायरे से बाहर है। घरेलू उद्योग ने याचिका दायर करते समय निम्नलिखित किस्मों के यार्न को स्वतः विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा है:-
- (क) 1000 से कम डेनियर युक्त यार्न;
  - (ख) ट्विस्टेड यार्न और
  - (ग) रंगीन यार्न
16. इस प्रकार अपवर्जन के लिए उपरोक्त दावा अनावश्यक है।
17. एडहेसिव एक्टिवेटेड कोटिंग युक्त और 1000 से कम डेनियर युक्त और एचएमएलएस यार्न के अपवर्जन के दावों के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:-

		एच यार्न डेनियर > 1000		एचएमएलएस यार्न	
		एसआरएफ	आरआईएल	एसआरएफ	आरआईएल
उत्पादन	यूनिट	***	शून्य	***	शून्य
व्यापारी की बिक्रियां	मी.टन	***	शून्य	***	शून्य
उत्पादन में व्यापारी की बिक्रियों का प्रतिशत	%	0.78%	शून्य	1.74%	शून्य

18. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग के पास 2000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न का उत्पादन और आपूर्ति करने की क्षमता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की व्यापारिक बाजार में 1000 से अधिक और 2000 तक के डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न की बिक्रियां नगण्य हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का महत्व है कि याचिकाकर्ता "पूर्ण शृंखला में" एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न की आपूर्ति नहीं करते हैं। हालांकि एसआरएफ ने जांच की अवधि के दौरान 1000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न का उत्पादन किया है, लेकिन उसने वाणिज्यिक रूप से अपने उत्पादन के 1% से भी कम भाग की बिक्री की है। इस प्रकार 1000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न को विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान जांच में शामिल करना उचित नहीं होगा। तदनुसार, प्राधिकारी का वर्तमान जांच के लिए 1000 से अधिक डेनियर युक्त एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है।
19. एचएमएलएस गुणक्षमताओं से युक्त यार्न के अपवर्जन के दावे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि एचएमएलएस यार्न एक ऐसा यार्न है, जिसकी विभीतीय स्थिरता, दीर्घीकरण अथवा दाब से स्ट्रेचिंग किए बिना और ताप का



अनुप्रयोग किए जाने के बावजूद उसके सिकुड़ने के बिना बनी रहती है। हम नोट करते हैं कि जारी किए गए पीसीएन के वर्गीकरण के रूप में एचएमएलएस यार्न के लिए परीक्षण का मानदंड, उसका “विभीतीय स्थिरता सूचक” 10 से कम है। आयामीय स्थिरता सूचकांक 4 सीएन/डीटीईएक्स पर लंबाई की मात्रा (एसीटीएम डी885 के अनुसार परीक्षित) तथा 0.05 सीएन/डीटीईएक्स सिरा भार (एएसटीएम डी4794 के अनुसार परीक्षित) पर 2 मिनट के लिए 177 डिग्री. से. पर हॉट एयर स्रिकेज के रूप में मापा जाता है। एचएमएलएस यार्न का उपयोग, टायरकोर्ड्स (यात्री कारों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त टायरों के भीतर इनफोर्समेंट के रूप में), मेकेनिकल रबड़ वस्तु उद्योग के लिए कनवेयर्स और वी-बेल्टों जैसे उत्पादों के लिए किया जाता है।

20. निर्यातकों और घरेलू उद्योग से पीसीएन वार सूचना प्राप्त होने पर यह देखा गया था कि आरआईएल ने जांच की अवधि के दौरान एचएमएलएस यार्न का उत्पादन नहीं किया था। हालांकि एसआरएफ ने जांच की अवधि के दौरान एचएमएलएस यार्न का उत्पादन किया था, लेकिन उसने एचएमएलएस यार्न के अपने उत्पादन के 2% से कम भाग को बेचा था। इस प्रकार एचएमएलएस यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र के भीतर शामिल करना उचित नहीं होगा। तदनुसार, प्राधिकारी का वर्तमान जांच के लिए एचएमएलएस यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है।
21. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने 6000 डेनियर से अधिक वाले यार्नों को हटाए जाने पर यह समझ कर विचार नहीं किया था कि ये यार्न वास्तव में ट्विस्टेड यार्न हैं। चूंकि, ट्विस्टेड यार्नों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से पहले ही अलग कर दिया गया था, अतः 6000 डेनियर से अधिक वाले यार्नों को अलग से हटाए जाने की मंजूरी देना आवश्यक नहीं समझा गया था। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षकारों ने 6000 डेनियर से अधिक वाले फ्लैट/अनट्विस्टेड यार्नों के आयातों के संबंध में प्राधिकारी की जानकारी में साक्ष्य दिए हैं। इसी के आलोक में प्राधिकारी यह पाते हैं कि 6000 डेनियर से अधिक वाले एचटी यार्नों को हटाए जाने के लिए दावा वैध है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर यह भी पाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का 6000 डेनियर से अधिक वाले हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न का कोई उत्पादन अथवा बिक्री नहीं है और इसीलिए उसके संबंध में कोई घरेलू आपूर्ति अथवा प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। तदनुसार, 6000 डेनियर से अधिक वाले यार्नों को हटाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के दावे को स्वीकार किया जाता है।
22. उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न के रूप में माना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

- (क) 1000 से कम डेनियर युक्त यार्न;
- (ख) 6000 से अधिक डेनियर युक्त यार्न;
- (ख) ट्विस्टेड यार्न;
- (ग) रंगीन यार्न और
- (घ) एचएमएलएस गुणक्षमताओं से युक्त यार्न

#### **घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार**

##### **उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

23. जांच की कार्यवाही के दौरान घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) याचिकाकर्ताओं ने अपनी उत्पादन क्षमता के ब्यौरे प्रकट नहीं किए हैं, हालांकि ऐसी सूचना उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। याचिकाकर्ताओं की उत्पादन क्षमता को हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न के लिए माना जाना चाहिए न कि समग्र औद्योगिक यार्न भाग के लिए। याचिकाकर्ता बहुविधि उत्पादों के विनिर्माता हैं और केवल संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की उनकी क्षमता पर ही विचार किया जाना चाहिए।
- (ख) एसआरएफ नामक एक याचिकाकर्ता, “कैप्टिव खपत” के लिए संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माता है और वह अपने उत्पादन के मामूली भाग को घरेलू बाजार में बेचता है। इसलिए ऐसे उत्पाद को “घरेलू बिक्रियों के लिए विनिर्माता” के रूप में घरेलू उद्योग का एक संघटक नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने “आस्ट्रेलिया और चीन

जनवादी गणराज्य से लो एश मेटल्लुर्जिकल (2016) के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणाम और सेस्टेट के निर्णय का हवाला दिया है।

- (ग) घरेलू उद्योग ने एसआरएफ लिमिटेड के कैप्टिव उत्पादन के ब्यौरे प्रदान नहीं किए हैं। इसके बजाए उसने रिकार्ड पर कोई संबद्ध साक्ष्य दिए बिना ऐसा मान लिया है कि वह घरेलू उद्योग का एक संघटक है और वर्तमान जांच में शामिल करने अथवा बाहर रखने के लिए एसआरएफ लिमिटेड का निर्धारण करने के लिए उसके कैप्टिव उत्पादन की कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) एसआरएफ लिमिटेड नामक एक याचिकाकर्ता संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का एक आयातक है और इसलिए उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार बाहर रखा जाए।
- (ङ) एसआरएफ लिमिटेड के जांच की अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से आयात लगभग 71482 मी. टन हैं और ये कुल आयातों में लगभग 4.64% भाग बनते हैं, जो कि पर्याप्त हिस्सा है।
- (च) घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र में एसआरएफ लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों का कोई मात्रात्मक ब्यौरा नहीं दिया है। यह देखा जा सकता है कि प्राधिकारी ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से सेलेमाईन (2018) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों पर गोपनीयता बनाए रखने का दावा करने की अनुमति नहीं दी है।
- (छ) चूंकि एक याचिकाकर्ता स्वतः एक आयातक है, हालांकि उसने उत्पादों की भिन्न श्रृंखला को पूरा किया है, ऐसी आशंका है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता बड़ी हुई कैप्टिव क्षमता का उपयोग करने लगेगा जिसकी संपूर्ति इस समय संबद्ध वस्तुओं के आयात से की जा रही है।
- (ज) यह स्वीकार्य तथ्य है कि भारत में मैसर्स फेयरडील जुम्बो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड नामक एक तीसरा उत्पादक भी है। इसके अतिरिक्त वह बाजार में कार्यचालन कर रहा है और उसे कोई क्षति नहीं हो रही है।
- (झ) वर्तमान मामले में उत्पादकों/निर्यातकों का संरचित सामान्य मूल्य, याचिकाकर्ताओं की कैप्टिव लागतों के आधार पर संरचित नहीं किया जा सकता है और न ही याचिकाकर्ताओं की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) भी मुख्यतया याचिकाकर्ताओं की इस कैप्टिव कीमत पर आधारित हो सकती है।

#### **घरेलू उद्योग के विचार**

24. घरेलू उद्योग के दायरे और उसके आधार के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
  - (क) याचिकाकर्ताओं का घरेलू उत्पादन में पर्याप्त प्रतिशत भाग बनता है और इसलिए वर्तमान याचिका को प्रस्तुत करने में उनका आवश्यक आधार है। यह मानते हुए कि घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादक का भी कुछ भाग बनता है, तब भी याचिकाकर्ताओं का उत्पादन में पर्याप्त प्रतिशत भाग बनता है और इसलिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ उनका आधार है।
  - (ख) याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तुओं की केवल कटिबद्ध क्षमता के ब्यौरे प्रदान किए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में पर्याप्तता और परिशुद्धता के लिए आंकड़ों को पहले से ही सत्यापित कर लिया गया है।
  - (ग) कैप्टिव क्षमता का तात्पर्य यह नहीं है कि उत्पादक घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के अयोग्य है। एसआरएफ लिमिटेड ने अपनी 56% क्षमता का कैप्टिवली उपयोग किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह “निजी-खपत” के लिए उत्पादन नहीं कर रहा था। हालांकि क्षति अवधि के प्रारंभ में कैप्टिव खपत कम थी, फिर भी एसआरएफ लिमिटेड मांग में वृद्धि होने से कैप्टिव खपत को बढ़ाने में भी समर्थ रहा था, लेकिन वह पाटित आयातों के कारण अपनी घरेलू बिक्रियों को समनुरूप बढ़ाने में असमर्थ था। इस प्रकार इस अवधि के दौरान उत्पादन की तुलना में कैप्टिव खपत के अनुपात में वृद्धि हुई है।
  - (घ) विगत में प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के कैप्टिव उत्पादकों को पात्र घरेलू उद्योग माना है। चीन जनवादी गणराज्य से विटामिन ई (2003) के मामले में अंतिम जांच परिणाम पर विश्वास किया गया है।

- (ड) "आस्ट्रेलिया और चीन जनवादी गणराज्य से लो एश मेटल्लुर्जिकल (2016)" के मामले के तथ्य और परिस्थितियां वर्तमान तथ्यों से विशेषणीय हैं क्योंकि उक्त मामले में घरेलू विक्रियां नगण्य थीं, जबकि एसआरएफ लिमिटेड की अत्यधिक व्यापारिक विक्रियां हैं।
- (च) प्राधिकारी कैप्टिव खपत के निमित्त उत्पादन को बाहर रखने के बाद याचिकाकर्ताओं के आधार पर विचार कर सकते हैं।
- (छ) आयात करने के तथ्य मात्र के फलस्वरूप उक्त उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर रखने के संबंध में निष्कर्ष को छोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इस संबंध में प्राधिकारी के विशेषाधिकार के विद्यमान होने का पता चलता है।
- (ज) शुल्क लागू किए जाने की स्थिति में आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए बड़ी हुई कैप्टिव खपत से संबंधित दावा पूर्णतया निराधार है। मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड निर्यात करने के प्रयोजन से निचले स्तर के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है। शुल्क लागू किए जाने के बाद भी ऐसी पद्धति सुगमता से निरंतर जारी रखी जा सकती है।
- (झ) मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड के आयात किए जाने के संबंध में शक्ति कोर्ड्स के निवेदन गलत हैं। घरेलू उद्योग द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के मात्र 50.4 मी. टन आयात किए हैं। इसलिए मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा किए गए आयात, संबद्ध देश से आयातों का केवल 0.3% भाग है, जो कि नगण्य है। यदि ये आयात 4% बनते हैं, जैसा कि शक्ति कोर्ड्स ने दावा किया है, तब भी ये विशिष्ट भाग नहीं बनेंगे, जब कि ऐसे आयात, निर्यात करने के प्रयोजन से अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत किए गए थे।
- (ञ) मैसर्स फेयरडील जुम्बो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लेने का विकल्प अपनाया है और इसलिए घरेलू उद्योग उसके कार्यचालन और क्षति की कमी के बारे में किए गए दावों की सच्चाई पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना उसके बारे में वक्तव्य मात्र दिए हैं। सुनवाई के दौरान एक हितबद्ध पक्षकार ने यह स्पष्ट किया था कि मैसर्स फेयरडील जुम्बो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का उत्पादन नगण्य है और निकृष्ट कोटि का है, जिससे पता चलता है कि उत्पादक अच्छा कार्य निष्पादन नहीं कर रहा है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:—  
*"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में लगे हुए हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*
26. आवेदन-पत्र मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक दो उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने यह दावा किया है कि भारतीय उत्पादन में उनका उत्पादन 90% से भी अधिक बनता है। यह तथ्यपरक स्थिति है कि मैसर्स फेयरडील जुम्बो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड नामक तीसरा उत्पादक भी है। तथापि, उक्त उत्पादक आगे नहीं आया है और जांच के प्रयोजनार्थ किसी भी पक्षकार ने अपनी उत्पादन क्षमताओं के बारे में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जांच के प्रयोजनार्थ किसी भी पक्षकार द्वारा रिकार्ड पर कोई भी सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने और मैसर्स फेयरडील जुम्बो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जांच में भाग नहीं लेने की स्थिति में प्राधिकारी यह मानते हैं कि क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उक्त उत्पादक पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घरेलू उद्योग के संघटकों के रूप में माना है।
27. इसके अतिरिक्त विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे दावे किए गए हैं कि मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड को उसकी कैप्टिव खपत और उसके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से आयात किए जाने के तथ्य के कारण पात्र घरेलू उद्योग का संघटक नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड को उसके द्वारा

उत्पादन के लिए कैप्टिवली खपत की गई मात्रा और व्यापारिक बाजार में बेची गई मात्रा का सत्यापन करके एक कैप्टिव उत्पादक के रूप में माना जा सकता है। यह देखा गया है कि एसआरएफ का उत्पादन अपनी खपत और व्यापारिक बिक्री के बीच वितरित किया गया है। इसके आलोक में मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड को एक कैप्टिव उत्पादक के रूप में माना जाना और व्यापारिक बाजार में उसके उत्पादन के जाने की अनदेखी करना अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड को घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में शामिल करने से क्षति के प्राचलों को अधिक सुव्यवस्थित ढंग से समझा जा सकेगा। इसलिए वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे तथ्यों से सुसंगत नहीं हैं।

28. इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेकाधिकार को बनाए रखते हैं कि क्या एक उत्पादक को, उसके द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जाने के बावजूद भी घरेलू उद्योग माना जा सकता है। वर्तमान मामले में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता - मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मामूली मात्रा 0.5% से भी कम है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाना अनुचित होगा कि मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड का मुख्य व्यवसायिक क्रियाकलाप संबद्ध वस्तुओं का आयात करना है। प्रकटन पश्चात स्तर पर किए गए अनुरोधों के आलोक में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता एसआरएफ इतने आंशिक आयात का उन्हें अथवा याचिकाकर्ताओं, दोनों को साथ मानकर, को हुई क्षति में योगदान नहीं हो सकता तथा नहीं रहा।
29. इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का प्रमुख भाग बनता है। इस जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं और वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के संघटक बनते हैं।

#### **ड. अत्यधिक गोपनीयता**

##### **उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

30. जांच की कार्यवाही के दौरान अत्यधिक गोपनीयता के बारे में निर्यातकों/आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:—
- (क) याचिकाकर्ता याचिका में और जांच की कार्यवाही के दौरान जटिल और मुख्य सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। सामान्यतया ऐसे आंकड़ों का प्रकटन प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण और/अथवा अंतिम जांच परिणाम जारी करने के समय किया जाता है और इसलिए उसे गोपनीय बनाए रखने और विरोधी पक्षकार को तथ्यपरक स्थिति का निवारण करने के अवसर से वंचित रखे जाने का कोई कारण नहीं है। इस संबंध में विभिन्न मामलों को उल्लेख किया गया था।
- (ख) याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाकर्ताओं की क्षमता, कैप्टिव खपत, भारतीय मांग, घरेलू उद्योग के उत्पादन की मात्रा, कुल भारतीय उत्पादन, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा, घरेलू उद्योग के निर्यातों की मात्रा, क्षमता उपयोग, याचिकाकर्ताओं के घरेलू बाजार का हिस्सा, अन्य भारतीय उत्पादकों, संबद्ध देश से आयात और ऐसे देशों से आयात, जो कि जांच के अधीन नहीं हैं, जैसे मुख्य प्राचलों की अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- (ग) इसके अतिरिक्त, प्रपत्र-IV(क) में निर्धारित कुछ प्राचलों को गोपनीय रखा गया है और वे सभी पक्षकारों को प्रदान नहीं किए गए हैं और ये सूचीबद्ध भी नहीं हैं। ऐसे प्राचलों में कैप्टिव खपत मूल्य, कैप्टिव खपत रहित बिक्रियों की मात्रा से संबंधित आंकड़े शामिल हैं और साथ ही इनमें कैप्टिव खपत, कैप्टिव खपत रहित मांग की मात्रा से संबंधित आंकड़े और कुल बिक्रियों की मात्रा की कैप्टिव खपत, माल-सूचियां (मात्रा) – प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक, निर्यात बिक्रियों से संबंधित बिक्रियों के आंकड़े, ब्याज, मूल्य ह्रास, विस्तार के लिए पूंजीगत निवेश, निबल अचल परिसम्पतियां और कार्यशील पूंजी भी शामिल है। यहां तक कि लाभ/हानि और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के प्रतिशत के आंकड़ों के साथ-साथ निर्यात की मात्राओं को गोपनीय रखा गया है।
- (घ) घरेलू उद्योग ने आवेदकों के कंपनी-वार उत्पादन और साथ ही अन्य घरेलू उत्पादक के उत्पादन अथवा भारतीय उत्पादकों के कुल घरेलू उत्पादन में अंशदान के ब्यौरे प्रदान नहीं किए हैं। घरेलू उद्योग ने मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड के कैप्टिव उत्पादन के ब्यौरे भी प्रदान नहीं किए हैं।
- (ङ) याचिकाकर्ता बहुविध उत्पाद कंपनियां हैं और इसलिए उनके उत्पाद-विशिष्ट वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

- (च) मौखिक सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसे कुछ आंकड़ों का प्रकटन किया गया है, जिनकी गोपनीयता का दावा किया गया है, जिससे उनके द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे अमान्य हो जाते हैं।
- (छ) याचिकाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, ताकि पक्षकारों को कैप्टिव खपत की मात्रा जो कि बहुत अधिक है, क्षमता उपयोग के स्तर जो कि अनुकूलतम है और मांग में हुई वृद्धि (42%) को पूरा करने के लिए आयात प्रवेश कर रहे हैं, जो कि याचिकाकर्ता की अनुकूलतम क्षमता से अधिक है, स्पष्ट रूप से समझने से रोका जा सके।
- (ज) याचिकाकर्ता अपने आयातों और संबद्ध वस्तुओं के आयातकों और निर्यातकों के साथ उनके संबंध की घोषणा करने में विफल रहे हैं।
- (झ) याचिकाकर्ताओं ने याचिका के एक भाग के रूप में कॉस्टिंग प्रपत्र संलग्न नहीं किया है। यहां तक कि कच्चे माल के नामों और अन्य संबद्ध व्यौरों और साथ ही अन्य संबद्ध सूचना की गोपनीयता का भी दावा किया गया है, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया के व्यौरों को समझने में सहायक होती है।
- (ञ) याचिकाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने का एक मात्र उद्देश्य ऐसी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने से रोकना है कि कैप्टिव खपत की मात्रा बहुत अधिक है, क्षमता उपयोग का स्तर अनुकूलतम है और मांग में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए आयात प्रवेश कर रहे हैं, जो कि याचिकाकर्ता की अनुकूलतम क्षमता से अधिक है।

#### **घरेलू उद्योग के विचार**

31. अत्यधिक गोपनीयता के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:—
- (क) याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि निर्यातकों/उत्पादकों ने गोपनीयता के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय वृत्तान्त में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन/विक्रियों में लगे संबंधित पक्षकारों की सूची, विचाराधीन उत्पाद के विनिर्देशनों, उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त पीसीएन, घरेलू और निर्यात विक्रियों, घरेलू विक्रियों की मात्रा और मूल्य को प्रमाणित करने के लिए प्रदत्त दस्तावेजों की सूची, मुख्य कच्चे माल की सूची आदि जैसी कुछ जटिल सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है।
- (ख) अपेक्षित आवेदन-पत्र के प्रपत्र में लागत सूचना के संबंध में सभी संबद्ध आंकड़े प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्षति के सभी प्राचल सूचीबद्ध रूप में प्रदान किए गए हैं, जो कि पक्षकारों को गुण-दोष पर मामले में तर्क देने के लिए पर्याप्त हैं।
- (ग) उत्पाद विशिष्ट आंकड़े प्रदान करने के दावे विधि में अपेक्षित प्रावधान से परे हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जहां किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए आंकड़ों को अभिज्ञात करना संभव नहीं है, वहां उत्पादकों की संकुचित श्रृंखला पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त न तो मैसर्स एसआरएफ और न ही मैसर्स आरआईएल उत्पाद विशिष्ट तुलन-पत्र अथवा लाभ और हानि के विवरण बना कर रखता है।
- (घ) विषमतः उत्पादकों और निर्यातकों ने गोपनीयता से संबंधित प्रावधानों का दुरुपयोग किया है और ऐसी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है, जिनका प्रकटन बमशिकल उनके हितों के प्रतिकूल होगा। इसके अतिरिक्त, किन्हीं प्रवृत्तियों और सूचीबद्ध आंकड़ों का प्रकटन भी नहीं किया गया है और अधिकतर मामलों में आंकड़ों का उचित अगोपनीय सारांश भी प्रदान नहीं किया गया है।
- (ङ) कैप्टिव खपत से संबंधित आंकड़ों का प्रकटन, मैसर्स एसआरएफ की कैप्टिव खपत के वास्तविक व्यौरों का प्रकटन करने के समान होगा, जो कि उसके लिए हानिकर होगा।
- (च) यह दावा निराधार है कि याचिकाकर्ताओं ने पक्षकारों और प्राधिकारी को इस तथ्य के संबंध में कि याचिकाकर्ता अनुकूलतम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, से भ्रमित करने के लिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इन तथ्यों

को मानते हुए भी भारत में ऐसे आयात पाटित नहीं किए जा सकते हैं और वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, जो कि वस्तुतः स्थिति है।

- (छ) क्षमता के व्यौरों की गोपनीयता का दावा किया गया है क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कटिबद्ध क्षमता से बल्कि समग्र औद्योगिक यार्न का उत्पादन करने की उसकी क्षमता से संबंधित है, जिसके आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
- (ज) इस दावे के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं को अपने आयातों और संबद्ध वस्तुओं के आयातकों और निर्यातकों के साथ उनके संबंध के बारे में घोषणा करनी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के निर्धारित प्रपत्रों में ऐसे किसी अधिदेश की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सभी संबद्ध सूचना प्रदान की गई है।
- (झ) सूचीबद्ध प्रपत्र में घरेलू उद्योग के प्रत्येक संघटक के लिए उत्पादन के व्यौरों अथवा अंशदान की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समग्र घरेलू उद्योग के लिए क्षति के प्राचल प्रदान करने की आवश्यकता है और उन्हें व्यवसाय संवेदी सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने की आवश्यकताओं के अध्यधीन विधिवत प्रदान कर दिया गया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

- 32. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत सूचना की जांच, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा उसे सार्वजनिक फाईल में खुला नहीं रखा है। इसके साथ ही प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम और अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों पर भी विचार किया है।
- 33. याचिकाकर्ताओं द्वारा कम सूचना प्रदान करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सूचना निर्धारित प्रपत्र के अनुसार थी और मामले के गुण-दोष से संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू की है।

### **च. विविध मुद्दे**

#### **उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

- 34. विभिन्न मुद्दों के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी किए गए कुछेक निवेदन निम्नानुसार हैं:—
- (क) प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने संबंधी सूचना गैर-कानूनी है और यह भारतीय पाटनरोधी नियमावली और विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अधिदेश से बाहर है और इसलिए संबद्ध जांच को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस दावे का आधार देर से जारी किया गया शुद्धि-पत्र है और यह वर्तमान मामले में अनुचित रूप से जांच शुरू करने के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
- (ख) याचिकाकर्ताओं ने याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त (एनसीवी) को 21 जून, 2017 को प्रस्तुत किया था। उसके बाद 18 जुलाई, 2017 को अन्य अगोपनीय वृत्तान्त (एनसीवी) प्रस्तुत किया गया था जिसमें विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तन कर दिया गया था और आंकड़ों को यह उल्लेख करते हुए पूरा किया गया था कि विगत अगोपनीय वृत्तान्त (एनसीवाई) में असावधानी पूर्वक कुछ गलतियां हो गई थीं। प्राधिकारी के शुद्धि-पत्र पर याचिका को अन्य वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया था। परिवर्तनीय वृत्तान्त याचिका को समाप्त करने का अधिकार देता है।
- (ग) याचिकाकर्ताओं ने केवल अद्यतन आंकड़े प्रदान किए हैं और संपूर्ण याचिका प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों के लिए भी अद्यतन करने की प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों में व्यापक परिवर्तन किया गया है, जिनको न्याय संगत बनाने की आवश्यकता है।
- (घ) प्राधिकृत पत्र और परिशुद्धता का प्रमाण-पत्र जांच की समाप्ति पर पूर्व-दिनांकित है।

- (ड) याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान जांच में आईबीआईएस के साथ-साथ डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं।
- (च) जांच शुरू करने के बाद निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पीसीएन उचित नहीं है और यह एचएमएलएस जैसे विशिष्ट उत्पादों के लिए परिकलन करने में विफल है।

### **घरेलू उद्योग के विचार**

35. विविध मुद्दों के बारे में निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कुछेक अन्य निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) मैसर्स ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गारवरे बॉल रोप्स लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इन पक्षकारों ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं देने का विकल्प चुना है।
  - (ख) प्राधिकारी के साथ परिचर्चा करने पर और विचाराधीन उत्पाद से कुछ उत्पादों को बाहर रखने तथा जांच की अवधि में परिवर्तन कर दिए जाने के कारण याचिका में परिवर्तन किया गया है। ऐसे लगाए गए आरोपों का स्पष्ट उद्देश्य याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की विश्वसनीयता को अनावश्यक रूप से नष्ट करना है।
  - (ग) याचिकाकर्ताओं ने जांच शुरू करने के समय विचाराधीन उत्पाद के लिए विधिवत् प्रलेखित याचिका प्रस्तुत की थी। उसके बाद जब प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू किए जाने के समय जांच की अवधि में परिवर्तन किया गया था, तब 13 अक्टूबर, 2017 को जांच की अवधि के लिए अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार याचिकाकर्ता जांच शुरू किए जाने के बाद एक नया आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे।
  - (घ) 17 मार्च, 2017 (सीवी) और 21 जून, 2017 (एनसीवी) को याचिका प्रस्तुत करने के समय याचिका के साथ परिशुद्धता के प्रमाण पत्र और प्राधिकार पत्र विधिवत् संलग्न किए गए थे। फिर भी चूँकि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया है, इसलिए ऐसे दावे निराधार हैं।
  - (ङ) आयात के कारोबार-वार आंकड़े प्रदान करने के संबंध में निवेदन है कि इन्हें प्राधिकारी को प्रदान कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को इन आंकड़ों को एक्सल रूपान्तर में उपलब्ध कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - (च) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में टिप्पणियों के अनुसार और सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श करके प्रयुक्त पीसीएन कार्यप्रणाली जारी की है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

36. उपरोक्त विभिन्न मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान निम्नानुसार किया गया है:—
- (क) प्राधिकारी जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना का शुद्धि पत्र जारी करना गैर-कनूनी नहीं समझते हैं। इसके अतिरिक्त, यह अस्पष्ट है कि उत्पादों का अपवर्जन कैसे किया गया है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र द्वारा किया गया है, जो कि हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्रतिकूल रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी का जांच शुरू करने के बाद यह निष्कर्ष है कि कुछ उत्पादों का अपवर्जन करने की मेरिट है और इसलिए पक्षकारों को उसके बारे में सूचित किया गया है।
  - (ख) यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में परिवर्तनीय याचिकाएं असुविधाजनक और पाटनरोधी जांच में समयबद्ध कार्रवाई करने के विपरीत है। तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जहां प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और जांच की अवधि में परिवर्तन किया है, यह पाया गया है कि जैसी आवश्यकता थी, याचिकाकर्ता आंकड़ों में संशोधन करने के लिए पूर्णतया न्यायसंगत थे।
  - (ग) याचिकाकर्ताओं का यह दायित्व है कि वे अद्यतन जांच की अवधि के लिए सभी संबद्ध सूचना प्रदान करें, जो कि किया गया है।
  - (घ) अद्यतन जांच की अवधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राधिकार पत्र और प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दावे वर्तमान मामले के तथ्यों में मेरिट के बिना हैं। प्राधिकारी ने दोनों याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों

- को सत्यापित किया है और उनकी संवीक्षा की है और इसलिए ऐसे प्राधिकार पत्र और प्रमाण पत्र के नहीं होने के कारण किसी भी तरीके से कार्रवाई विकृत नहीं हुई है और न ही इसके कारण हितबद्ध पक्षकारों को कोई हानि हुई है।
- (ङ) पीसीएन से संबंधित मुद्दे का निदान विचाराधीन उत्पाद के मुद्दों के अंतर्गत कर दिया गया है। तथापि, यह देखा गया है कि यहां रिकार्ड किए गए निवेदन, पीसीएन को अंतिम रूप दिए जाने से पहले किए गए थे और इसलिए ये मेरिट रहित हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की टिप्पणियों के आधार पर पीसीएन का निर्धारण किया है। वास्तव में वर्तमान मामले में अपनाए गए पीसीएन ने हितबद्ध पक्षकारों के दावों का निदान कर दिया है।
- (च) आयात आंकड़े प्रदान करने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी यह उल्लेख करना चाहेंगे कि दिनांक 14 मार्च, 2018 की व्यापार अधिसूचना संख्या 7/2018 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी लिखित अनुरोध के आधार पर वैध आवेदक को डीजीसीआईएस से आयात के आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करेंगे। तथापि, आवेदक/याचिकाकर्ता उद्योग द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के समय डीजीएडी को प्रस्तुत आयात आंकड़ों की हार्ड कॉपी (संसाधित/परिवर्तित आंकड़े) को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा निर्धारित घोषणा-पत्र/वचनबद्धता देने पर ही किया जा सकता है। इसलिए यह दायित्व हितबद्ध पक्षकारों का है कि वे विश्लेषण के लिए कारोबार-वार आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार-पत्र प्राप्त करें।
- (छ) याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि मैसर्स ऑटोलिव और मैसर्स गारवारे ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए वे असहयोगी हैं, पूर्णतया निराधार है। प्राधिकारी को इन पक्षकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

#### **छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

##### **उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

37. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/ आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:—
- (क) संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य की संरचना विकट रूप से त्रुटिपूर्ण है। सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त खपत के मानदंड प्रदान नहीं किए गए हैं। सामान्य मूल्य में विचारित समस्त संघटक जैसे कि कच्चे माल की लागत, उपयोगिता, परिवर्तनीय लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत पर याचिकाकर्ताओं के अनुसार विचार किया गया है, जो कि विश्व व्यापार संगठन के करार और भारतीय पाटनरोधी नियमावली का उल्लंघन है।
- (ख) वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत अथवा भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना को, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सूचीबद्ध पूर्व दो विकल्पों पर विचार करने के बाद सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए एक ठोस आधार माना जा सकता है। ऐसे विकल्पों को अपनाए बिना ऐसी कार्य-प्रणाली को प्रयुक्त करना, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 की अपेक्षाओं का स्पष्ट उल्लंघन करना है।
- (ग) यदि प्राधिकारी भारत में घरेलू उत्पादकों के अनुभव के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य पर विश्वास करते हैं, तो उसका आधार केवल अत्यधिक कुशल घरेलू उत्पादक होना चाहिए। प्राधिकारी की यही सुसंगत पद्धति है और उन्हें इससे विचलित नहीं होना चाहिए।
- (घ) इसके अतिरिक्त यदि उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दर्जा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्पादक/निर्यातक के खपत के मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए।
- (ङ) याचिका में निर्यात कीमत में समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन अथवा उसके आधार का समायोजन करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (च) निर्यात कीमतों से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समायोजन के दावे बहुत अधिक हैं जिसके फलस्वरूप वर्तमान जांच में पाटन के दावे बढ़ा-चढ़ा कर किए गए हैं। वर्तमान जांच की शुरुआत गलत तथ्यों के आधार पर की गई है।
- (छ) उत्पादकों/निर्यातकों के संरचित सामान्य मूल्य को याचिकाकर्ताओं की कैप्टिव लागतों के आधार पर संरचित नहीं किया जा सकता है और न ही याचिकाकर्ताओं की क्षति रहित कीमत (एनआईपी), मुख्यतया याचिकाकर्ताओं की इस कैप्टिव कीमत पर आधारित हो सकती है।



- (ज) प्राधिकारी को उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर पहले सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत पर और उसके बाद पाटन मार्जिन पर विचार करना चाहिए।
- (झ) यह कि विश्व व्यापार संगठन के चीन अभिगमन नयाचार के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, घरेलू विक्रयों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर होना चाहिए क्योंकि एनएमई व्यवहार के लिए 15 वर्ष की अवधि 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई है।
- (ञ) यह कि व्यापार संगठन के चीन अभिगमन नयाचार के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार पाटनरोधी कार्रवाई में “प्रतिनिधि देश” की पद्धति, 11 फरवरी, 2016 से बहुपक्षी कानूनी आधार रही है। ऐसी पद्धति समाप्त और उन पर लागू नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा भारतीय जांच प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे इस मामले में सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि क्या चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, “प्रतिनिधि देश” की कार्य-प्रणाली प्रयुक्त नहीं करें।
- (ट) *पेक्टो सेंट सर्वेडा* – एक मूल सिद्धांत है और इस अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत दायित्व का अभिप्राय यह है कि कोई भी पक्षकार चीन के उद्यमियों के साथ पक्षपात पूर्ण ढंग से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अथवा घरेलू विधियों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत अपने दायित्वों की अपवचना नहीं करेगा, जो कि अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है। इस प्रकार, भारत को चीन की संपूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था को मान्यता देने के लिए और संबद्ध घरेलू विनियमों में संशोधन करके संबद्ध करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए ताकि चीन के खिलाफ पाटनरोधी जांच में “प्रतिनिधि देश” के उपागम को प्रयुक्त करना बंद किया जा सके। चीन अभिगमन नयाचार का अनुच्छेद 15 संबद्ध प्रावधान है, जिसमें यह निर्देश है कि सभी सदस्य देशों को “प्रतिनिधि देश” के उपागम को प्रयुक्त करना बंद करना चाहिए।

### **घरेलू उद्योग के विचार**

38. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:—
- (क) घरेलू उद्योग ने याचिका प्रस्तुत करते समय उसके पास उचित रूप से उपलब्ध आंकड़े प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी को जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ साक्ष्य की परिशुद्धता और पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। *ऑटोमेटिव टायर मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2011)* के मामले में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य की संतुष्टि का निर्धारण, जांच शुरू किए जाने के समय याचिकाकर्ता के उत्पादन की लागत के आधार पर किया जा सकता है।
- (ख) हितबद्ध पक्षकारों ने स्वतः कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों पर विश्वास करना चाहिए।
- (ग) इसके अतिरिक्त, सहभागी उत्पादकों और निर्यातकों ने वास्तविक सूचना को छिपाया है और अयथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है।
- (घ) हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि यदि सामान्य मूल्य घरेलू उत्पादकों की लागत पर आधारित होता है, तो यह अत्यधिक कुशल घरेलू उत्पादक की लागत पर आधारित होना चाहिए। ऐसे दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त, विदेशी उत्पादकों की कार्यकुशलता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
- (ङ) इसके अतिरिक्त, और बिना किसी पूर्वाग्रह के अत्यधिक कुशल घरेलू उत्पादक ऐसा उत्पादक नहीं हो सकता है, जिसके उत्पादन की निम्नतर लागत हो। बल्कि कार्य-कुशलता का निर्धारण करने के लिए अनेक कारकों को शामिल किया जा सकता है।
- (च) याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया निर्यात कीमत का समंजन, वास्तविक व्यय के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में श्रेष्ठ अनुमानों पर आधारित है। वास्तविक व्यय की सूचना केवल निर्यातक के पास है। चूंकि, निर्यातकों ने निर्यात की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके अब जांच में भाग लेना शुरू कर दिया है, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर निर्यात कीमत परिकलित की जा सकती है, यदि यह सभी पहलुओं पर संपूर्ण पाई जाती है और सत्यापन करने पर परिशुद्ध और विश्वसनीय पाई जाती है।

- (छ) निर्यातकों ने इस बात का विरोध नहीं किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राशि अत्यधिक है अथवा कुछ समायोजन का याचिकाकर्ता द्वारा उस खर्च के लिए दावा किया गया है जो नहीं किया गया। चूंकि, निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर जांच में अब भाग लिया है, अतः निर्यात कीमत का परिकलन उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया जा सकता है, यदि वह हर दृष्टि से पूरी पाए जाए और सत्यापन पर शुद्ध एवं विश्वसनीय पाई जाए।
- (ज) इसके अतिरिक्त, निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वस्तुओं के बेचने में शामिल प्रत्येक व्यापारी की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन का उचित ढंग से परिकलन और समायोजन किया गया है।
- (झ) यह भी उल्लेख किया जाता है कि निर्यातकों द्वारा रिकार्ड विदेशी भाषा में बना कर रखे जाते हैं और इसलिए किसी भी स्थिति में न केवल प्राधिकारी को यह पता लगाया जाना चाहिए कि प्रदत्त सूचना, प्राप्त की गई सूचना है और उसका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाए, बल्कि साथ ही प्राधिकारी को अनुवादक की सेवाओं का भी लाभ उठाना चाहिए ताकि क्योंकि प्राधिकारी और दल इन भाषाओं को समझ नहीं पायेंगे।
- (ञ) प्राधिकारी को उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना और किए गए दावों से संबंधित सार्थक प्रकटन विवरण तैयार करना चाहिए। साथ ही प्राधिकारी को उत्पादकों/निर्यातकों की सत्यापन रिपोर्टों, निर्यातक के साथ पत्राचार और उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरों, वास्तविक पाटन मार्जिन का प्रकटन भी करना चाहिए।
- (ट) वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक (12 महीनों) की है। क्षति की जांच की अवधि में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि भी शामिल है। चूंकि जांच की पर्याप्त अवधि, उपरोक्त प्रावधान की समाप्ति से पहले पड़ती है, इसलिए चीन जनवादी गणराज्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना जा सकता है।
- (ठ) चूंकि सामान्य मूल्य की संरचना घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है, इसलिए एनसीवी में उसके व्यौरे प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं।
- (ड) यह नोट करना प्रासंगिक है कि हालांकि सामान्य मूल्य की संरचना करने की कार्य-प्रणाली पर हितबद्ध पक्षकारों ने आपत्ति व्यक्त की है, फिर भी निर्यातक ने उचित तृतीय देश के बारे में सुझाव देने और उस समय प्रचलित घरेलू कीमतों के बारे में सूचना प्रस्तुत करने जैसा कुछ भी नहीं किया है, जिससे जांच में सहायता मिलेगी। इससे स्पष्ट पता चलता है कि निर्यातक प्राधिकारी को भ्रम में डालने के उद्देश्य से कठिनाई उत्पन्न कर रहा है और वर्तमान जांच में बाधा डाल रहा है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

#### **छ.1 चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

39. जहां तक चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण हो रही क्षति का तथ्य जांच की अवधि के आधार पर सिद्ध है। जांच की अवधि के दौरान विद्यमान स्थितियां ही वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए संगत, उपयुक्त और आवश्यक हैं। वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017 है। चूंकि, जांच की अधिकतर अवधि के दौरान अनुच्छेद 15 का उप पैरा विद्यमान था। अतः प्राधिकारी उस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं जो चीन जन. गण. में घरेलू कीमतों अथवा लागतों की सख्ती से तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह न दर्शा सकें कि विनिर्माण, उत्पादन और उस उत्पाद की बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।
40. यह भी नोट किया जाता है कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन. गण. को नियमावली के संदर्भ में निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों द्वारा अवधारणा के खंडन के अध्यधीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।
41. जांच की शुरुआत के चरण में प्राधिकारी ने इस अवधारणा से कार्रवाई की कि चीन जन. गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। जांच की शुरुआत कर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की

प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें कि वे संगत सूचना उपलब्ध कराएं।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित तरीके एवं प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता के संबंध में ज्ञात चीनी उत्पादकों/निर्यातकों तथा चीन जन. गण. सरकार को पर्याप्त रूप से अधिसूचित कर दिया गया है और उन्हें इस संबंध में अपने अनुरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी जांच की शुरुआत की सूचना के परिणामस्वरूप निम्नलिखित चीनी कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
  - i. झेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.;
  - ii. झेजियांग गुक्सियांडाओ पॉलिस्टर डोप डाइट कं. लि.;
  - iii. ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि.;
  - iv. ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य;
  - v. जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.;
  - vi. जियांग्सू तैजी न्यू मैटेरियल्स कं. लि.;
  - vii. झेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि. और
  - viii. हुझोऊ उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर लि.
  - ix. ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड और
  - x. ऑरियंटल टेक्सटाइल्स (होल्लिंग) लिमिटेड
44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि., चीन जन. गण. तथा उसके व्यापारी, मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य और मैसर्स जियांग्सू तैजी न्यू मैटेरियल्स कं. लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली दायर की है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किया।
45. निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर और इन उत्तरदाता उत्पादकों एवं निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की गई। बाजार अर्थव्यवस्था के दावे से संबंधित रिकार्डों का स्थल सत्यापन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में किया गया था। सत्यापनों के कारण बाजार अर्थव्यवस्था दावे के संबंध में स्थिति निम्नलिखित रूप में संक्षेप में दी गई है।
 

**(i) मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि., चीन जन. गण. और ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार**
46. मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि., चीन जन. गण. (एचसीएफ) और उसके व्यापारी, मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (ह्योसंग - कोरिया) द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का स्थल सत्यापन क्रमशः चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य में कंपनियों के परिसरों में किया गया और विस्तृत सत्यापन रिपोर्टें उन्हें उस पर टिप्पणियां देने के लिए जारी की गईं।
47. प्राधिकारी ने एचसीएफ के रिकार्डों का विस्तारपूर्वक सत्यापन किया। यह नोट किया गया कि एचसीएफ ह्योसंग - कोरिया के पूर्ण नियंत्रण में प्रचालन करता है जो कोरिया गणराज्य में आधारित है और जो एचसीएफ का अंतिम शेयरधारक है। निदेशक बोर्ड में पूर्णतः कोरियाई नागरिक हैं और एचसीएफ के निदेशक बोर्ड में कोई चीनी (सरकार अथवा अन्यथा) नागरिक नहीं हैं। भारतीय ग्राहकों में बिक्रियों की स्थितियों के लिए वार्ताएं ह्योसंग कोरिया द्वारा सीधे ही की जाती हैं और आदेश एचसीएफ को पारदर्शी एसएपी प्रणाली के माध्यम से दिए जाते हैं। घरेलू बिक्रियों के लिए ह्योसंग - कोरिया द्वारा एचसीएफ को चीनी ग्राहकों के साथ बिक्री की शर्तों के संबंध में वार्ता करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रमुख कच्ची सामग्री असंबद्ध कंपनियों से ली जाती है। यह भी नोट किया गया था कि कच्ची सामग्री के लिए एचसीएफ की खरीद कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को दर्शाती है। यह भी सुनिश्चित किया गया था कि वस्तु का उपभोग वार्ता के आधार पर तय की गई दरों पर आधारित है अथवा सभी प्रयोक्ताओं के लिए सार्वभौमिक रूप से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार, कोई विशेष अथवा सब्सिडीयुक्त दर नहीं लगाई जाती है।

48. प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की कि क्या एचसीएफ की प्रक्रियाओं में कोई सरकारी हस्तक्षेप है अथवा नहीं है। यह पाया गया कि कंपनी कोरियाई वर्तमान कंपनी के अधिदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों अर्थात् आईएफआरएस के अनुसार, अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्टों का रख-रखाव करती है। यह एचसीएफ के वित्तीय रिकार्डों को ह्योसंग के वित्तीय रिकार्डों में आसान समेकन के लिए किया जाता है। उसकी भी जांच की गई है। प्राधिकारी ने यह भी सत्यापित किया कि एचसीएफ में भर्ती सीधे श्रम बाजार से अथवा आंतरिक संदर्भों के माध्यम से चीन में श्रम कानून के कार्यवाहों के अंतर्गत की जाती है।
49. एचसीएफ विदेशी मुद्रा लेन-देनों को सूचित मुद्रा लेन-देनों में बदलने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम दिन को विदेशी विनिमय राज्य प्रशासन द्वारा घोषित दरों के अनुसार वाणिज्यिक विनिमय दर अपनाती है। एचसीएफ के निर्यात राजस्व का प्रयोग करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।
50. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि एचसीएफ ने चीन के संपत्ति कानून अथवा दिवालिया कानून, कंपनी कानून, श्रम कानून, लेखाकरण कानून, संविदा कानून के तहत कोई छूट स्वयं नहीं दी। यह पाया गया कि कंपनी लाभ की वापसी के वितरण अथवा निवेश की गई पूंजी पर किसी प्रतिबंध के अधीन नहीं है।
51. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने व्यापारी मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के रिकार्डों का भी सत्यापन किया।
52. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि., चीन जन. गण. (एचसीएफ) तथा उसके व्यापारी, मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (ह्योसंग) ने यह सिद्ध करने के लिए सूचना तथा पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि एचसीएफ बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत प्रचालन कर रही है और इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर के लिए पात्र है।

**(ii) मैसर्स जियांग्सू तैजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कं. लि., चीन जन. गण. (जेटीएनएम) के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार**

53. चीन में सत्यापन दौर के दौरान जेटीएनएम ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि कंपनी अपने एमईटी दावे को वापस लेना चाहेगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने जेटीएनएम के दावे को के अनुरोध को स्वीकार किया और उसे वापस लेने की अनुमति दी। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित पैराओं में उल्लिखितानुसार नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

**(iii) मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि., चीन जन. गण. (एचसीएफ) और मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (ह्योसंग) के लिए सामान्य मूल्य**

54. उत्पादक/निर्यातक को ऊपर बताए गए अनुरोध बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करते हुए पाया गया।
55. एचसीएफ द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचसीएफ ने जांच की अवधि के दौरान भारत को केवल एक पीसीएन का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने उसी पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। यह नोट किया गया कि जांच की अवधि के दौरान एचसीएफ ने घरेलू बाजार में तुलनीय पीसीएन के \*\*\* मी. टन की बिक्री की है। घरेलू बाजार में सभी बिक्रियां जांच की अवधि के दौरान गैर-संबद्ध पक्षकारों को की गई थीं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री लेन-देन करने के लिए लाभ निर्धारित करने हेतु व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि अपनाई। यह नोट किया गया कि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम थे, तदनुसार, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।
56. एचसीएफ ने अंतर्देशीय भाड़ा और घरेलू बिक्री कीमत से ऋण व्यय के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उसके लिए समायोजनों की अनुमति दी है। तदनुसार, एचसीएफ के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य \*\*\* अमेरिकी डॉलर/ मी. टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

**(iv) एचसीएफ को छोड़कर चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

57. चूंकि, एमईटी के स्तर का अंतिम रूप से दावा चीन जन. गण. में केवल एक उत्पादक (जांचकर्ता दल के निर्यातक सत्यापन दौर के दौरान एमईटी के लिए मैसर्स जियांग्सू तैजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कं. लि., चीन जन. गण. के अपने अनुरोध को वापस लेने का) द्वारा ऊपर बताए गए अनुसार किया गया था, अतः प्राधिकारी चीन जन. गण. को ऊपर उल्लिखित अपवाद के साथ वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उपयुक्त समझते हैं तथा चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाई करते हैं।

58. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में घरेलू बिक्री कीमतों, अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित किसी दूसरे देश में ऐसे तीसरे देश से निर्यात कीमतों के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, तथापि, यदि सामान्य मूल्य उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता तो निर्दिष्ट प्राधिकारी वास्तव में दी गई कीमत अथवा समान उत्पाद के लिए भारत में देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं जिसमें उपयुक्त लाभ मार्जिन समायोजित किया गया।
59. उपर्युक्त के मद्देनजर, भारत में चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार कर तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उपयुक्त लाभ मार्जिन उपयुक्त रूप से जोड़े जाने के बाद "किसी अन्य आधार" के आधार पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, जांच की अवधि के लिए प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य निम्नलिखित बनता है:

पीसीएन	भारित औसत सीएनवी डॉलर/मी. टन
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
औसत	***

**छ2. चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**

- (i) **मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि., चीन जन. गण. (एचसीएफ) और मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (ह्योसंग) के लिए निर्यात कीमत**
60. एचसीएफ ने अपने संबंधित व्यापारी ह्योसंग के साथ प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। एचसीएफ ने अपने व्यापारी ह्योसंग के माध्यम से भारत में \*\*\* मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। एचसीएफ ने अंतर्देशीय भाड़ा और पत्तन सार-संभाल व्यय, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण व्यय और बैंक प्रभार के निमित्त समायोजनों का दावा

किया। उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने ह्योसंग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन भी किया है और नोट करते हैं कि जिस कीमत पर ह्योसंग ने भारत में संबद्ध सामानों की बिक्री की, उसमें उसके एसजीए व्यय शामिल हैं और ह्योसंग को उपयुक्त लाभ मार्जिन भी देता है। यह नोट किया जाता है कि ये खर्चों तथा लाभ मार्जिन भी प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप उत्पादक निर्यातक के लिए कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यात कीमत से हटाए गए थे। तदनुसार, भारित औसत निर्यात कीमत एचसीएफ ह्योसंग के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

**(ii) ज़ेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि., चीन जन. गण. (गुक्सियांडाओ आईएफ) और ज़ेजियांग गुक्सियांडाओ पॉलिस्टर डोप डाइड यार्न कं. लि., चीन जन. गण. (गुक्सियांडाओ पीडीडी) के लिए निर्यात कीमत**

61. गुक्सियांडाओ आईएफ और गुक्सियांडाओ पीडीडी, दोनों संबद्ध सामानों के संबंधित उत्पादक हैं और दोनों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। गुक्सियांडाओ पीडीडी जांच की अवधि के दौरान गुक्सियांडाओ आईएफ के लिए औद्योगिक यार्न के कार्य प्रसंस्करण में भी लगा हुआ था। अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन सार-संभाल व्यय, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण व्यय और बैंक प्रभार के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया। उचित सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, भारित औसत निर्यात कीमत गुक्सियांडाओ आईएफ - गुक्सियांडाओ पीडीडी के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

**(iii) मैसर्स जियांग्सू तैजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कं. लि., चीन जन. गण. (जेटीएनएम) के लिए निर्यात कीमत**

62. जेटीएनएम ने यह सूचित करते हुए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को केवल "हार्ड मॉड्यूलस लो स्प्रिंग" यार्न का ही सीधे निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण व्यय और बैंक प्रभार के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया है। तथापि, प्राधिकारी के विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एचएमएलएस यार्न (सभी डेनियरों के) को छूट देने के लिए प्राधिकारी के निर्णय से निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की गई है।

**(iv) जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि., चीन जन. गण. (जेएचसीएफ) के लिए निर्यात कीमत**

63. जेएचसीएफ द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने स्वयं द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों का भारत में सीधे ही निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण व्यय और बैंक प्रभार के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया। उचित सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, भारित औसत निर्यात कीमत जेएचसीएफ के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

**(v) ज़ेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि., चीन जन. गण. और हुझोउ उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर लिमिटेड, चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत**

64. जेडयूआईएफ और एचयूआईएफ द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी संबद्ध सामानों के उत्पादकों से संबंधित है। एचयूआईएफ ने जेडयूआईएफ के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और जेडयूआईएफ ने स्वयं द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों का भारत में निर्यात सीधे ही किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन सार संभाल व्यय, कमीशन, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण व्यय और बैंक प्रभार के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया। उचित सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, भारित औसत निर्यात कीमत जेडयूआईएफ और एचयूआईएफ के लिए \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

**(vi) ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड (ओटीआईजेड) और मैसर्स ऑरियंटल टेक्सटाइल्स (होल्लिंग) लिमिटेड, चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत**

65. ओटीआईजेड और ओटीटीआई द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओटीआईजेड ने ओटीटीआई के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया गया कि ओटीआईजेड ने कुछ नमूना निर्यात लदान हवाई जहाज द्वारा भी निर्यात किया है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के परिकलन के लिए इन नमूना लेन-देनों पर विचार नहीं किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन सार संभाल व्यय, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और ऋण व्यय के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया। उचित सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, ओटीटीआई के माध्यम से ओटीआईजेड के लिए भारित औसत निर्यात कीमत \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

66. इस संबंध में प्राधिकारी ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. द्वारा उसके सीधे निर्यात के संबंध में किए गए अनुरोध को हल करना उपयुक्त मानते हैं। ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. द्वारा उठाया गया दावा सही नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लि. का एक लेन-देन है जो उसके व्यापारिक चैनल के माध्यम से बजाए उसके द्वारा सीधे ही निर्यातित किया गया है। तथापि, वह वाणिज्यिक बिक्री नहीं है बल्कि नमूने की आपूर्ति का

मामला है। इसे ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, नमूने की आपूर्तियों से संबंधित सभी लेन-देन विचार किए जाने से अलग कर दिए गए हैं क्योंकि व्यापार की साधारण अवधि में ये विक्रियां नहीं हैं। तदनुसार, हम ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. के उसे शुल्क तालिका में उत्पादक एवं निर्यातक माने जाने के अनुरोध को अस्वीकृत करते हैं।

**(vii) चीन जन. गण. के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। चीन जन. गण. ने सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों के आधार पर \*\*\* अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की है।

**छ.3 चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण**

68. पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए भारत में निर्यात कीमत की तुलना सामान्य मूल्य से की गई है। पाटन मार्जिन विश्लेषण पीसीएन-वार किया गया है। संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित किया गया है।

**पाटन मार्जिन तालिका**

देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अमेरिकी डॉलर/मी. टन	निबल निर्यात कीमत अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन (रेंज %)
चीन जन. गण.	ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि.	ह्योसंग कारपोरेशन	***	***	***	***	नकारात्मक
चीन जन. गण.	1. झेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.  2. झेजियांग गुक्सियांडाओ पॉलिस्टर डोप डाइड यार्न कं. लि.	झेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि., चीन जन. गण.	***	***	***	***	15-25
चीन जन. गण.	जियांगसू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	जियांगसू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	20-30
चीन जन. गण.	1. हुझोउ उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर लिमिटेड  2. झेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.	झेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	25-35
चीन जन. गण.	ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि.	ऑरियंटल टेक्सटाइल (होल्लिंग) लि.	***	***	***	***	नकारात्मक
चीन जन. गण.	कोई अन्य संयोजन	कोई अन्य संयोजन	***	***	***	***	45-55

69. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन काफी हैं और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि. और ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. को छोड़कर सभी उत्पादकों – निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं।

**ज. क्षति का निर्धारण एवं कारणात्मक संपर्क**

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी भी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाएं "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए .....". कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में कीमतों में अन्यथा कोई कटौती हुई है अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में हो गई होती।
71. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

**घरेलू उद्योग के क्षति दावों के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

72. घरेलू उद्योग के क्षति दावों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए दावों के संबंध में जांच के दौरान निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क.** क्षति एवं कारणात्मकता के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में याचिकाकर्ताओं की ओर से विफलता नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं का उल्लंघन है कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य जांच की शुरुआत का औचित्य बताने के लिए "पर्याप्त" हों।
- ख.** क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री जैसे याचिकाकर्ता के आर्थिक मानदंड जांच की अवधि में तथा क्षति की अवधि में सुधरे हैं।
- ग.** आंकड़े 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्षमता में गिरावट दर्शाते हैं। जब जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर था तो क्षमता में इस गिरावट का कारण नहीं बताया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि आयातों के कारण क्षमता में कोई गिरावट आई है।
- घ.** जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग उच्चतम स्तर पर था। इस प्रकार, इस निमित्त कोई क्षति नहीं हुई। उत्पादन में समान वृद्धि देखी जाती है तथा इस मानदंड पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को भी नकारा जाता है।
- ङ.** याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र में स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी जांच की अवधि में स्थिर है और क्षति जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में 11 प्रतिशत की वृद्धि है।
- च.** उत्पादन एवं बिक्री आंकड़ों की तुलना से यह सिद्ध है कि उत्पादन एवं बिक्री एक-दूसरे के आस-पास रहे। यदि कुछ है तो बिक्री के आंकड़े उत्पादन आंकड़ों से काफी अधिक बढ़े।
- छ.** कुल बिक्री में गिरावट घरेलू बाजार में बिक्री करने की अर्थक्षमता के कारण नहीं है। इसके बजाए, बढ़ी हुई कैप्टिव खपत दर्शाती है। यह सिद्ध है कि घरेलू उद्योग की कुल बिक्री के संबंध में सूचकांक में "गिरावट" याचिकाकर्ताओं की कैप्टिव खपत में काफी वृद्धि और उत्पादन में सीमित वृद्धि दर्शाती है।
- ज.** ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इष्टतम क्षमता उपयोग पर निष्पादन कर रहे हैं और इसीलिए बढ़ती हुई बाजार मांग को पूरा करने के लिए बिक्री बढ़ाने में असमर्थ हैं जो मांग 42 प्रतिशत तक बढ़ी है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं की क्षमता स्थिर रही है और कैप्टिव खपत काफी बढ़ी है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की आपूर्ति और भारतीय बाजार की मांग के बीच के अंतराल को साधारणतः पूरा कर रहे हैं।
- झ.** चूंकि, बिक्री के आंकड़े कैप्टिव खपत के सहित और उसको अलग करके नहीं दिए गए हैं, अतः कैप्टिव खपत के बिना और कैप्टिव खपत के बिक्री के सूचकांक के साधारण औसत के आधार पर यह पाया जाता है कि क्षति जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में 41 प्रतिशत की वृद्धि है।
- ञ.** घरेलू उद्योग ने कैप्टिव खपत सहित मांग के ब्यौरे भी नहीं दिए हैं, अतः चूंकि, बिक्री 41 प्रतिशत तक बढ़ी है, अतः घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी वृद्धि दर्शाएगा और बाजार हिस्से के संबंध में भी घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होगी।
- ट.** घरेलू उद्योग की कुल बिक्री के संबंध में सूचकांक में गिरावट याचिकाकर्ताओं का दुर्बल निर्यात निष्पादन दर्शाता है।
- ठ.** याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई क्षति उनके बढ़ी हुई कैप्टिव खपत और दुर्बल निर्यात निष्पादन के कारण है। आवेदक उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात में क्षति जांच की अवधि में 74 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।



- ड. याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई क्षति घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण है। इस संबंध में, एसआरएफ की वार्षिक रिपोर्टें उल्लिखित हैं।
- ढ. घरेलू उद्योग ऐतिहासिक रूप से हानियों में है और ये हानियां संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो सकतीं। इसकी बजाए, यह घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हैं।
- ण. याचिकाकर्ताओं की नियोजित बढ़ी हुई पूंजी तथा परिणामस्वरूप मूल्यहास और व्याज लागत में अचल परिसंपत्तियों में किसी वृद्धि के बिना वृद्धि के कारण उसके लाभ में गिरावट आई है।
- त. यह भी अनुरोध है कि नियोजित पूंजी में कोई वृद्धि, जो भावी कमीशनिंग के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा किए जा रहे क्षमता विस्तार से संबंधित है, एनआईपी परिकलन का आधार नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ताओं के लिए निर्मित एनआईपी में वह एक कारक न हो।
- थ. चीन जन. गण. से तथाकथित आयातों के परिणामस्वरूप कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण से संबंधित दावे केवल विवरण हैं। यह सामान्य उद्योग की जानकारी है कि कच्ची सामग्री अर्थात् पीटीए और एमईजी/पॉलिस्टर चिप्स संबद्ध सामानों की कीमत निर्धारित करते हैं और इसीलिए संबद्ध सामानों की कीमतों में उतार-चढ़ाव कच्ची सामग्री की कीमत के कारण हैं। कच्ची सामग्री में एचटीपीवाई की कुल उत्पादन लागत का लगभग 80-90 प्रतिशत होता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप है न कि चीन जन. गण. से तथाकथित पाटन के कारण।
- द. संबद्ध आयातों और घरेलू कीमतों के बीच समानांतर कीमत प्रवृत्तियों की मौजूदगी ही कीमत प्रभाव की मौजूदगी दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं बनती।
- ध. याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र में स्वीकार किया है कि क्षति जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में 11 प्रतिशत की वृद्धि है।
- न. घरेलू उद्योग ने औसत स्टॉक के ब्यौरे चतुराई से दिए हैं जो पूरे उचित रूप से क्षति संबंधी कोई सार्थक परिकलन नहीं बता सकते क्योंकि यह अंतिम स्टॉक है जिसे उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में एवं घरेलू उद्योग की बिक्री के रूप में जांचा जाना है जो यह दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।
- प. घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या पूरी जांच की अवधि में स्थिर है और क्षति जांच की अवधि में कर्मचारियों को भुगतान की गई मजदूरियों में 52 प्रतिशत की वृद्धि है। याचिकाकर्ताओं की मजदूरी कर्मचारियों की संख्या में किसी वृद्धि के बिना अथवा उत्पादकता में वृद्धि के अनुरूप बढ़ी है। इससे उत्पादकता में किसी सुधार के बिना अधिक लागत आई है जिससे क्षति, यदि कोई है, हुई है।
- फ. यद्यपि, आधार वर्ष में कुल आयात बढ़े, तथापि, उसे स्वयं एसआरएफ द्वारा आयातों के आलोक में तथा इस तथ्य पर विचार करके भी देखा जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग ने एचएमएलएस जैसे नाजुक ग्रेडों की आपूर्ति नहीं की और प्रयोक्ता आयात करने के लिए मजबूर थे।
- ब. वर्ष 2013 से 2017 तक संबद्ध देशों से आयातों की वृद्धि का कारण पाटन नहीं है बल्कि भारतीय बाजार की मांग में वृद्धि है जिसके बाद निचले उद्योग का विकास हुआ।
- भ. याचिकाकर्ताओं के प्रति यूनिट लाभ की प्रवृत्ति अनियमित रूप से बढ़ी है और लाभप्रदता में गति आयातों की कीमतों में गति से तुलनीय नहीं हैं। इस प्रकार, यह सिद्ध है कि लाभ प्रदान करने वाले कुछ भीतरी अन्य कारक हैं तथा इन हानियों का कारण आयात कीमत नहीं है।
- म. जब आयात कीमत आधार वर्ष में बढ़ी तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में नकारात्मक स्तर से सकारात्मक स्तर में भारी सुधार हुआ। उसके बाद 2015-16 और जांच की अवधि के बीच आयात कीमत में थोड़ा-सा परिवर्तन आया। तथापि, याचिकाकर्ताओं की हानियां दोगुने से अधिक हैं। इस प्रकार, दोनों के बीच में कोई कारणात्मकता नहीं है।
- य. नकारात्मक लाभप्रदता मजदूरी लागत में वृद्धि तथा व्याज एवं मूल्यहास लागत में वृद्धि के मद्देनजर बढ़ी है क्योंकि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी क्षति जांच की अवधि में 12 प्रतिशत तक बढ़ी जो यह दर्शाती है कि तथाकथित संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं है।
- कक. दोनों याचिकाकर्ता बहु-उत्पाद कंपनियां हैं और उन दोनों के लिए संबद्ध उत्पाद उनके लिए कुल राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा है। इस प्रकार, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता वर्तमान जांच में सार्थक कारक नहीं है।
- खख. उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा, मजदूरी, उत्पादकता आदि में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं है।
- गग. कोरिया और ताइवान से आयात 3 प्रतिशत की शुरुआत से अधिक हैं। इस प्रकार, इन देशों से कीमत संबद्ध देश की तुलना में अधिक प्रतीत होती है। तथापि, एनआईपी से तुलना की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

घ. याचिकाकर्ताओं ने सकल अचल परिसंपत्तियों पर 30 प्रतिशत आय का दावा किया है। प्राधिकारी को उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ को अपनाना चाहिए जब पाटन का आरोप नहीं लगाया गया था न कि 22 प्रतिशत आरओसीई पर। 22 प्रतिशत को अपनाने से घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण मिलता है। ब्रिजस्टोन और ह्योसंग कारपोरेशन के मामले का संदर्भ दिया गया था। इस संबंध में इसी परिपाटी का संदर्भ भी दिया गया।

डड. प्रपत्र IVक में क्षति मानदंडों का उचित रूप से पठन करना यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को तथाकथित पाटन के कारण कोई क्षति नहीं हुई।

#### **घरेलू उद्योग के विचार**

73. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति संबंधी मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आयात पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में बढ़े हैं।
- ख. आयातों का याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण एवं हासमान प्रभाव पड़ा है।
- ग. आयातों से याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत पर कम बिक्री तथा बिक्री कीमत पर कटौती हुई है।
- घ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है।
- ड. याचिकाकर्ताओं के उत्पादन और क्षमता उपयोग में काफी वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत में वृद्धि के कारण है। यदि कैप्टिव खपत के लिए किया गया उत्पादन समाप्त किया जाए तो यह दर्शाएगा कि उत्पादन 2014-15 से कम होता रहा है और वस्तुतः पिछले दो वर्षों में 15 प्रतिशत तक कम हो गया है।
- च. इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया था कि यद्यपि मांग में वृद्धि से याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, तथापि, यह वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप कहीं भी नहीं है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के पाटन के कारण संभावित बिक्री को खोया है।
- छ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की मालसूची इस अवधि में बनी है।
- ज. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी हास हुआ है और उसे हानियां हो रही हैं।
- झ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के नकद लाभ में गिरावट आई है और उसकी आय नकारात्मक है।
- ञ. सभी लाभप्रदता के मानदंडों में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है।
- ट. इस तर्क के दावे को मानते हुए कि याचिकाकर्ता इष्टतम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं, पाटित आयातों से फिर भी घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं होती, यदि आयात उसके बाजार हिस्से को खाए बिना बढ़ी हुई मांग को केवल पूरा कर रहे होते। तथापि, वर्तमान मामले में बाजार हिस्से में गिरावट है और याचिकाकर्ता अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर रहे हैं।
- ठ. यह तर्क कि कैप्टिव खपत में वृद्धि से लाभ में कमी आई है, आधारहीन है। तथापि, वास्तविक रूप से बढ़ी हुई कैप्टिव खपत के कारण उत्पादन में वृद्धि से याचिकाकर्ताओं को बेहतर लागत दक्षता प्राप्त करने में मदद मिली होती और लाभ में सुधार हुआ होता, यदि पाटन के क्षतिकारक प्रभाव न होते।
- ड. किसी भी दशा में कैप्टिव खपत के लिए सामानों का मूल्य उत्पाद कानूनों की अपेक्षाओं के अनुरूप लागत प्लस 10 प्रतिशत पर लगाया जाता है। तथापि, बाहरी बिक्री के लिए कीमतें लागत से कम रखी गई हैं।
- ढ. इसके अतिरिक्त, लाभप्रदता से संबंधित मानदंड विशिष्ट रूप से घरेलू बाजार में व्यापारिक बिक्री से संबंधित हैं। इस प्रकार, कैप्टिव खपत का उस पर कोई प्रभाव नहीं है।
- ण. याचिकाकर्ताओं ने घरेलू एवं निर्यात प्रचालनों के लिए आंकड़ों को अलग-अलग किया है और लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय और अन्य संगत मानदंडों, जहां तक वे केवल घरेलू प्रचालनों से संबंधित हैं, से संबंधित आंकड़े ही दिए हैं। घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों अर्थात् लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय, ने क्षति की अवधि में गिरावट दर्शाई है।
- त. यह दावा कि क्षति परस्पर प्रतिस्पर्द्धा के कारण हुई है, आधारहीन है। आयात बाजार के प्रमुख हिस्से का 60 प्रतिशत तक है। इस प्रकार, संबद्ध सामानों की कीमत निर्देशित करने वाले बाजार में प्रमुख प्रभावी बाजार बल हैं। प्रत्येक घटक द्वारा हुई क्षति दूसरे के कार्य के कारण मानना उचित नहीं है।
- थ. एसआरएफ की वार्षिक रिपोर्ट पर विश्वास करने, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक नए व्यापारी के प्रवेश से मार्जिनों के सिकुड़ने की संभावना है, का कोई औचित्य नहीं है। प्रथमतः यह वाक्य वास्तविक विवरण की बजाए केवल एक अवधारणा है।
- द. किसी भी दशा में वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं पलटते कि पाटन का घरेलू उद्योग को

- क्षति में योगदान है क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष में लाभप्रदता दर्शाती है जबकि यह जांच, जांच की अवधि में प्रवृत्तियों से संबंधित है। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के समग्र प्रचालनों से संबंधित है न कि केवल घरेलू प्रचालनों से संबंधित है तथा वार्षिक रिपोर्ट पाटन के कारणों को देखती है जिसका प्राधिकारी से कोई संबंध नहीं है।
- ध. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में विवरण विचाराधीन उत्पाद के संबंध में नहीं है, बल्कि वह खंड अर्थात् समग्र रूप से औद्योगिक यार्न है जबकि वर्तमान जांच केवल कुछ किस्मों के औद्योगिक यार्न के संबंध में है।
- न. मूल्यहास और ब्याज लागत में क्षति की अवधि में कमी आई है। मूल्यहास और ब्याज, लागत घरेलू उत्पादन, निर्यात उत्पादन के लिए बिक्री, बिक्री के आधार पर आबंटन के अनुपात से प्रभावित हुई है तथा क्षति की अवधि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है। तथापि, प्रति यूनिट लागत प्रपत्र सीआई के आधार पर अनुपात में इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं है और इस प्रकार कुल लागत में वृद्धि अथवा कमी की प्रवृत्तियां बेहतर दर्शाती हैं। इस लागत के आधार पर निर्धारित प्रति यूनिट लाभ/हानि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और उसे हानियां होनी आरंभ हो गईं।
- प. बढ़ते हुए आयातों और सतत सकारात्मक आरओसीई के बीच कारणात्मक संपर्क के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का दावा आधारहीन है। कई अन्य कारक भी हैं जिनका घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय पर प्रभाव पड़ा होगा; जिनमें वह कीमत शामिल है जिस पर बाजार में आयातों ने प्रवेश किया है, बाजार में आयातों का हिस्से शामिल है, चाहे आयातों ने घरेलू उद्योग के हिस्से को खाया हो, चाहे आयातों से घरेलू उद्योग आज की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा हास हुआ हो।
- फ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2014-15 के बाद गिरा है और उसे हानियां होनी शुरू हो गई हैं।
- ब. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं हास हुआ है जिसके कारण घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में काफी हानियां हुई हैं। यह नोट किया जाए कि जब कीमत कटौती 8 प्रतिशत है तो आयातों की पहुँच कीमत वास्तविक रूप से संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत से कम 18 प्रतिशत है।
- भ. कर्मचारियों की उत्पादकता इस अवधि में बढ़ी है। प्रति कर्मचारी 84 मी. टन की उत्पादकता से वह बढ़कर 94 मी. टन प्रति कर्मचारी हो गई है। इसी प्रकार, प्रति दन उत्पादकता में भी बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है। इस प्रकार, यह तर्क कि उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं है, गलत है।
- म. जहां तक मजदूरी में वृद्धि का संबंध है, यह वृद्धि 4 वर्ष की अवधि में केवल 57 प्रतिशत तक है जो असामान्य नहीं है। किसी भी दशा में मजदूरियां संबद्ध सामानों की बिक्री लागत का केवल 4-5 प्रतिशत हैं। इस प्रकार, मजदूरियों में वृद्धि का लागत अथवा लाभों के संचलन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।
- य. याचिकाकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क से सहमत हैं कि नियोजित पूंजी, जहां तक उसका क्षमता विस्तार से संबंध है, पर क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े सिद्ध करते हैं कि क्षमता विस्तार के लिए निवेश सूचित निवल अचल परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने उसका सत्यापन भी किया है।
- कक. याचिकाकर्ताओं की कीमतों में गिरावट, कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के कारण लागत में गिरावट से कहीं अधिक है और वह स्पष्ट रूप से पाटित आयातों के कारण हुई है।
- खख. आयात भारतीय बाजार में अनुचित रूप से कम कीमतों पर आए हैं जिससे याचिकाकर्ता अपनी कीमतों को कम करने के लिए और कम लागत पर बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। कीमतों में कमी के बावजूद कीमत कटौती सकारात्मक है जो कि स्पष्ट रूप से उस कारण है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है।
- गग. चाहे बाजार हिस्से पर कैप्टिव खपत को शामिल करते हुए अथवा न करते हुए विचार किया जाए, इस पर ध्यान न देते हुए यह दर्शाएगा कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा शेष जांच की अवधि से तुलना करने पर जांच की अवधि में न्यूनतम है।
- घघ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता, जहां तक संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले प्रभाग का संबंध है, प्रभावित हुई है।
- ङङ. जहां तक कारण न होने के विश्लेषण के दावे का संबंध है, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं रखा है जो यह सिद्ध करे कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक के कारण है। इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए कारण न होने का विश्लेषण करने का कोई कारण नहीं है।
- चच. याचिकाकर्ता यह मानने में असमर्थ हैं कि किसी ऐतिहासिक हानि से जांच की अवधि में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को क्षति कैसे हो सकती है। लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय से संबंधित आंकड़े जांच की अवधि के दौरान आयोजित राजस्व और लगाई गई लागत पर आधारित हैं। विगत में हुई किसी भी हानि से प्रभावित किसी भी तरीके

- में इनमें से कोई कारक नहीं है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की समझ में ऐतिहासिक हानियां केवल प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए संगत हैं और जांच की अवधि में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते।
- छ. एक ओर निर्यातक ने याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख किया है और दूसरी ओर यह दावा किया है कि निर्यात में गिरावट से प्रति यूनिट निर्धारित लागत में वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि हुई है तो यह बहुत ही स्पष्ट है कि निर्धारित लागत प्रति यूनिट में गिरावट आनी ही चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों के ये दावे आधारहीन हैं।
- ज. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की कुल संयंत्र क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद और अन्य किस्म के यार्न, दोनों मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के मामले में उसी संयंत्र में बनाए जाते हैं। समयोजित क्षमता जहां तक संबद्ध सामानों की क्षमता से उसका संबंध है, दी गई है। इस संबंध में आंकड़ों की परिशुद्धता और पर्याप्तता का प्राधिकारी ने स्वयं ही सत्यापन कर दिया है।
- झ. कोरिया गणराज्य और ताइवान से आयातों से संबंधित दावे के संबंध में कानून में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि अन्य देश घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक पर बिक्री करें अथवा कारणात्मक संपर्क सिद्ध नहीं होगा। वर्तमान मामले में संबद्ध आयातों का बाजार के 60 प्रतिशत से अधिक पर कब्जा है। इसके विरोध में अन्य देशों से आयात अर्थात् कोरिया गणराज्य और ताइवान का आयात बाजार के केवल 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत ही है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह देखा जाएगा कि संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कहीं अधिक है और इस प्रकार ऐसे आयातों से याचिकाकर्ताओं की कीमतों की न तो कटौती हो सकती है और न उनका न्यूनीकरण प्रभाव हो सकता है। वस्तुतः कोरिया गणराज्य और ताइवान से आयातों की पहुँच कीमत याचिकाकर्ताओं की उत्पादन लागत से काफी अधिक है।
- ञ. यह पूर्वानुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि डिण्ड कोर्ड अथवा ब्रेडेड यार्न जैसे निचले उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाए जाने का क्या प्रभाव होगा। यह हो सकता है कि निचले डिण्ड कोर्ड और ब्रेडिंग्स यार्न के विदेशी उत्पादकों के पास इन सामानों की अधिशेष क्षमताएं न हों और इस प्रकार उनका बाजार में इनके पाटन का कोई इरादा न हो अथवा संभवतः यदि ऐसे सामानों का आयात भी किया जाता है तो उससे घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं होगी। इस प्रकार, केवल इस अवधारणा पर कि डिण्ड कोर्ड और ब्रेडिंग यार्न के आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बढ़ सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों से याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के अधिकारपूर्ण संरक्षण को नकारना काफी नहीं है।
- ट. ये दावे कि कीमत कटौती असंगत है जब घरेलू उद्योग का निष्पादन सुधर गया हो, आधारहीन हैं। वर्तमान मामले में अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ताओं ने सस्ते पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमत घटाई है। इस प्रकार, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण एवं ह्रासमान प्रभाव रहा है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानियां हो रही हैं और नियोजित पूंजी पर उसकी आय नकारात्मक है। तथापि, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतें कम किए जाने के बावजूद उन आयातों से उन कीमतों की कटौती हुई है जिसके कारण याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा खो दिया है।
- ठ. प्राधिकारी क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत पर आय की दर की निरंतर अनुमति देते रहे हैं। अतः इस परिपाटी से विचलन का कोई आधार नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि वर्तमान मामले में 22 प्रतिशत आरओसीई अनौचित्यपूर्ण है।

#### **प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच**

74. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण में किए गए अनुरोधों सहित किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।
75. पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षा है कि वे मात्रा एवं कीमत प्रभाव, दोनों की जांच कर क्षति की जांच करें। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव तथा (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल है। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण संदर्भ में अथवा भारत में उत्पादन या उपभोग के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों को अन्यथा प्रभावित करने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

76. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लिखित है:

*"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"*

77. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं; जबकि कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं।
78. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को उनके अनुरोधों में ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ रूप में क्षति मानदंडों की जांच की है।

#### ड.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

##### मांग का मूल्यांकन

79. संबद्ध सामानों की मांग सभी देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के साथ समान उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री जोड़कर निर्धारित की गई है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है जो कि निम्नलिखित तालिका में देखी जा सकती है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (2016-17)
चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	5903	7087	9092	13412
पाटित आयात	मी. टन	4939	5719	7784	12241
अपाटित आयात	मी. टन	964	1368	1308	1171
अन्य देशों से आयात	मी. टन	3768	1928	2105	1950
याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	121	120	128
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	105	93	93
कुल मांग	मी. टन	16470	17072	19127	23716

##### आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

80. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की अपेक्षा है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध सामान के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (2016-17)
चीन जन. गण. से पाटित आयात	मी. टन	4939	5719	7807	12241
कुल मांग	मी. टन	16470	17072	19127	23716
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	105	112

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (2016-17)
भारतीय खपत के संबंध में पाटित चीनी आयात	%	30%	33%	41%	52%
घरेलू उद्योग उत्पादन के संबंध में पाटित चीनी आयात	%	36%	37%	54%	80%

81. उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

**क.** संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात 2013-14 के दौरान 4939 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 12,241 मी. टन हो गए।

**ख.** घरेलू खपत/मांग के संबंध में चीन जन. गण. से पाटित आयात बढ़े हैं और जांच की अवधि के दौरान 52 प्रतिशत के स्तर पर हैं।

**ग.** भारत में घरेलू उत्पादन के संबंध में चीन जन. गण. से पाटित आयात बढ़े हैं और जांच की अवधि के दौरान 80 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचे हैं।

82. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयात पूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़े हैं।

## ज.2 घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत प्रभाव

83. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समग्र अर्थों में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के कारण कीमतों का अत्यधिक हास हुआ है अन्यथा कीमत वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती।"

84. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत का पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का हास करने के लिए अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए अन्यथा काफी मात्रा तक है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत हास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। प्राधिकारी द्वारा हटाए जाने की स्वीकृति दिए जाने पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद की पूर्ति के लिए मूल्यों में आवश्यक समायोजन किए गए हैं, जैसा कि इस प्रकटन विवरण में अब परिभाषित किया गया है।

## कीमत कटौती

85. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली से की है। इस संबंध में, उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत सभी छूटों और करों के निबल की व्यापार के समान स्तर पर तुलना की है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गईं। घरेलू कीमतें और कटौती का मार्जिन निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (2016-17)
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	125.74	117.24	100.60	94.48
घरेलू बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
कीमत कटौती	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
	पहुँच मूल्य का %	***	***	***	***
	रेंज	0-5%	0-5%	0-10%	5-15%

86. प्राधिकारी उपर्युक्त तालिका से नोट करते हैं कि कीमत कटौती मौजूद है। यह भी नोट किया जाता है कि पिछले दो वर्षों में कीमत कटौती काफी रही है। कीमत कटौती इन वर्षों में बढ़ी है और आधार वर्ष से तुलना करने पर जांच की अवधि में यह काफी अधिक है।

#### कम कीमत पर बिक्री

87. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की क्षति की भी जांच की है। इसके लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से की गई है। आयातों की भारित औसत पहुँच कीमत से घरेलू उद्योग की भारित औसत एनआईपी की तुलना नीचे दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि (2016-17)
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	94.48
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	रु./कि. ग्रा.	***
क्षति मार्जिन	रु./कि. ग्रा.	***
	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
	%	***
	रेंज	10-20%

88. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से काफी कम थी।

#### कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

89. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का ह्रास हो रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों एवं कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया। यह स्थिति निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	88	84	85
घरेलू बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	91	83	80
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	125.74	117.24	100.60	94.48
	सूचीबद्ध	100	93	80	75

90. उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की बिक्री लागत में जांच की अवधि और क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है। तथापि, उसके संबंध में याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत में और अधिक गिरावट आई तथा जांच की अवधि में बिक्री लागत से नीचे रही। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत संबंध आयातों के पहुँच मूल्य की प्रवृत्ति के अनुरूप निकटता से चलती है। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ताओं को पहुँच मूल्य की कीमत प्रवृत्ति के कारण कीमत न्यूनीकरण/ह्रास का सामना करना पड़ा।
91. इस प्राधिकारी के समक्ष यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत में गिरावट कम हुई कच्ची सामग्री की कीमतों के कारण बिक्री लागत में गिरावट के फलस्वरूप है। तथापि, यह वह मामला प्रतीत नहीं होता जब याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत उनकी अपनी कीमतों से काफी अधिक गिर जाएं। इसकी बजाए यह पाया जाता है कि जब जांच की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि हुई तो भी बिक्री कीमत में घटते हुए पहुँच मूल्यों के अनुरूप निरंतर गिरावट आती रही।

### ज.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

92. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

### ज.4 उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

93. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और घरेलू उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता (विचाराधीन उत्पाद + गैर-विचाराधीन उत्पाद)	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद + गैर-विचाराधीन उत्पाद)	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	104	110
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	104	111
उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद)	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	105	112
याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	121	120	128
चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	4,939	5,719	7,807	12,241

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के क्षमता उपयोग, बिक्री और उत्पादन में क्षति की अवधि और जांच की अवधि में सुधार आया है।

### ज.5 लाभप्रदता

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
-------	-------	---------	---------	---------	--------------



विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
लाभ/(हानि)	रु./लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	59	(141)	(346)
लाभ/(हानि)	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	49	118	(271)

95. प्राधिकारी उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2014-15 के अपवाद के साथ क्षति जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं।

ख. यह दिखाई देता है कि घरेलू उद्योग अपनी विक्री लागत को वसूल करने अथवा उपयुक्त लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है।

#### ज.6 नियोजित पूंजी पर आय

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आरओसीई	%	***	***	***	***
	रेंज	(0-5)%	0-5%	(0-5)%	(0-5)%

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पूरी क्षति जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है।

#### ज.7 बाजार हिस्सा

97. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
कुल मांग	मी. टन	16470	17072	19127	23716
	सूचीबद्ध	100	104	116	144
<b>का बाजार हिस्सा</b>					
- याचिकाकर्ता	%	***	***	***	***
	रेंज	30-40%	35-45%	30-40%	25-35%
- अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
चीन जन. गण. से पाटित आयातों का हिस्सा	%	30%	33%	41%	52%
चीन जन. गण. से अपाटित आयातों का हिस्सा	%	6%	8%	7%	5%
अन्य देशों से आयातों का हिस्सा	%	23%	11%	11%	8%

98. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भारत में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ने के बाद भी घटा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में काफी बढ़ा है।

#### ज.8 मालसूची

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
प्रारंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	136	146
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	133	125
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	134	135

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के सामने संचित मालसूची की समस्या है। मालसूची का स्तर आधार वर्ष की तुलना में बढ़ता रहा है। बढ़ते हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया है और बढ़ती हुई मांग को काफी मात्रा में आयातों ने ले लिया है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के पास बढ़ती हुई मालसूची की स्थिति रह जाती है।

#### ज.9 घरेलू उद्योग की उत्पादकता

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर स्थिर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में सुधार हुआ है। अतः यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचकांक	100	100	100	100
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ कर्मचारी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचकांक	100	114	105	112

#### ज.10 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्र एवं मशीनों में काफी निवेश किए हैं। तथापि, इन निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी गिरावट आई है और आगे निवेश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

#### ज.11 पाटन एवं पाटन मार्जिन का स्तर

102. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात देश में पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और यह कि पाटन का मार्जिन काफी है।

#### ज.12 घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

103. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक, जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातित सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और बिक्री कीमत से कम है जो भारतीय बाजार में काफी कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण/ह्रास कर रही है। इस प्रकार, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य है।

104. इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण दृष्टि से काफी वृद्धि हुई है। आयात भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में काफी बड़े हैं। इस प्रकार, आयात भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से बड़े हैं। पाटित आयातों का कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के संदर्भ में काफी प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है। कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बाजार कीमतें देने के लिए मजबूर होता पड़ा जो कि उसकी लागत को भी नहीं ले सकती थी। आयातों का पहुँच मूल्य वस्तुतः कच्ची सामग्री की

लागत से भी काफी कम है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि के दौरान प्रभावित हुई है।

### ज.13 क्षति संबंधी समग्र विश्लेषण

105. रिकार्ड में सूचना को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयात पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़े हैं। आयातों के फलस्वरूप बाजार में कम कीमत पर बिक्री हो रही है और घरेलू उद्योग को वे उस स्तर तक अपनी कीमत लेने से रोक रहे हैं जहां घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत वसूल सकता है तथा निवेश पर उपयुक्त लाभ अर्जित कर सकता है। उत्पाद के लिए मांग काफी बढ़ी है। तथापि, चीन जन. गण. से पाटित आयातों ने मांग में वृद्धि में बारी हिस्सा लिया है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लाभप्रदता पूरी क्षति जांच की अवधि में नकारात्मक रही है क्योंकि पूरी क्षति जांच की अवधि में आयात बहुत ही कम कीमतों पर आते रहे हैं। मालसूची काफी बढ़ी है।

### ज.14 कारणात्मक संपर्क और अन्य कारक

106. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है। पाटन एवं घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के बीच जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

#### (i) तीसरे देश से आयात

107. संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से आयात मात्रात्मक दृष्टि से इतने काफी नहीं है कि वे घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बन सकें अथवा खतरा पैदा कर सकें। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों से जिस कीमत पर सामान आ रहे हैं, वह कीमत उस कीमत से अधिक है जिस पर संबद्ध देश से सामान आ रहे हैं।

#### (ii) मांग में संकुचन

108. संबद्ध सामानों के लिए मांग ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है। तदनुसार, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती। वस्तुतः घरेलू उद्योग अपनी बिक्री और मांग में वृद्धि के अनुरूप बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

#### (iii) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

#### (iv) प्रौद्योगिकी में विकास

110. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारक नहीं माना जा सकता।

#### (v) खपत पैटर्न में परिवर्तन

111. घरेलू उद्योग उस प्रकार के सामानों का उत्पादन कर रहा है जिनका भारत में आयात किया गया है। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन वे कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए दावा किए जा सकें।

#### (vi) निर्यात निष्पादन

112. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित काफी ह्रास के कारण हुई है। वस्तुतः यद्यपि घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट आई है, तथापि, आंकड़ा मूल्यांकन अकेले घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना के आधार पर किया गया है। इस प्रकार, घरेलू बिक्री को क्षति को अलग किया गया है और यथासंभव सीमा तक जांच की गई है।

#### (vii) अन्य उत्पादकों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रभावित नहीं हुआ है। प्राधिकारी द्वारा जिस सूचना पर विचार किया गया है, वह केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है। प्राधिकारी ने गैर-विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निष्पादन पर भी विचार किया है और पाया कि उन क्षेत्रों का निष्पादन प्रतिकूल नहीं है और इसीलिए उसे विचाराधीन उत्पाद में नहीं ले जाया जा सकता।

#### (viii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में ह्रास से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। इसकी बजाए, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में बढ़ती हुई प्रवृत्ति नजर आई है।

### झ. कारणात्मक संपर्क से संबंधित तथ्य

115. क्षति की अवधि में पाटित आयातों का विश्लेषण और घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित तथ्य प्रकट करता है:

- संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात जांच की पूर्ण अवधि में पूर्ण दृष्टि से बढ़ा है।
- संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में बढ़ा है।
- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भारत में संबद्ध सामानों की बढ़ती हुई मांग के बावजूद कम हुआ है।
- घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि और जांच की अवधि में सुधार हुआ है।
- घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ती रही है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। भारत में आ रहे कम कीमत के पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण/ह्रास रहा है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

#### ख. क्षति मार्जिन की मात्रा

116. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की एनआईपी याचिकाकर्ता-वार निर्धारित की गई है और तदनुसार, भारत औसत एनआईपी निकाली गई है। भारत औसत एनआईपी पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए असहयोगी पक्षकारों तथा भागीदार उत्पादक/निर्यातक से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है।
117. भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों तथा असहयोगी पक्षकारों के लिए क्षति मार्जिन निम्नलिखित है:

#### क्षति मार्जिन

देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पहुँच मूल्य अमेरिकी डॉलर/मी. टन	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर/मी. टन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज %
चीन जन. गण.	ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि.	ह्योसंग कारपोरेशन	***	***	***	***	नकारात्मक
चीन जन. गण.	1. झेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.  2. झेजियांग गुक्सियांडाओ पॉलिस्टर डोप डाइड यार्न कं. लि.	झेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि., चीन जन. गण.	***	***	***	***	10-20
चीन जन. गण.	जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	15-25
चीन जन. गण.	1. हुझोउ उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर लिमिटेड  2. झेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.	झेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	20-30
चीन जन. गण.	ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि.	ऑरियंटल टेक्सटाइल (होलिंग) लि.	***	***	***	***	नकारात्मक
चीन जन. गण.	अन्य कोई संयोजन	अन्य कोई संयोजन	***	***	***	***	45-55

118. निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का स्तर मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि. और ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड को छोड़कर काफी हैं।

**ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**

घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार जनहित में जांच की अवधि के दौरान निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. संबद्ध उद्योग के सामने पर्याप्त मांग और आपूर्ति के अंतराल की समस्या है और शुल्क लगाना घरेलू बाजार पर अनुचित भार होगा जिसको याचिकाकर्ता पूरी तरह से आपूर्ति नहीं कर सकते।
- ख. याचिकाकर्ता की घरेलू मांग के एक मार्जिन की पूर्ति करते हैं जो मांग के 50 प्रतिशत से कम है। इस प्रकार, शुल्क लगाना अनुचित भार होगा।
- ग. याचिकाकर्ता विशेष रूप से एसआरएफ की अपनी कैप्टिव खपत बढ़ाने की संभावना है जिससे मांग और आपूर्ति का अंतराल बढ़ जाएगा।
- घ. याचिकाकर्ता एकाधिकारिक, प्रतिस्पर्धारोधी बाजार सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बाद वे उच्च कीमतों पर उत्पाद कीमतें बनाए रखने में सक्षम होंगे जो देश के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होगा।
- ङ. याचिकाकर्ता संबद्ध सामानों की आपूर्ति में विलंब एवं व्यवधान की संभावना वाले हैं और इस प्रकार उन पर विश्वास करना पूर्णतः असंभव है। विगत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें याचिकाकर्ताओं से आपूर्ति विभिन्न कारणों से रोक दी गई है।
- च. याचिकाकर्ताओं के सामने कई गुणवत्ता संबंधी मुद्दे हैं जिनके कारण संबद्ध सामानों के प्रयोक्ता आयातित सामानों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हुए हैं। यहां तक कि याचिकाकर्ता (एसआरएफ) खुद संबद्ध सामानों का एक आयातक है।

**घरेलू उद्योग के विचार**

120. घरेलू उद्योग द्वारा जनहित में किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. अब तक यह सुनिर्धारित कानूनी सिद्धांत है कि मांग आपूर्ति अंतराल पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के लिए आधार नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य संबद्ध सामानों के पाटन के माध्यम से निर्यातकों द्वारा लिए गए अनुचित लाभों को समाप्त करना है। लगाया गया शुल्क केवल उचित प्रतिस्पर्द्धा स्थापित करता है और बाजार में सामानों की उपलब्धता प्रतिबंधित नहीं करेगा, क्योंकि आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपभोक्ता फिर भी बहुविध आपूर्ति स्रोतों को बनाए रख सकते हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की आपूर्ति के अभाव के संबंध में कोई खतरा नहीं है।
- ख. इसके अतिरिक्त, आरआईएल ने जांच की अवधि के बाद प्रमुख क्षमता विस्तार प्रति वर्ष 27,000 मी. टन तक किया है जिसके बाद मांग एवं आपूर्ति के अंतराल का यह मुद्दा हल हो जाएगा।
- ग. घरेलू उद्योग एकाधिकारिक स्थिति बनाने की स्थिति में कभी नहीं होगा जो उसे प्रतिस्पर्द्धारोधी कीमतें लगाने की अनुमति देगा क्योंकि संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात इस प्रकार की किसी प्रतिस्पर्द्धारोधी परिपाटी पर नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगे। किसी भी दशा में जहां एक से अधिक उत्पादक हैं, वहां बाजार में एकाधिकारिक स्थितियां नहीं रहेंगी।
- घ. यह अनुरोध याचिकाकर्ताओं द्वारा अनियमित आपूर्ति है, औचित्यहीन है। यदि घरेलू उद्योग उसके आदेशों को पूरा करने में असमर्थ था, तो घरेलू उद्योग की बिक्री कम हो गई होती। तथापि, मामला वह नहीं रहा है और अनुचित रूप से सस्ती कीमतों पर आ रहे आयातों के बावजूद घरेलू उद्योग ह्रासमान लाभप्रदता की लागत पर भी अपने उत्पादों का विपणन करने में सक्षम रहा है। बिक्री में यह वृद्धि उस स्थिति में संभव नहीं होती जब सामानों के उपभोक्ता सामानों की सुपुर्दगी के लिए आश्वस्त न हो।

**प्राधिकारी की जांच**

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

122. जहाँ तक गुणवत्ता के मुद्दे का उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि आयातक उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों का आयात करने में निरंतर सक्षम रहेंगे और इसीलिए किसी भी दशा में याचिकाकर्ताओं की दया पर नहीं रहेंगे। अतः ये दावे उपयुक्त नहीं हैं।

**ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध**

**विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

123. उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रकटन पश्चात अनुरोधों में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं। संक्षिप्तता के लिए पूर्व में किए गए अनुरोध तथा प्रकटन विवरण में हल किए गए अनुरोध दोबारा नहीं दिए जा रहे हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एचएमएलएस गुणधर्मों वाले यार्न के लिए परीक्षण मानदंड में तकनीकी परिपूर्णता और शुद्धता के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी आयामी स्थिरता सूची की परिभाषा में संशोधन करें जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

*"आयामी स्थिरता सूची को 0.05 सीएन/डीटीईएक्स सिरे वाले भार (एएसटीएम डी4974) के अनुसार परीक्षित) पर दो मिनट के लिए 4 सीएन/डीटीईएक्स (एएसटीएम डी885 के रूप में परीक्षित) और 177 डिग्री से. पर तप्त वायु सिकुड़न पर लंबाई की मात्रा के रूप में मापा जाता है।"*

ख. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित उत्पादों को हटाए जाने के लिए मांग की है/दावों को दोहराया है:

- 1000 डेनियर वाले एंटेजिव एक्टिवेटेड यार्न को इस आधार पर कि याचिकाकर्ता उसके कैप्टिव उपभोक्ता हैं, घरेलू बाजार में उसकी आपूर्ति नहीं कर रहे हैं तथा याचिकाकर्ताओं का उत्पादन और बिक्री का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।
- 1000 डेनियर वाले नियमित हाई टेनेसिटी लो स्प्रिंग (एचटीएलएस) यार्न को इस आधार पर कि याचिकाकर्ता उसके कैप्टिव उपभोक्ता हैं और उस समान के व्यापारिक विक्रेता नहीं हैं।
- 6000 से अधिक डेनियर वाले हाई टेनेसिटी यार्न को इस आधार पर कि याचिकाकर्ता इन सामानों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं और उनका भारत में आयात किया गया है। प्राधिकारी की टिप्पणी के विपरीत फ्लेट यार्न अर्थात् 6000 से अधिक डेनियर वाले अनट्विस्टेड यार्न का आयात किया गया है।

ग. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र से कैप्टिव घरेलू उत्पादक को शामिल करने अथवा हटाने के लिए निर्धारण हेतु अपनाए जाने वाला मानदंड संबद्ध सामानों का उत्पादन है न कि क्षमता। यह बात दोहराई जाती है कि एसआरएफ द्वारा कैप्टिव उत्पादन की जांच वर्तमान जांच में महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका संबद्ध सामानों का भारी एवं महत्वपूर्ण उत्पादन कैप्टिव खपत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एवं चीन जन. गण. लो एंश मेट कोक में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम का भी संदर्भ दिया जाता है।

घ. प्राधिकारी एसआरएफ द्वारा उत्पादन की तुलना में दिए गए अग्रिम लाइसेंस एवं शुल्क के तहत एसआरएफ के ब्यौरों का भी उल्लेख कर सकते हैं। यह भी दावा किया गया था कि एसआरएफ वे कानून बताने में विफल रहा जिनके कारण ये आयात हुए और उसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी को अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत किसी भी आयात को शामिल करते हुए एसआरएफ के आयात पर विचार करना चाहिए।

ङ. प्राधिकारी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि क्या प्राधिकारी द्वारा माने जा रहे याचिकाकर्ताओं के उत्पादन संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए समर्पित क्षमता है अथवा क्या यह भी अन्य सामानों के विनिर्माण के लिए क्षमता को शामिल करती है।

च. चीन जन. गण. से उत्पादक एवं निर्यातक स्वतः ही 11 दिसंबर, 2016 के बाद बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर प्राप्त करेंगे। तदनुसार, प्राधिकारी को इस मामले में "सरोगेट कंट्री" परिपाटी को नहीं अपनाना चाहिए। 11 दिसंबर, 2016 के बाद डब्ल्यूटीओ के सदस्य चीन जन. गण. को स्वतः ही "बाजार अर्थव्यवस्था" के रूप में मानेंगे। चीन जन. गण. के बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर को निर्धारित करने के लिए किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

छ. जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि., चीन जन. गण. ने अनुरोध किया कि उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाए कि डब्ल्यूटीओ में चीन जन. गण. के अभिगम नयाचार के पैरा 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां न होने पर चीनी

- उत्पादकों की घरेलू कीमतों अथवा लागतों को न मानने के लिए 15 वर्षों की अवधि पैरा 15(घ) के अनुसार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई है।
- ज. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि., चीन जन. गण. ने यह भी अनुरोध किया है कि उसका सामान्य मूल्य उन चीनी उत्पादकों के रिकार्डों के आधार पर निर्धारित किया जाए जिन्हें वर्तमान जांच में एमईटी प्रदान किया गया है क्योंकि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यह सबसे उपयुक्त आधार होगा।
- झ. याचिका और प्रकटन विवरण का सार्वजनिक रूपांतर सूचना को विशेष रूप से प्रत्येक कंपनी के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में अंतरों के संबंध में पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं करता।
- ञ. झेजियांग उनिफॉल और हुझोऊ उनिफॉल की लागत कच्ची सामग्री की बाजार कीमत के अनुसार है और संबंधित उत्पाद के लिए उनकी कीमत निर्यात बिक्री और घरेलू बिक्री के लिए संबंधित उत्पाद की बाजार कीमत के अनुरूप है। यहां तक कि उत्पादन प्रक्रिया चीन जन. गण. में अन्य उत्पादक/निर्यातक के समान है। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि झेजियांग उनिफॉल और हुझोऊ उनिफॉल के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन अन्य सहयोगी कंपनियों की अपेक्षा बहुत अधिक क्यों हैं। इस संबंध में, यह भी दावा किया गया है कि महत्वपूर्ण आंकड़े गोपनीय रखे गए हैं और प्रकटन विवरण में अपर्याप्त रूप से संक्षेप में दिए गए हैं।
- ट. प्राधिकारी ने उन उत्पादकों/निर्यातकों के नाम दिए हैं जिन्होंने उत्तर दायर किए हैं, परंतु उसमें ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाए कंपनी का उल्लेख "इन पक्षकारों को छोड़कर निम्नलिखित पक्षकारों से भी टिप्पणियां प्राप्त की गईं और ऊपर विचार भी किया गया है" के तहत किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि जिस उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी प्रश्नावली अथवा प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए, उसे नकारात्मक मार्जिन कैसे प्राप्त हुआ।
- ठ. घरेलू उद्योग ने केवल यह उल्लेख किया है कि चीन जन. गण. से तथाकथित आयातों के परिणामस्वरूप कीमत कटौती है तथा कीमत ह्रास भी है। तथापि, यह सामान्य उद्योग की जानकारी है कि संबद्ध सामानों की कीमत कच्ची सामग्री अर्थात् पीटीए एवं एमईजी/पॉलिस्टर चिप्स द्वारा मुख्य रूप से निर्धारित की जाती है और संबद्ध सामानों की कीमतों में पीटीए एवं एमईजी/पॉलिस्टर चिप्स की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ उतार-चढ़ाव होता है। यह भी सामान्य उद्योग की जानकारी है कि कच्ची सामग्री पीटीए एवं एमईजी/पॉलिस्टर चिप्स की लागत में हाई टेनेसिटी यार्न की कुल उत्पादन लागत का लगभग 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत होता है। अतः जब कभी कच्ची सामग्री पीटीए एवं एमईजी/पॉलिस्टर चिप्स की कीमतों में गिरावट आती है तो संबद्ध सामानों की कीमत में भी गिरावट आती है तथा इसके विपरीत भी होता है। यह वर्तमान जांच में स्पष्ट स्थिति है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट कच्ची सामग्री पीटीए एवं एमईजी/पॉलिस्टर चिप्स की कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप है न कि चीन जन. गण. से तथाकथित पाटित आयातों के कारण।
- ड. संबद्ध आयातों और घरेलू कीमतों के बीच क्षति जांच की अवधि के दौरान केवल समांतर कीमत प्रवृत्तियों की मौजूदगी अपने आप में कीमत प्रभाव की मौजूदगी दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं बनता। प्राधिकारी को कच्ची सामग्री की कीमतों की प्रवृत्तियों, वैश्विक कीमत प्रवृत्तियों और इसी प्रकार के अन्य कारकों पर यह निर्धारित करने के लिए विचार करना चाहिए कि कीमत प्रवृत्तियां किसी तरीके में क्यों जाती हैं। चीन - जीओईएस में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया।
- ढ. प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से से संबंधित आंकड़ों को रिकार्ड करने अथवा प्रकट करने में विफल रहे हैं और इसीलिए आयातों की कीमतों पर ही पृथक् रूप से विचार करना और घरेलू उत्पादक की निवल बिक्री कीमत पर विचार करना क्षति का संकेतक अथवा याचिकाकर्ताओं को उसकी कमी का संकेतक नहीं होगा। ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2011) में सेसेटे की टिप्पणियों पर विश्वास किया गया।
- ण. याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से का विश्लेषण कैप्टिव खपत के आलोक में किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, कैप्टिव खपत सहित बिक्री, बाजार हिस्सा और मांग सिद्ध की जानी चाहिए। वह याचिकाकर्ताओं को क्षति का अभाव दर्शाएगी।
- त. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग जैसे आर्थिक मानदंडों में सुधार हुआ है, कैप्टिव खपत के बिना बिक्री क्षति जांच की अवधि में 28 प्रतिशत तक बढ़ी है, उत्पादकता 12 प्रतिशत तक बढ़ी है तथा समग्र वृद्धि हुई है।
- थ. तथाकथित रूप से पाटित आयातों के कारण क्षति का अभाव है जो कि घरेलू उद्योग के प्रमुख मात्रात्मक मानदंडों, यथा उत्पादन, बिक्री आदि में सकारात्मक कटौती और बढ़े हुए आयातों के बावजूद वृद्धि से सिद्ध है।
- द. क्षति मानदंडों, विशेष रूप से, प्रमुख लाभप्रदता मानदंडों के पीसीएन-वार मूल्यांकन को विचाराधीन उत्पाद में परस्पर प्रकार की मौजूदगी के निमित्त ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- ध. याचिकाकर्ताओं के कर्मचारियों की संख्या स्थिर है, परंतु मजदूरी में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, इस संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं है।
- न. याचिकाकर्ताओं की मालसूची का क्षति के वस्तुपरक विश्लेषण के लिए उनको उत्पादन के संबंध में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- प. याचिकाकर्ताओं की नकारात्मक लाभप्रदता मजदूरी लागत में वृद्धि तथा ब्याज एवं मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण है क्योंकि घरेलू उद्योग की लगाई गई पूंजी क्षति जांच की अवधि में 12 प्रतिशत तक बढ़ी जो यह दर्शाती है कि तथाकथित संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं है।
- फ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता वर्तमान जांच में एक सार्थक कारक नहीं है क्योंकि संबद्ध उत्पाद में उन याचिकाकर्ताओं के लिए कुल राजस्व का बहुत ही छोटा हिस्सा है जो बहु उत्पाद कंपनियां हैं।
- ब. प्राधिकारी को उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ को लेना चाहिए जब पाटन का आरोप लगाया गया, न कि 22 प्रतिशत आरओसीई। वर्ष 1987 में डिजाइन किया गया 22 प्रतिशत आरओसीई का आधार, जब ब्याज दर और निगम कर जैसे सभी मानदंड अलग-अलग थे, को वर्ष 2016 में 30 वर्ष बाद उपयुक्त नहीं माना जा सकता। 1987 में ब्याज की दर लगभग 18 प्रतिशत थी और निगम कर 40 प्रतिशत था। अब ब्याज की दर (लगभग 10 प्रतिशत) और निगम कर (30 प्रतिशत), दोनों कम हो गए हैं। अतः यह अनुरोध है कि 22 प्रतिशत आरओसीई लागू कर डीजीएडी घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दे रहे हैं।
- भ. कारणात्मक संपर्क के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि गैर संबंध विश्लेषण अपर्याप्त है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि:
- प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ऐतिहासिक हानियों तथा घरेलू उत्पादकों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा, पीटीए और एमईजी/पॉलिस्टर चिप्स की कीमतों में गिरावट तथा आवेदक उत्पादकों के कमजोर निर्यात निष्पादन पर विचार नहीं किया है।
  - प्राधिकारी को एसआरएफ के आयातों के कारण स्वतः प्रभावित क्षति की संभावना की जांच करनी चाहिए।
  - प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं की कैप्टिव खपत में काफी वृद्धि के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।
  - प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं की निर्यात बिक्री में काफी गिरावट के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।
  - प्राधिकारी को व्यापारिक बाजार से कैप्टिव खपत में जाने वाले याचिकाकर्ताओं की खपत/बिक्री पैटर्न में परिवर्तनों के कारणों तथा कमजोर निर्यात निष्पादन पर विचार करना चाहिए।
  - प्राधिकारी को समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्द्धा के प्रभाव पर विचार करना चाहिए।
  - प्राधिकारी को कोरिया गणराज्य और ताइवान से आयातों, जिन दोनों के वे न्यूनतम से अधिक हैं, के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए।
  - कर्मचारियों की संख्या में किसी वृद्धि के बिना अथवा उत्पादकता में तदनुरूपी वृद्धि के बिना याचिकाकर्ता की लागत की मजदूरी की मात्रा में वृद्धि।
- म. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने शुल्क तालिका में नाम में संशोधन की मांग की है। इस संबंध में यह दावा किया गया है कि अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:

प्रकटन विवरण में रिकार्ड किया गया गलत नाम	अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किए जाने वाला सही नाम
ऑरियंटल इंडस्ट्रीज होलिंग लि.	ऑरियंटल टेक्सटाइल (होलिंग) लिमिटेड
ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि.	ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि.
ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य	ह्योसंग कारपोरेशन

- य. ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. ने केवल ऑरियंटल टेक्सटाइल (होलिंग) लि. के माध्यम की बजाए भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात सीधे भी किया है। अतः प्राधिकारी शुल्क तालिका में उत्पादक के बजाए उत्पादक एवं निर्यातक के रूप में ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।
- कक. हाल ही के समय में निर्यातकों ने सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई हैं। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता अपने सामानों की आयातों की अलग-अलग कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम है। यह भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अच्छी स्थिति का अनुभव कर रहा है। उस पर भी विधिवत विचार किया जाना चाहिए। कीमत दर प्रतिशत के रूप में शुल्क लगाना



प्रयोक्ता उद्योग के लिए हानिकारक होगा। प्राधिकारी को कोई भी शुल्क लगाने के संबंध में पुनः विचार करना चाहिए और निर्धारित शुल्कों के बजाए मानक शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए।

खख. पाटनरोधी उपाय के कार्यान्वयन से मांग में वृद्धि के साथ निचले भारतीय उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि पाटनरोधी शुल्क के कारण भारतीय बाजार से संबद्ध सामानों को अचानक रोक दिया गया तो भारतीय निचले उद्योग पर अपर्याप्त आपूर्ति, अत्यधिक उच्च खरीद कीमत और कम लाभ अथवा हानि होने जैसे नकारात्मक प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ेंगे।

### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

124. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात अनुरोधों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं। संक्षिप्तता के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों को और जिन पर प्रकटन विवरण में पहले ही कार्रवाई कर दी गई है, उन्हें नीचे दोहराया नहीं गया है:

- क. प्राधिकारी कृपया संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतर प्रकट करें। जहां सत्यापन रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, वहां प्राधिकारी को उत्पादन, लागत, कैप्टिव इनपुट का मूल्यांकन, संबद्ध पक्षकारों के बीच लेन-देन, मूल्य श्रृंखला की आवश्यकता की दृष्टि से प्रभावली के उत्तरों की परिपूर्णता विभिन्न लेन-देनों की आयात कीमतों में भारी अंतरों की दृष्टि से निर्यात कीमत आदि के संबंध में तथ्य प्रकट करने चाहिए।
- ख. याचिकाकर्ताओं को विश्वास है कि प्राधिकारी ने विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए कुछ सूचना दायर करने हेतु निर्यातकों को निर्देश दिया और यदि निर्यातकों ने उत्तर में कोई सूचना मूल प्रभावली के उत्तरों के अलावा दायर की है तो वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी के व्यापार नोटिसों का सीधा उल्लंघन है क्योंकि कोई अगोपनीय रूपांतर दायर नहीं किया गया था।
- ग. उत्तरदाता निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन से वास्तविक रूप से कम और यहां तक कि दो निर्यातकों के लिए नकारात्मक है। याचिकाकर्ता अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं।
- घ. प्राधिकारी को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को मेल अथवा पत्र द्वारा भेजे गए सभी पत्रों की प्रति तथा इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए उत्तरों की प्रति उपलब्ध करानी चाहिए। कम से कम उसका अगोपनीय रूपांतर प्रकट किया जाना चाहिए।
- ङ. प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं को क्षति मानदंड प्रकट करने चाहिए क्योंकि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा खुद प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है।
- च. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य प्रकट करना चाहिए क्योंकि यह घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित है (केवल एक निर्यातक के लिए)।
- छ. याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि भागीदार निर्यातकों के मामले में वास्तविक पाटन मार्जिन के प्रकटन का अर्थ सामान्य मूल्य अथवा निर्यात कीमत का प्रकटन नहीं है।
- ज. निर्मित सामान्य मूल्य का निर्धारण, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है, प्रकट किया जाना चाहिए क्योंकि प्रकटन विवरण में निर्धारित सामान्य मूल्य याचिकाकर्ता द्वारा किए गए परिकलनों से वास्तविक रूप से कम है और वह भी जब सामान्य मूल्य याचिकाकर्ता के आंकड़ों पर आधारित हो।
- झ. याचिकाकर्ता 1000 डेनियर से अधिक वाले और एचएमएलएस गुणधर्मों वाले एडेजिव एक्टिवेटेड (एए) यार्नों को हटाने का विरोध करते हैं।
- ञ. 1000 डेनियर से अधिक वाले एडेजिव एक्टिवेटेड (एए) यार्नों को शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि उसका उत्पादन किया जाता है और उसकी छोटी-सी मात्रा की बिक्री भी की गई है। 2000 डी वाले वे यार्न कुछ नहीं हैं बल्कि 1000 डेनियर यार्न के दोगुने हैं। अतः 2000, 3000 और उसी प्रकार के अन्य डेनियर उसी श्रेणी में आते हैं। 730 मी. टन एए यार्न के उत्पादन का साक्ष्य देते हुए पूर्व में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पत्र का संदर्भ दिया जाता है जिस यार्न को देश में मांग की कमी के कारण निर्यात किया गया था।
- ट. एचएमएलएस गुणधर्मों वाले यार्न को हटाने के संबंध में याचिकाकर्ता एचएमएलएस यार्न बेचने के लिए ग्राहकों से संपर्क करते रहे हैं। तथापि, ग्राहकों ने कोई उत्तर नहीं दिया और रुचि नहीं दर्शाई। उनमें से एक ने यह उल्लेख करते हुए उत्तर दिया कि घरेलू उद्योग की कीमतें बहुत अधिक हैं।
- ठ. याचिकाकर्ताओं ने एचएमएलएस तथा रेगुलर हाई टेनेसिटी और लो स्प्रिंगेज यार्न के उत्पादन और बिक्री के लिए सुविधाओं का साक्ष्य भी दिया।
- ड. याचिकाकर्ताओं ने यह साक्ष्य दिया कि याचिकाकर्ता के उत्पादों के तकनीकी गुणधर्मों और चीनी आपूर्तिकर्ताओं गुक्सियांडाओ तथा उनीफुल के गुणधर्मों की तुलना उनमें कोई अंतर नहीं दर्शाती।

- ढ. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि एसआरएफ कैप्टिव खपत तथा औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए एचएमएलएस का उत्पादन करता है। तथापि, एचएमएलएस की कैप्टिव खपत जांच की अवधि के दौरान संस्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत से कम थी।
- ण. याचिकाकर्ता एक निर्यातक को एमईटी प्रदान करने पर विवाद करते हैं। इस संबंध में यह अनुरोध है कि केवल इस बात से कि चूँकि कंपनी एक चीनी कंपनी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एमईटी के लिए हकदार है। डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटों में प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष का संदर्भ रखा गया था जिसमें कोडक तथा फुजी को एमईटी प्रदान नहीं किया गया था।
- त. अतिरिक्त रूप से याचिकाकर्ताओं ने संबंधित व्यापारी ह्योसंग कारपोरेशन से संबंधित एसजीए एवं लाभ को ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि. के लिए परिकलित निर्यात कीमत से घटाने के संबंध में दावे किए हैं।
- थ. चूँकि, एनआईपी घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है, अतः याचिकाकर्ता निर्धारित एनआईपी का विस्तृत ब्यौरा प्रकट करने का अनुरोध करता है ताकि याचिकाकर्ता उस पर टिप्पणियां दे सकें।
- द. याचिकाकर्ताओं द्वारा सूचित लगाई गई पूंजी के निर्धारण के लिए मानी गई निवल अचल परिसंपत्तियों में तथा प्रकटन विवरण में मानी गई धनराशि में भारी अंतर तथा कमी पाते हैं। यह स्वविवेक से की गई कमी अनुचित, अनौचित्यपूर्ण तथा पूर्वाग्रही है।
- ध. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 04.05.2018 के ई-मेल द्वारा कार्य प्रणाली के संबंध में अनुरोध किए थे। तथापि, उस पर कहीं भी चर्चा नहीं की गई अथवा प्रकटन विवरण में विचार नहीं किया गया।
- न. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित स्वरूप) होनी चाहिए।
- प. याचिकाकर्ता करते हैं कि प्राधिकारी कारणात्मक संपर्क और गैर संबंध से संबंधित घरेलू उद्योग के आधार, क्षति विश्लेषण और विश्लेषण के संबंध में प्रकटन विवरण में सिद्ध अपने जांच परिणामों को पुनः पुष्ट करें।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध दोहराई गई प्रकृति के हैं और उनका पहले ही प्रकटन विवरण में समाधान कर दिया गया था। उपर्युक्त जांच परिणाम घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों के उन सभी तर्कों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक तथा पहले हल न किए गए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की है:
  - क. प्राधिकारी ने एचएमएलएस गुणधर्मों वाले यानों के लिए परीक्षण मानदंड के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर विचार किया है। तदनुसार, "विचाराधीन उत्पाद" के लिए मूल्यांकन के तहत शुद्धियों को शामिल किया गया है।
  - ख. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने यह समझकर 6000 से अधिक डेनियर वाले यानों के लिए उन्हें हटाए जाने पर विचार नहीं किया था कि ये यार्न वास्तव में ट्विस्टेड यार्न हैं। प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षकारों ने 6000 से अधिक डेनियर वाले फ्लेट/अनट्विस्टेड यानों के आयातों के संबंध में प्राधिकारी की जानकारी में साक्ष्य रखे हैं। इसी के आलोक में और याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के अभाव में अथवा उपर्युक्त सामानों की बिक्री के अभाव में प्राधिकारी ने इस मुद्दे के पुनर्मूल्यांकन किया है और "विचाराधीन उत्पाद" के अंतर्गत अपनी टिप्पणियां रिकार्ड कीं।
  - ग. प्राधिकारी ने 1000 डेनियर वाले हाई टेनेसिटी लो स्प्रिंग यार्न तथा 1000 डेनियर वाले एडेजिव एक्टिवेटेड यार्न को हटाए जाने से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया है। फिर भी, यद्यपि इस प्रकार न हटाए जाने के दावे विलंब से पहली बार उठाए गए थे, तथापि, प्राधिकारी ने उनका मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि याचिकाकर्ता इन यानों का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं और इसीलिए 1000 डेनियर के बराबर वाले एए यानों तथा 1000 डेनियर के बराबर वाले हाई टेनेसिटी लो स्प्रिंग यार्न को हटाए जाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों को रद्द किया जाता है।
  - घ. क्षति मूल्यांकन करते समय प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के विचाराधीन उत्पाद तथा गैर विचाराधीन उत्पाद पर विचार किया है।
  - ङ. चीन जन. गण. के बाजार अर्थव्यवस्था वाले व्यवहार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध जांच की अवधि के दौरान पूर्व में किए गए उन्हीं अनुरोधों की पुनरावृत्ति है। उनका मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा विस्तारपूर्वक उपयुक्त पैराग्राफों में कर दिया गया है।
  - च. जियांगसू हेंगली उस उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किए जाने का अनुरोध करते हैं जिसे बिना किसी औचित्य के एमईटी प्रदान किया गया है। प्राधिकारी ने उन सभी भागीदारों के लिए

- सामान्य मूल्य निर्मित किया है जिन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुसार एमईटी का दावा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि जिस उत्पादक/निर्यातक को एमईटी प्रदान किया गया है, वह केवल एक पीसीएन का आपूर्तिकर्ता है, अतः उनका सामान्य मूल्य उन अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपयुक्त मानक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता जिन्होंने विभिन्न पीसीएन के मिश्रण का निर्यात किया है।
- छ. झेजियांग उनिफुल और हुझोउ उनिफुल ने इन कारणों से संबंधित कई प्रश्न उठाए हैं कि उनके लिए और अन्य भागीदारी उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बीच काफी अंतर क्यों है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने प्रस्तुत वास्तविक सूचना तथा प्रत्येक भागीदार के लिए सत्यापित सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन-वार सूचना पर विचार किया है।
- ज. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑरियंटल इंडस्ट्रीज सुझोउ लि. और उसके व्यापारी ऑरियंटल टेक्सटाइल (होल्लिंडिंग) लि. द्वारा प्रभावली के उत्तर विधिवत दायर किए गए थे। इन कंपनियों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उनके प्रभावली के उत्तरों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
- झ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत न्यूनीकरण और ह्रास के मूल्यांकन तथा कच्ची सामग्री पीटीए और एमईजी की कीमत प्रवृत्तियों की तुलना में कीमत प्रवृत्तियों की तुलना से संबंधित अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा अपने "कीमत न्यूनीकरण/ह्रास" के मूल्यांकन में विचार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को बिक्री लागत की तुलना में बिक्री कीमत में भारी गिरावट का अनुभव हुआ (जिसमें कच्ची सामग्री की कीमतें शामिल हैं)। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में कीमत न्यूनीकरण है।
- ञ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से को प्रकट न किए जाने के संबंध में अनुरोध किए हैं। इस प्रकार का अनुरोध गलत है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा कम श्रृंखला, प्रवृत्तियों की तुलना करने के लिए पर्याप्त तथा प्राधिकारी के मूल्यांकन के रूप में दिया है।
- ट. प्राधिकारी पीसीएन-वार क्षति मूल्यांकन करने के अनुरोध को नोट करते हैं। प्राधिकारी ने, प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुरूप पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का पीसीएन-वार मूल्यांकन किया है। इससे अधिक क्षति मानदंडों का पीसीएन-वार मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ठ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न अनुरोध क्षति मानदंडों के मूल्यांकन के संबंध में किए गए तर्कों की पुनरावृत्ति में किए गए हैं। उनका समाधान प्रकटन विवरण में पहले ही कर दिया गया है। इन दावों के संबंध में मूल्यांकन "क्षति एवं कारणात्मक संपर्क का निर्धारण" के अंतर्गत किया गया है।
- ड. लगाई गई पूंजी पर कम आय (आरओसीई) पर विचार करने से संबंधित दावों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरओसीई प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुरूप एनआईपी के निर्धारण के लिए 22 प्रतिशत मानी गई है।
- ढ. प्रकटन पश्चात स्तर पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दोहराए गए गैर संबद्ध दावों के संबंध में प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों पर विधिवत विचार किया है कि क्या एसआरएफ के आयातों के कारण स्व-प्रभावित क्षति है। तथापि, वे आंशिक हैं और याचिकाकर्ताओं को हुई हानियों तथा क्षति में उनका कोई योगदान नहीं है।
- ण. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं की कैप्टिव खपत में काफी वृद्धि के कारणों पर विचार किया है। यह नोट किया गया कि उससे क्षति के किसी कारण की बजाए याचिकाकर्ताओं के लाभप्रदता मानदंडों में स्थिरता आई है। घटती हुई बिक्री के आलोक में याचिकाकर्ताओं की बढ़ी हुई कैप्टिव खपत उपयुक्त प्रतीत होती है।
- त. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की क्षति समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्द्धा के कारण नहीं है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पाद क्षेत्र काफी मात्रा में एक-दूसरे से भिन्न है और इसीलिए पूरे स्तर पर हुई क्षति को अन्य याचिकाकर्ता के निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।
- थ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ उत्पादकों/निर्यातकों के नाम शुल्क तालिका में गलत रिकार्ड किए गए हैं। यह गलती से हुआ था और उसे वर्तमान जांच परिणाम में ठीक कर लिया गया है।
- द. ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. ने यह दावा किया है कि वह उत्पादक एवं निर्यातक है। तथापि, यह दावा गलत है। प्राधिकारी ने इसका मूल्यांकन "ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि. (ओटीआईजेड) तथा मैसर्स ऑरियंटल टेक्सटाइल (होल्लिंडिंग) लि., चीन जन. गण." के अंतर्गत किया है।

- ध. हाल ही में निर्यात कीमतों में वृद्धि के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दावों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जांच की अवधि से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। जांच की अवधि के बाद निर्यात कीमतों में वृद्धि पर वर्तमान जांच के लिए विचार नहीं किया जा सकता।
- न. सार्वजनिक हित तथा निचले उद्योग की क्षति से संबंधित दावों के संबंध में प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि शुल्क लगाना व्यापार पर बाधा डालने का कार्य नहीं है। इसकी बजाए, इसका लक्ष्य कुछ उत्पादकों और निर्यातकों की अनुचित व्यापार परिपाटियों के निमित्त है तथा एक ओर विदेशी उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच तथा दूसरी ओर घरेलू उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में कार्य करना है।
- प. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों और याचिकाकर्ताओं द्वारा भी कुछ दावे किए गए हैं कि प्रकटन विवरण जारी करने में ही अत्यधिक गोपनीयता बरती गई है। ये दावे आधारहीन हैं। प्राधिकारी ने अगोपनीय मानी गई पूरी सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध आंकड़े, जहां आवश्यक हुआ, गोपनीय सूचना के संबंध में दिए गए हैं।
- फ. निर्यातकों के साथ किए गए पत्राचार, मूल प्रश्नावली के बाद उत्तर के स्तर पर दायर सूचना और सत्यापन रिपोर्टों को प्रकट करने के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इस अनुरोध की कोई वैधता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन दस्तावेजों में निर्यातकों की गोपनीय सूचना है और वह रिपोर्ट प्राधिकारी द्वारा किसी भी पाटनरोधी जांच में प्रकट नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं से एकत्रित किए गए दस्तावेज तथा याचिकाकर्ताओं की सत्यापन रिपोर्ट गोपनीय मानी जाती है और जांच में अन्य पक्षकारों को नहीं दी जाती है।
- ब. उत्पादकों/निर्यातकों तथा सत्यापन के दौरान संशोधन के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए आंकड़ों में उस दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता कि दायर अगोपनीय रूपांतरों में बदलाव आ जाए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने कुछ दावों को सिद्ध करने की मांग की है जो याचिकाकर्ताओं सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सहायक दस्तावेजों के माध्यम से कब दिया गया है। इन आंकड़ों का सार संभव नहीं है और इसीलिए किसी एनसीवी की मांग नहीं की गई थी अथवा दायर नहीं की गई थी।
- भ. याचिकाकर्ताओं ने पाटन मार्जिन के प्रकटन की मांग की है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन प्रकट नहीं किया जा सकता। यह प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप है।
- म. 1000 डेनियर से अधिक वाले एए यार्नों तथा एचएमएलएस गुणधर्मों वाले यार्नों को हटाए जाने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरोध के संबंध में प्राधिकारी ने उसकी जांच "विचाराधीन उत्पाद" के अंतर्गत विस्तार से की है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा एडेजिव एक्स्ट्रिक्ट यार्न के विनिर्माण के संबंध में दिये गये याचिकाकर्ताओं के साक्ष्य के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उनमें 1000 डेनियर के बराबर तथा 1000 से भी अधिक डेनियर वाले एए यार्न शामिल हैं। तथापि, स्थिति यह नहीं है कि सभी एडेजिव एक्स्ट्रिक्ट यार्न विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटा दिए गए हैं। इसकी बजाए, इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि याचिकाकर्ता 1000 डेनियर के बराबर वाले एए यार्न के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता हैं और उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया गया है।
- य. याचिकाकर्ताओं के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने के विरोध के संबंध में केवल इसलिए कि कंपनी "चीनी" कंपनी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को भ्रमित किया गया है। प्राधिकारी ने एमईटी का दावा करने वाले उत्पादक तथा निर्यातक का विस्तृत मूल्यांकन किया है। इस संबंध में, मूल्यांकन "मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि., चीन जन. गण. तथा मैसर्स ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य" के अंतर्गत निहित है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एमईटी प्रदान करने के लिए मूल्यांकन मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है और इसीलिए प्रत्येक परिदृश्य में विद्यमान वास्तविक मैट्रिक्स के आधार पर अलग-अलग होगा।
- कक. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि. के लिए निर्यात कीमत पर संबंधित व्यापारी ह्योसंग कारपोरेशन के एसजीएंडए खर्चों तथा लाभ को घटाने सहित उचित समायोजनों के बाद विचार किया गया है।
- ड. सिफारिशें**
126. जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा एकत्रित अनिवार्य तथ्य और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा सिद्ध तथ्य प्रकटन विवरण में विधिवत प्रकट किए गए थे ताकि विभिन्न हितबद्ध पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एकत्रित इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणियां दे सकें। तदनुसार, टिप्पणियां प्राप्त की गईं और वर्तमान जांच परिणाम के दौरान उन पर विचार किया गया।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा सभी निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच शुरू करने पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, पाटन, क्षति तथा उसके कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच करने पर और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति सिद्ध होने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी निम्नलिखित रूप में वर्णित स्वरूप एवं तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।
128. मामले की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए शुल्क ढांचे के संबंध में अमेरिकी डॉलर के रूप में पाटनरोधी शुल्क के निर्धारित स्वरूप की सिफारिश करना उपयुक्त माना जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन से कम के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

### शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	यूनिट
	5402.2090*	1000 डेनियर से कम और 6000 डेनियर से अधिक वाले यार्नों को हटाकर हाई टेनेसिटी पॉलिस्टर यार्न्स, 1000 डेनियर से अधिक वाले ट्रिबस्टेड यार्न्स, कलर्ड यार्न्स, एधेसिव एक्टिवेटेड यार्न्स तथा एचएमएलएस गुणधर्मों वाले यार्न	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कं. लि.	ह्योसंग कारपोरेशन	शून्य	मी. टन/अमेरिकी डॉलर
	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	1) झेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि. 2) झेजियांग गुक्सियांडाओ पॉलीस्टर	झेजियांग गुक्सियांडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.	174	मी. टन/अमेरिकी डॉलर

क्रम सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	यूनिट
					डोप डाइड यार्न कं. लि.			
	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	जियांग्सू हेंगली केमिकल फाइबर कं. लि.	234	मी. टन/अमेरिकी डॉलर
	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	(1) झेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि. (2) हुझोऊ उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर लिमिटेड	झेजियांग उनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.	316	मी. टन/अमेरिकी डॉलर
	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	ऑरियंटल इंडस्ट्रीज (सुझोउ) लि.	ऑरियंटल टेक्सटाइल (होल्लिंग) लि.	शून्य	मी. टन/अमेरिकी डॉलर
	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	क्रम सं. 1 से 5 को छोड़कर कोई भी संयोजन		528	मी. टन/अमेरिकी डॉलर
	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	528	मी. टन/अमेरिकी डॉलर
	- वही -	- वही -	कोई अन्य	चीन जन. गण.	कोई अन्य	कोई अन्य	528	मी. टन/अमेरिकी डॉलर

\* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

129. इस अंतिम जांच परिणाम के कारण उत्पन्न होने वाली केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION****New Delhi, the 24th May, 2018****FINAL FINDINGS****(Case No. OI 19/2017)**

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “High Tenacity Polyester Yarns” originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/12/2017- DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD rules”), thereof;

**A. Background of the Case**

2. M/s. SRF Limited and M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “Applicants” or “Petitioners” or “Domestic Industry”) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Act and the AD Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “**High Tenacity Polyester Yarn**” (hereinafter also referred to as the “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”), and requested for initiation of an investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.
3. The Authority on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant issued a public notice in accordance with Rule 6(1) of the Rules vide Notification No.6/12/2017-DGAD dated 15<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
4. In the initiation notice, the PUC was inadvertently identified as “*High tenacity polyester yarn*” without any exclusions, although the Petition itself had excluded some products. Accordingly, the Authority issued a corrigendum vide Notification F.No.6/12/2017-DGAD dated 22 September, 2017 to the initiation notice dated 15 June, 2017, whereby the Authority identified the PUC as “*High Tenacity Polyester Yarn, excluding yarn below 1000 denier, coloured yarn and twisted yarn*”. The revised petition with the determined PUC and POI was filed by the Petitioners on 13<sup>th</sup> October, 2018.

**B. Procedure**

5. The procedure described below has been followed:
  - a. The Authority under the AD Rules, received a written application from the petitioners on behalf of domestic industry of subject goods, alleging dumping of subject goods originating in or exported from subject country and resultant injury to the domestic industry and requesting recommendation for imposition of antidumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
  - b. The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.

- c. The Authority sent copy of initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/ exporters from the subject country and known importers/ users/ associations of the subject goods as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- d. The Authority forwarded copy of the non-confidential version of the application to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from the subject country and known importers of the subject goods, in accordance with the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- e. The Embassy of China PR in India was also requested to advise the producers/exporters from their country to file their responses within the prescribed time limits.
- f. The Authority sent the exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
  - 1. Zhejiang Guxiandao New Materials Co. Ltd.
  - 2. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd.
  - 3. Jiang Su Heng Li Chemical Fibre Co. Ltd.
  - 4. Hangzhou Huachun Chemical Fibre Dyeing and Weaving Co. Ltd.
  - 5. Oriental Industries (Suzhou) Ltd.
  - 6. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd.
  - 7. Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd.
- g. The following producers /exporters filed a response to the Exporter's Questionnaire in the prescribed format:
  - 1. Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd.;
  - 2. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Co. Ltd.;
  - 3. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.;
  - 4. Hyosung Corporation, Korea RP;
  - 5. Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd.;
  - 6. Jiangsu Taiji New Materials Co. Ltd.;
  - 7. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd. and
  - 8. Huzhou Unifull Industrial Fibre Ltd.
  - 9. Oriental Industries (Suzhou) Limited
  - 10. Oriental Textile (Holding) Limited
- h. Except for M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR alongwith its trader, M/s Hyosung Corporation, Korea RP and M/s. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd., China PR none of the producers/ exporters from China PR have responded to the Market Economy Treatment (MET) Questionnaire. Hence, the other, cooperating exporters have been given non-market economy treatment in the present investigation. M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR along with their trader, M/s Hyosung Corporation, Korea RP and M/s. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd., China PR claimed market economy treatment and have submitted Market Economy Treatment (MET) questionnaire response.
- i. Questionnaires were sent to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
  - 1. Shakti Cord
  - 2. Tuffropes
  - 3. India Nets
  - 4. Ferreterro India Pvt. Ltd.
  - 5. Garware Wall Ropes Ltd.
  - 6. Autoliv India Pvt. Ltd.
  - 7. Maccaferri Environment Solutions Pvt. Ltd.
  - 8. Poly Hose India
  - 9. Strata Geosystems (India) Pvt. Ltd.
  - 10. Maruti Rub Plast



11. Axiom Ropes
  12. Khosla Profil
  13. Techfab India Industries Ltd.
- j. The following importers/users filed a response to the Importer's Questionnaire in the prescribed format:
1. Shakti Cords
  2. Garware Wall Ropes Ltd.
  3. Strata Geosystems (India) Pvt. Ltd.
  4. Techfab India Industries Ltd.
  5. Autoliv India Pvt. Ltd.
  6. Madhuram Fabrics Pvt. Ltd.
  7. Madura Coats Pvt. Ltd.
  8. Mehler Engineered Products India Pvt. Ltd.
  9. Vardhman Yarns and Threads Ltd.
- k. Submissions were also made from time to time by the parties who filed Questionnaire Responses. Other than such parties, comments were also received from the following parties, and have also been considered:
1. China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles;
  2. Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd.;
  3. Sanrhea Technical Textiles Ltd.
- l. Letters filed from time to time have also been considered, including comments on PUC issues, PCN comments, claims for product exclusions, etc. made by various parties over the course of the present investigation.
- m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the domestic industry, producers / exporters and the importers in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present disclosure statement.
- n. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- o. Further information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary.
- p. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- q. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules. It has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- r. Verification of the information provided by the applicant domestic industry was carried out by the Authority during 29-31 January 2018 to the extent deemed necessary. Similarly, during 02-07 April 2018 the Authority verified, on-site in China PR and Korea RP, the data and information provided by some of the exporters. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- s. Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> April 2016 to 31<sup>st</sup> March 2017 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.

- t. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted for the purpose of the present investigation.
- u. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- v. Based on the suggestions put forward by the Petitioners, and comments received thereon, the Authority constructed the PCN classification and circulated the same on 20<sup>th</sup> March, 2018. Revised Questionnaire responses based on the PCN classification were received from the Exporters on 27<sup>th</sup> March, 2018.
- w. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 13 March, 2018. All the parties attending the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally by 20<sup>th</sup> March, 2018. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders by 26<sup>th</sup> March, 2018.
- x. The arguments made in the written submissions and rejoinders submissions as well as letters received from time to time from the interested parties have been considered in the present findings.
- y. In accordance with the Rules, the Authority also disclosed the essential facts of the present investigation to all interested parties vide a disclosure statement issued on 4<sup>th</sup> May, 2018, and advised them to file the comments on the disclosure statement by 14<sup>th</sup> May, 2018. The comments received from the domestic industry and other interested parties have been addressed in this findings to the extent considered relevant.
- z. Exchange rate prevailing during the POI for conversion of US\$ to INR is considered as INR 67.95=US\$1 and has been adopted by the Authority.
- aa. In this notification, \*\*\* represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

**C. Product Under Consideration and Like Article**

Views of the producers/exporters, importers and other interested parties

- 6. The following submissions were put forward by exporters/importers/other interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article:
  - a. The PUC should be revised to exclude certain products, such as Adhesive Activated Yarns, Yarns having denier greater than 6000 and High Modulus Low Shrinkage (HMLS) Yarns.
  - b. With respect to yarns having denier more than 6000, the interested parties submitted that the Domestic Industry does not produce such goods. Therefore, the same should be excluded from the PUC.
  - c. With respect to adhesive activated yarns, it was submitted that the Domestic Industry was unable to supply HTPY Adhesive Activated having denier more than 1000D.
  - d. The Petitioners do not have stable production of Adhesive Activated yarns in the full range. If duties are imposed on these goods, it would make the producers of RFL dipped Fabrics unnecessarily uncompetitive.
  - e. The Petitioners do not produce twisted yarns and therefore the same also should be excluded.
  - f. With respect to HMLS yarn, it was submitted that HMLS yarns are unique in their characteristics. It was claimed that the Domestic Industry does not supply the same. In this regard, the interested parties pointed out

that the Petitioner RIL had admitted during the Oral Hearing that it launched its HMLS facilities only recently. Therefore, during the POI, the Petitioner RIL was not producing or supplying HMLS yarns. Moreover, the other Petitioner-SRF- appears to captively consume the entirety of its HMLS yarn production and therefore, even SRF does not supply the HMLS yarn to the domestic market.

- g. One of the producers namely Reliance Industries Ltd admittedly does not have even the capacity to produce HMLS and SRF Ltd did not supply the same citing reason that they can only produce it against order with complete specification to be provided by the user. Effectively, the domestic industry did not supply HMLS in the POI and this should lead to the exclusion of HMLS from the scope of PUC and the interested parties have prayed for the same.
- h. The producers should supply HMLS yarn sample which would be tested by the user and further fine-tuned as per the user's requirement. It involves detailed analysis of behavior in plant and consistency of the product. Thereafter, the process of customer approvals starts. This takes at least 2 years to complete. The long period of approvals is well accepted by the petitioners in the written submission and oral hearing.
- i. There is no case for the inclusion in the PUC of products having denier more than 6000, Adhesive Activated yarns having denier more than 1000 and yarns having HMLS properties.

#### Views of the domestic industry

7. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
  - a. The PUC is High Tenacity Polyester Yarns excluding yarns having denier below 1000, twisted yarns and coloured yarns.
  - b. With respect to the claim for exclusion of HMLS yarns, it was submitted that it is not necessary for each constituent of the domestic industry to produce the like article. During the POI, SRF has both produced and sold HMLS yarns. The said product is not being used solely for captive consumption. SRF has also offered to sell such yarns to M/s Shakti Cords, one of the interested parties, and therefore, argument that such yarns are not being produced or sold have no merit.
  - c. Even RIL has the capacity to produce and sell HMLS yarns. However, owing to lack of approvals and specifications of the product, the same have not been supplied. Despite offering the product to M/s Shakti Cords, the sales did not materialize because M/s Shakti Cords was unable to provide a sample yarn for ascertaining the exact specifications of the product.
  - d. The evidence on record shows that HMLS yarn was produced and supplied by the domestic industry during the POI.
  - e. Regarding the clubbing of HMLS yarns in the "others" category, it is submitted that detailed PCN wise categorization has been proposed by the Authority and therefore, this issue is invalid.
  - f. Moreover, the law under Rule 2(b) does not require the subject domestic industry to be engaged in supply of the like article during the POI. Rather, read with Rule 2(d), it is clear that the domestic industry is required to be engaged in the manufacture of the like article.
  - g. With respect to the request for exclusion of Adhesive Activated yarns having denier more than 1000, it is submitted that it is not necessary for each constituent of the domestic industry to produce the like article. In the present case, during the period of investigation, SRF has produced and sold adhesive activated yarn of more than 1000 deniers.
  - h. Non-production or low production volumes of certain varieties of the yarn was more due to the disinterest of the domestic consumers to buy from the DI rather than an inability of the DI from producing the same. The

main reason for the domestic consumers preferring to import their requirements was the dumped prices rather than due to quality issues or inability of the DI to supply the required volumes.

- i. Requests have been made for exclusion of yarns having denier more than 6000. However, no reasons have been provided for such claims. The Authority has held in past cases that for claiming an exclusion, there should have been either imports of the product type for which exclusions are sought or the domestic industry should have failed to supply the said product. Where no such case has been made out, the claim for exclusion from the PUC is unjustified.

#### Examination of the Authority

8. In the initiation notice, the product under consideration in the present investigation has been taken as “*High Tenacity Polyester Yarn, excluding yarn below 1000 denier, coloured yarn and twisted yarn*” also known as polyester industrial yarn (PIY) or industrial yarn (IDY) in market parlance. High tenacity Industrial Grade yarn has various grades depending on end application requirement such as Regular Adhesive Activated (AA), Regular Adhesive Non-activated (NAA), High Modulus Low Shrinkage Adhesive Activated (HMLSAA), High Modulus Low Shrinkage Non-Adhesive Activated (HMLS NAA), Low Shrinkage (LS), Super Low Shrinkage (SLS), Ultra Low Shrinkage (ULS), Dope Dyed Yarn.
9. The subject goods are used for manufacture of wide variety of products like - tyre cord fabric, seat belt webbing, Geo grids, geo strips, slings, ropes, single cord, coated fabric, conveyor belt fabric, rubberized hose, fire hose, automotive hose, etc. PUC is classified under Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 5402.2090. The Customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.
10. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD Rules provides as follows: -“*like article*” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
11. The interested parties have sought exclusion of a number of product types from the scope of PUC on the grounds that the domestic industry does not produce and/ or regularly supply the product in the desired product type, or, the quality of the product produced and supplied by the domestic industry is not up to the satisfaction of the users. The arguments of interested parties have been examined by undertaking on the spot verification at the premises of the petitioning companies and calling for relevant information from the interested parties.
12. The Petitioners had submitted PCN classification in their Petition and accordingly, data was received from the interested parties. Thereafter, the PCN was clarified by the Petitioners vide their communication dated 12 March, 2018. The Authority circulated the same to the interested parties and sought comments regarding the same. Comments were received from various interested parties pertaining to the classification and the testing criterion for each of the classification adopted in the PCN classification. Accordingly, and post- discussions with the domestic industry as well, the Authority issued the PCN classification on 20<sup>th</sup> March, 2018 and revised questionnaire responses were required to be filed by 27<sup>th</sup> March, 2018. Accordingly, the revised data was also sought from the domestic industry and received.
13. The Authority notes that based on the submissions of the interested parties, the following four claims for exclusion of certain types of yarns need to be examined:
  - a. Twisted Yarns;
  - b. Yarns having denier more than 6000;
  - c. Yarns having Adhesive Activated coating having denier more than 1000; and
  - d. Yarns with High Modulus Low Shrinkage (HMLS) properties.
14. Before examining the claims for exclusion, the Authority would like to point out that based on information provided by both sides it is clear that the PUC is a technical yarn. A variety of technically specified fabrics/ goods are being produced using these yarns. It therefore, cannot be denied that the purchase decision for a large

proportion of these yarns would include the verification/ ascertainment of some level of technical specificity or performance requirement. The purchase decision cannot be price-based alone. While the Authority cannot go into the reason behind why every individual offer to supply was accepted or rejected, it is confident that any decision based on the actual production/ sales performance is fair to both the sides.

15. With respect to the claim for exclusion of Twisted Yarns, the Authority notes that the scope of PUC in any case does not include twisted yarns. Thus, any HTPY Twisted Yarn is beyond the scope of present investigation. The Domestic Industry has excluded the following types of yarns from PUC at the stage of filing the petition itself:
  - a. Yarns having denier below 1000;
  - b. Twisted Yarns; and
  - c. Coloured Yarns.

16. Thus, the claim for exclusion of twisted yarns is unwarranted.

17. With respect to the claims for exclusion of yarns having Adhesive Activated coating and of denier more than 1000 and HMLS Yarn, the Authority notes as below:

	Unit	AA Yarns Denier > 1000		HMLS Yarns	
		SRF	RIL	SRF	RIL
Production	MT	***	NIL	***	NIL
Merchant Sales	MT	***	NIL	***	NIL
Merchant Sales as % of Production	%	0.78%	NIL	1.74%	NIL

18. The above table shows that the Domestic Industry has production and sales of Adhesive Activated yarns having denier up to 2000. However, it is noted that the Domestic Industry has negligible sales of Adhesive Activated Yarn having denier more than 1000 and up to 2000 in the merchant market. In light of the same, there is merit in the claim of the interested parties that the petitioners do not supply Adhesive Activated yarns “in the full range”. The Authority also notes that even though SRF has produced Adhesive Activated Yarns having Denier more than 1000 during the POI, it has only commercially sold less than 1% of its production of the same. Thus, inclusion of AA yarns having denier more than 1000 within the scope of PUC and the current investigation is inappropriate. Accordingly, the Authority has excluded Adhesive Activated yarns having denier more than 1000 from the scope of PUC for the present investigation.
19. Regarding the claim for the exclusion of yarns having HMLS properties, it is noted that HMLS yarn is a yarn having dimensional stability without elongation or stretching under pressure and without shrinking despite heat application. We note that the testing criterion for HMLS yarn, in terms of the PCN classification issued, was determined to be its “dimensional stability index” below 10. The Dimensional Stability Index is measured as the sum of elongation at 4Cn/dtex (tested as per ASTM D885) and hot air shrinkage at 177°C for 2 minutes at 0.05Cn/dtex end load (tested as per ASTM D4974). HMLS yarn is used in products such as tire cords (as reinforcement inside tyres used in passenger cars and light commercial vehicles.), conveyors and v-belts for the mechanical rubber goods industry.
20. Upon receipt of PCN wise information from the exporters and the domestic industry, it was observed that RIL has not produced the HMLS yarn during the POI. Even though SRF has produced HMLS yarn during the POI, it has only commercially sold less than 2% of its HMLS yarn production. Thus, inclusion of HMLS yarn within the scope of PUC and the current investigation would not be appropriate. Accordingly, the Authority has excluded yarns having HMLS properties from the scope of PUC for the present investigation.
21. In the disclosure statement, the Authority had not considered the exclusion for yarns having denier more than 6000, on the understanding that such yarns are actually twisted yarns. Since twisted yarns were already excluded from the scope of the PUC, it was not considered necessary to grant a separate exclusion to yarns having denier more than 6000. In the post disclosure comments, interested parties have brought evidence to the notice of the Authority regarding imports of flat/ untwisted yarns having denier more than 6000. In light of the same, the

Authority finds that there is a legitimate claim for exclusion of HT yarns having denier more than 6000. Based on information available with the Authority, it is also observed that the Petitioners have no production or sales of high tenacity polyester yarn having denier more than 6000 and therefore, there is no domestic supply or competition with respect to the same. Accordingly, the claim of the interested parties for exclusion of yarns having denier more than 6000 is accepted.

22. Based on the foregoing, the Authority has considered the PUC as High Tenacity Polyester Yarns excluding:
- Yarns having denier below 1000;
  - Yarns having denier above 6000;
  - Twisted yarns;
  - Coloured yarns;
  - Adhesive Activated yarns with denier higher than 1000; and
  - Yarns with HMLS properties.

**D. Domestic Industry and Standing**

Views of the producers/exporters, importers and other interested parties

23. The submissions made by the exporters/importers/other interested parties during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry and standing are as follows:
- The Petitioners have not divulged details of their production capacity even though such information is available in the public domain on their own websites. Production capacity for the Petitioners should be considered on the basis of dedicated capacity for high tenacity polyester yarn rather than the entire industrial yarns segment. Petitioners are manufacturers of multiple products, and only the dedicated capacity to produce subject goods should be considered.
  - One of the Petitioners, SRF, is a 'manufacturer of the subject goods for captive consumption' and sells only a marginal portion of its production in the domestic market. Therefore, such producer cannot be considered as a constituent of the domestic industry as its costs are incomparable with a 'manufacturer for domestic sales'. In this regard, the interested parties cited the Authority's finding and CESTAT decision in *Low Ash Metallurgical Coke from Australia and China PR (2016)*.
  - The domestic industry has not provided the details of captive production by SRF Ltd. Rather, it has assumed, without providing any relevant evidence on record, that it is a part of the domestic industry and that there is no need for any examination of captive production to determine SRF's inclusion or exclusion in the current investigation.
  - One of the Petitioners, SRF, is an importer of the subject goods from the subject country and therefore, may be excluded in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.
  - SRF's import are about 714.82 MT from China PR in the POI out of total import of 15524 MT and work out to about 4.64% share in total imports which is a substantial share.
  - The domestic industry has not provided any quantitative details of the imports made by SRF Ltd. in their application. It may be seen that the Authority in the recently concluded SSR AD investigation concerning imports of *Melamine from EU, Iran, Indonesia and Japan (2018)* did not allow the domestic industry to claim confidentiality over the imports made by the domestic industry.
  - Since one of the Petitioners is an importer itself, even if it is to supplement a different line of products, there is apprehension that in case of imposition of anti-dumping duties, the Petitioner would resort to increased captive consumption which is at present being met by importation of subject goods.
  - Admittedly, there is a third producer in India- M/s Fairdeal Jumbo Packaging Pvt. Ltd. Moreover, it is functioning well in the market, and is not suffering any injury.

- i. The constructed normal value of producers/ exporters in the present case cannot be constructed on the basis of the Petitioners' captive costs and neither can the NIP of the Petitioners be based predominantly on this captive price of the Petitioners.

Views of the domestic industry

24. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of domestic industry and standing, considered relevant by the Authority, are as follows:
  - a. The Petitioners account for substantial percentage of domestic production and therefore, they have the requisite standing to file the present petition. Even assuming that some part of the production is done by another producer in the domestic industry, the Petitioners still have substantial percentage of production and therefore, have standing for the purposes of the present petition.
  - b. The Petitioners have provided details of only dedicated capacity of the subject goods. The data in this regard has already been verified by the Designated Authority for adequacy and accuracy.
  - c. Captive consumption does not mean that the producer is ineligible to be treated as domestic industry. SRF has utilized 56% of its production captively, which establishes that it was not producing for "self-consumption". Rather, though the captive consumption was lower in the beginning of the period of injury, SRF was able to increase captive consumption with increase in demand but was unable to commensurately increase its domestic sales owing to dumped imports. Thus, the ratio of captive consumption to production increased over the period.
  - d. The Authority has, in the past, considered captive producers of subject goods as part of eligible domestic industry. Reliance was placed on the Final Findings in *Vitamin E from China PR (2003)*.
  - e. The facts and circumstances in the case of *Low Ash Metallurgical Coke from China PR and Australia (2016)* are distinguishable from the present facts as the domestic sales in that case were negligible while SRF has significant merchant sales.
  - f. The Authority may consider the standing of the Petitioners after excluding the production meant for captive consumption.
  - g. The mere fact of importation does not lead to a foregone conclusion regarding the exclusion of the said importer from the Domestic Industry, rather, there exists discretion with the Authority in this regard.
  - h. The claim pertaining to increased captive consumption to replace importation in case of imposition of duty is entirely baseless. M/s SRF Limited has been importing the subject goods under advance license to produce downstream products for export. Such practice can be easily continued even after imposition of duties.
  - i. Submissions by Shakti Cords pertaining to SRF's importation are inaccurate. The data filed by the domestic industry clearly shows that SRF imported merely 50.4 MT of the subject goods from the subject country. Therefore, the imports made by M/s SRF Limited constitute only 0.3% of the imports from the subject country, which is insignificant. Even if the imports had been amounting to 4% as claimed by Shakti Cords, it would still not qualify as a significant share, particularly when the imports were made under advance license for the purpose of exportation.
  - j. M/s Fairdeal Jumbo Packaging Pvt. Ltd. has opted not to participate in the present investigation and therefore, the Domestic Industry is unable to comment on the veracity of claims regarding its functioning and lack of injury. The interested parties have merely made statements regarding the same without supplying any evidence in this regard. During the hearing, one of the interested parties had clarified that the production of M/s Fairdeal Jumbo Packaging Pvt. Ltd. is insignificant and of poor quality, indicating that the producer is not performing well.

## Examination of the Authority

25. Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”*

26. The application has been filed by two producers, RIL and SRF, claiming that their production put together is more than 90% of Indian production. It is an admitted position that there is a third producer, M/s Fairdeal Jumbo Packaging Pvt. Ltd. However, the said producer has not come forward and none of the parties to the investigation have supplied any evidence regarding its production capacities. The Authority finds that in view of the lack of any information brought on record by any of the parties to the investigation and the non-participation of M/s Fairdeal Jumbo Packaging Pvt. Ltd., the said producer cannot be considered for the purposes of injury determination. Therefore, the Authority has considered SRF and RIL as the constituents of the domestic industry.
27. Further, claims have been made by various interested parties that SRF may not be considered as part of the eligible domestic industry owing to its captive consumption and the fact of importation from China PR. The Authority has examined whether SRF can be considered a captive producer by verifying the quantum of production consumed captively and the quantum sold in the merchant market. It is observed that SRF's production is evenly distributed between self-consumption and merchant sales. In light of the same, it would be inappropriate to consider SRF as a captive producer and disregard its production going into merchant market. Moreover, inclusion of SRF as part of the domestic industry allows for a more holistic understanding of the injury parameters. Therefore, the claims made by the interested parties are not pertinent in the facts of the present case.
28. Moreover, with respect to the importation of the subject goods, the Authority retains the discretion to determine whether a producer may be considered eligible to constitute domestic industry despite its importation of the subject goods from the subject country. In the present case, it is noted that marginal volumes, amounting to less than 0.5% of imports are attributable to the Petitioner-SRF. Thus, to conclude that the main business activity of SRF is importation of the subject goods would be inappropriate. In light of submissions made at the post-disclosure stage, the Authority also notes that such marginal importation by the Petitioner SRF could not have, and did not, contribute to the injury suffered by them or the Petitioners considered together.
29. Therefore, the Authority holds that the Petitioners command a major proportion of the production of the subject goods in India. For the purpose of this investigation the Petitioners satisfy the standing requirement in terms of Rule 5(3) and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

**E. Excessive Confidentiality**

Views of the producers/exporters, importers and other interested parties

30. The submissions made by the exporters/importers/other interested parties during the course of the investigation with regard to excessive confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
- a. The Petitioners have failed to disclose critical and basic information in the Petition and over the course of the investigation. Such data is normally revealed by the Authority at the time of disclosure and / or Final Findings, and therefore, there is no reason for keeping the same confidential and denying the Respondent herein an opportunity to address the factual situation. Various cases were cited in this regard.
- b. Excessive confidentiality has been claimed by the Petitioners with respect to basic parameters such as capacity, captive consumption of the Petitioners, Indian Demand, Production volume of the domestic industry, Total Indian production, Sales volume of the domestic industry, Export volume of the domestic industry, Capacity



Utilization, Domestic Market Share of Petitioners, other Indian producers, Imports from the subject country and Imports from Countries not subject to investigation.

- c. Moreover, certain Parameters prescribed in Proforma IV(A) have been kept confidential and not provided at all, not even in indexed form. Such parameters include Captive Consumption Value, volume related figures of sales without captive consumption as well as including captive consumption, volume related figures of demand without captive consumption and as well as including captive consumption Total Sales Value, Inventories (Volume)- Opening Stock and Closing Stock, Sales figures pertaining to Export Sales, Profit and Loss figures pertaining to Export Sales, Interest, Depreciation, Capital investment for expansion, Net Fixed Assets and Working Capital. Even the percentage figures of profit/ loss & ROCE as well as the export volumes have been kept as confidential.
- d. The domestic industry has not provided the details of company-wise production of the applicants and also of the other domestic producer or share in total domestic production of Indian producers. The domestic industry has not provided the details of captive production by SRF Ltd.
- e. The Petitioners are multi product companies and therefore, are required to provide product-specific financial statements.
- f. Certain data claimed as confidential was revealed by the Petitioners at the time of oral hearing, invalidating any confidentiality claims put forward by them.
- g. Excessive confidentiality has been claimed by the Petitioners in order to prevent a clear understanding of the extent of captive consumption which is high; the level of capacity utilization which is optimum; and that the imports are entering to cater to the growth in demand (42%) which is beyond the optimum capacity of the Petitioner.
- h. The Petitioners have failed to declare their imports and relationship with the importers and exporters of the subject goods.
- i. The Petitioners have not enclosed the costing formats as part of the Petition. Even the names of the raw materials and other relevant details which are helpful in understanding the details of the production process as well as other relevant information have been claimed as confidential.
- j. The sole purpose of Petitioners' claim of excessive confidentiality is to prevent a clear understanding that the extent of captive consumption is very high, the level of capacity utilization is optimum, and that the imports are entering to cater to growth in demand which is beyond optimum capacity of petitioners.

Views of the domestic industry

31. The submissions made by the domestic industry with regard to excessive confidentiality, considered relevant by the Authority, are as follows:
  - a. The Petitioners have put forward the claim that Exporters/ Producers have abused confidentiality provisions. In this regard, the Petitioners have claimed that certain critical information, such as list of related parties involved in the PUC production / sales, specifications of the PUC, PCN used by the producers/ exporters, list of documents provided to substantiate domestic and export sales, volume and value of domestic sales, list of key raw materials, etc. have not been disclosed in the non-confidential version of the Questionnaire responses filed by the producers/ exporters.
  - b. With respect to the costing information, all relevant data has been supplied to the Authority in the required application formats. Moreover, all the injury parameters have been provided in the indexed form sufficient to allow the parties to argue the case on merits.

- c. The claims for provision of product specific data are beyond what is contemplated in the law. As per the AD Rules, where separate identification of data for a particular product is not possible, then the narrowest range of products should be considered. Besides, neither SRF nor RIL maintains product-specific Balance Sheet or statement of profit and loss.
- d. By contrast, the producers and exporters have abused the provisions with regard to confidentiality and have claimed even such information, the disclosure of which could hardly be prejudicial to their interests, as confidential. Furthermore, no trends or indexed data has been provided, and in most cases, an appropriate non-confidential summary of the data has not been provided.
- e. Disclosing data pertaining to captive consumption would be tantamount to disclosing actual details of captive consumption of SRF, which would be prejudicial to it.
- f. The claim that Petitioners have exercised excessive confidentiality to mislead parties and the Authority regarding the fact that Petitioners are performing at optimum capacity is baseless. Even assuming such facts, even such imports cannot be dumped into India and cause injury to the domestic industry, which is the case here.
- g. Details of capacity have been claimed as confidential as it pertains to the dedicated capacity for the production of product under consideration rather than its capacity to produce industrial yarn as a whole, which is the data available in the public domain.
- h. As regards the claim that Petitioners should have declared their imports and relationship with the importers and exporters of the subject goods, it is noted that the prescribed formats of the Authority require no such mandate. In any case, all relevant information has been provided.
- i. There is no requirement to provide the details of or share in production for each constituent of the domestic industry, even in the indexed form. The injury parameters are required to be provided for domestic industry as a whole, and the same has been duly provided, subject to the requirements to maintain confidentiality of business sensitive information.

#### Examination of the Authority

- 32. With regard to the confidentiality of information, the Authority notes that the information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim in accordance with Rule 7 of the AD Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not kept open in public file. The Authority has also considered the confidentiality claims of other interested parties in accordance with the aforesaid rule and its consistent practice.
- 33. As regards the argument on the deficient information provided by the petitioners, the Authority notes that the information provided by the petitioners in the application was as per the proforma prescribed and only upon satisfaction of the merit of the case, the Authority initiated the present investigation.

#### F. Miscellaneous Issues

##### Views of the producers/exporters, importers and other interested parties

- 34. Certain other submissions were also put forward by the exporters/ importers/ other interested parties pertaining to miscellaneous issues:
  - a. The initiation notice issued by the Authority is illegal and travels beyond the mandate of the Indian AD Rules and the WTO ADA, and therefore, the subject investigation merits termination. The basis of the claim is that issue of corrigendum is belated and cannot substitute the improper initiation in the present case.

- b. The Petitioners filed the non-confidential version (NCV) of the petition on 21 June, 2017. Thereafter, on 18 July, 2017 another NCV was filed changing PUC and complete data citing certain inadvertent errors in the previous NCV version. Upon the Authority's corrigendum, another version of the Petition was filed. The changing versions warrant termination of the Petition.
- c. The Petitioners have only provided updated data and have not filed complete petition. Moreover, the Petitioners' data has undergone massive changes in the process of updation, even for prior years, which needs to be justified.
- d. The Authorization letter and certificate of correctness pre-date the end of period of investigation.
- e. The Petitioners have not provided the transaction-wise import data obtained from IBIS as well as DGCI&S in the current investigation.
- f. The PCN proposed by the DI in its post initiation submission are not appropriate and fails to account for specific products like HMLS.

#### Views of the domestic industry

35. Certain other submissions were also put forward by the exporters/importers/other interested parties pertaining to miscellaneous issues:
- a. M/s Autoliv India Pvt. Ltd. and M/s Garware Wall Ropes Ltd. have not filed a response to the Importers Questionnaire. These parties have chosen not to co-operate with the Authority.
  - b. The Petition has undergone change owing to discussions with the Authority and agreement to exclude certain products from the PUC and owing to the revision of the POI. The allegations being made are clearly intended to unnecessarily undermine the credibility of the petitioning domestic industry.
  - c. The Petitioners had filed duly documented petition for the PUC at the time of initiation of the investigation. Thereafter, when the POI was modified by the Authority at the time of initiation, the updated data for the POI was duly filed on 13 October, 2017. In terms of Rules 5 and 6 of the AD Rules, the Petitioner could not have filed a fresh application post initiation of the investigation.
  - d. The petitions were duly accompanied by the certificate of correctness and the authorization letter at the time that they were filed, i.e., 17th March, 2017 (CV) and 21st June, 2017 (NCV). In any case, since verification of the domestic industry has been conducted by the Authority, such claims are unfounded.
  - e. With respect to provision of import transactions data, the same has been provided to the Authority. There is no requirement to make the same available in excel version to the interested parties.
  - f. The Authority has issued the PCN methodology to be used in the present investigation, pursuant to comments and detailed discussions with all interested parties.

#### Examination by the Authority

36. The various submissions made by the interested parties and the Petitioners with regard to miscellaneous issues as recorded above have been examined and addressed below:
- a. The Authority sees no illegality in the issuance of corrigendum to the initiation notice. Moreover, it is unclear how the exclusion of products, as was done by the Corrigendum issued by the Authority, has been prejudicial to the interested parties. Further, it is noted that the Authority, post-initiation of the investigation came to the conclusion that certain products merit exclusion and therefore, the same was notified to the parties.

- b. It is noted that the changing petitions in the present case are inconvenient and contrary to the time-bound proceedings as in an anti-dumping investigation. However, given the facts and circumstances of the present case, where the Authority modified the PUC and the POI, it is found that the Petitioners were fully justified in the revision of the data as was required.
- c. The petitioners are obliged to provide all relevant information for the updated POI, which has been done.
- d. The claims of the interested parties pertaining to re-filing of Authorizations and certificates by the Petitioners in line with the updated POI are without merit in the facts of the present case. The Authority has verified and scrutinized the data of both the petitioners and therefore, the absence of such authorization and certificates have not vitiated the proceedings in any manner nor caused any prejudice to the interested parties.
- e. The issue regarding PCN has been considered under the PUC issues. However, it is observed that the submissions recorded herein were made prior to finalization of the PCN and therefore, are meritless. The Authority has concluded the PCN based on comments from the interested parties as well as the domestic industry. In fact, the PCN followed in the present case has addressed the claims of the interested parties.
- f. With regard to the request for provision of import data the Authority would like to point out that Trade Notice No. 7/2018 dated 15 March 2018 provides that the Authority, on the basis of a written request would authorize the bona fide applicant to obtain the Transaction-wise import data from DGCIS. While the hard copy of the import data (processed/ transformed data) submitted by the applicant/ petitioner industry to DGAD at the time of filing of the application can also be accessed by the interested parties, but only after providing a prescribed declaration/ undertaking. It is therefore for the interested party to seek authorization from the Authority for obtaining transaction wise data for analysis.
- g. The Petitioners' claim that M/s Autoliv and M/s Garware have not filed the importers' questionnaire response and are therefore, non-cooperative is entirely baseless. The Authority has received the responses of these parties and has made available the responses filed by these companies in the Public File.

**G. Determination of Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Dumping Margin**

Views of the producers/exporters, importers and other interested parties

37. The following submission was made by the producers/ exporters/ importers/ other interested parties with regard to market economy treatment, normal value, export price and dumping margin.
- a. The construction of the Normal Value for the subject country is deeply flawed. The consumption norms used to calculate the normal value have not been provided. All elements considered in the Normal Value, such as raw materials cost, utility, conversion cost, selling, general and administrative costs, have been considered as per the Petitioners' costs in violation of the WTO AD Agreement and the Indian AD Rules.
  - b. Construction of Normal Value on the basis of the price actually paid or payable in India may only be considered as a sound basis for construction of the normal value after the prior two options listed under para.7 of Annexure I of the AD Rules have been exhausted. Without exhausting such options, the usage of such a methodology is clearly in contravention of the requirements of paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules.
  - c. In case the Authority opts to rely upon a constructed normal value based on the experience of domestic producers in India, then the same must be based on only the most efficient domestic producer. This is the consistent practice of the Authority and should not be deviated from.
  - d. Moreover, even when a producer/ exporter is not granted market economy treatment, the consumption norms of the producer/ exporter must be considered for determination of normal value.

- e. There is no evidence of adjustments made in export price such as ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight expenses, bank charges, commission, or the basis thereof has been provided in the petition.
- f. The adjustments claimed by the domestic industry from the export prices are on the higher side resulting in exaggerated claims of dumping in the current investigation. The present initiation was done on the basis of incorrect facts.
- g. The constructed normal value of the producers/ exporters cannot be constructed on the basis of the Petitioners' captive costs and neither can the NIP of the Petitioners be based predominantly on this captive price of the Petitioners.
- h. The Authority must consider Normal Value, Export Price and in turn, dumping margin on the basis of data provided by the producers / exporters and duly verified by the Authority.
- i. That in accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, the Normal Value for the producer / exporter should be based on its domestic sales and cost of the subject goods as the period of 15 years for NME treatment expired on 11 December, 2016.
- j. That in accordance with relevant provisions of the Protocol on China's accession to the WTO, the "surrogate country" practice in Anti-dumping actions should be lacking in multilateral legal basis since 11th Dec, 2016. Such practice is bound to expire from then on. We therefore request the Indian investigating authority not to use "surrogate country" methodology in calculating the normal value for this case, regard less whether treating China PR as a market economy country.
- k. "*Pacta sunt setvanda*" is a basic principle and obligation under International Law, which means that no party shall evade its obligations under international treaties for political considerations or in the excuse of domestic laws to treat Chinese enterprises with discriminatory actions which are unfair, unjust and unreasonable. Thus, India must fulfill its obligations under relevant agreements, to recognize China's full market economy status, and by amending relevant domestic regulations, to legally stop using the "surrogate country" approach in anti-dumping investigations against China PR. Section 15 of China's Accession Protocol is the relevant provision which directs all member countries to stop using surrogate country approach.

#### **Views of the domestic industry**

38. The following submission was made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:
- a. The domestic industry submitted data, as reasonably available to it, at the time of filing the petition. The Authority was required to be satisfied with regard to accuracy and adequacy of the evidence for the purpose of initiation of investigations. In terms of *Automotive Tyre Manufacturer's Association vs. Designated Authority (2011)*, such *prima facie* satisfaction may be determined on the basis of the cost of production of the petitioner at the time of initiation.
  - b. The interested parties have contended that the Petitioners should have relied on international raw material prices for estimation of normal value without providing any such evidence by themselves.
  - c. Moreover, even the participating producers and exporters have suppressed and misrepresented material information.
  - d. The interested parties have claimed that in case normal value is based on the cost of the domestic producers, it should be based on the cost of the most efficient domestic producer. There is no legal basis to such a claim. Moreover, efficiency of foreign producers cannot be presumed.

- e. Further and without prejudice, the most efficient producer may not refer solely to the producer having the lowest cost of production. Rather, a number of factors may be involved in determining efficiency.
- f. Adjustments to the export price claimed by the Petitioners is based on best estimates in the absence of any public information with regard to actual expense. Actual expenses are within the knowledge of the exporters alone. The adjustments to the export price, as claimed by the petitioners were reasonable estimates on the conservative side.
- g. The exporters have not contended that the amounts claimed by the petitioner are excessive or some adjustment has been claimed by the petitioner for an expense which was not incurred. Since the exporters have now participated in the investigation by filing responses to the Exporters Questionnaire, the export price can be computed on the basis of the information provided by them, if it is found complete in all respects, and on verification is found to be accurate and reliable.
- h. Further, in determining the export price, it should be ensured that the selling, general and administrative expenses and profit margin of each trader involved in selling the goods are appropriately captured and adjusted.
- i. It is also pointed out that the records are kept by the exporters in foreign languages and therefore in any case, not only that the information provided to the Authority is a derived information and must necessarily be verified, but also, the Authority should use services of a translator, as the Authority and the team may not be able to understand these languages.
- j. The Authority should make a meaningful disclosure pertaining to the information filed and claims made by the producers / exporters. In turn, the Authority should disclose the verification reports of the producers / exporters, communications with the exporter and replies filed by them, disclosure of actual dumping margin
- k. The investigation period considered by the Authority in the present case is April, 2016 to March, 2017 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period 2013-14, 2014-15, 2015-16 and POI. Since much of the period of investigation falls prior to the expiry of the abovementioned provision, China PR cannot be treated as a market economy.
- l. Since normal value is constructed on the basis of the cost of production of the domestic industry, therefore details thereof could not have been provided in the NCV.
- m. It is relevant to note that though the methodology of construction of normal value has been questioned by the interested parties, the exporter has done nothing, which would assist in the investigation such as suggesting an appropriate third country and bringing forth information with regard to the domestic prices prevailing therein. The exporter is clearly trying to merely stir up trouble with the intention of misleading the Authority and hampering the present investigations.

### **Examination of the Authority**

#### **G.1 Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR**

39. As regards the computation of normal value for China PR, the Authority notes that the factum of dumping causing injury to the Domestic Industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone are relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April, 2016 - March, 2017. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during most of the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China PR if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

40. It is also noted that in the past three years, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.
41. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information.
42. The Authority notes that the known Chinese producers/ exporters and the Government of China PR have been adequately notified about the requirement of submission of information in the form and manner prescribed and adequate opportunity was also granted to them to make their submissions in this regard.
43. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority in the present investigation, the following Chinese companies have filed exporter's questionnaire response:
  - i. Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd.;
  - ii. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Co. Ltd.;
  - iii. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.;
  - iv. Hyosung Corporation, Korea RP;
  - v. Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd.;
  - vi. Jiangsu Taiji New Materials Co. Ltd.;
  - vii. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd.
  - viii. Huzhou Unifull Industrial Fibre Ltd.;
  - ix. Oriental Industries (Suzhou) Limited; and
  - x. Oriental Textiles (Holding) Limited
44. The Authority notes that M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR along with its trader, M/s. Hyosung Corporation, Korea RP and M/s. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd. have filed market economy treatment (MET) questionnaire as well, to rebut the non-market economy presumption.
45. The exporters questionnaire responses and the market economy treatment questionnaire responses of these responding producers and exporters were examined. On-the-spot verification of records relating to market economy claim was carried out in respect of all the producers/ exporters. The position on the market economy claim, arising out of the verifications, is summed up as below.

(i) **Market Economy Treatment for M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR and M/s Hyosung Corporation, Korea RP**

46. On the spot verification of the information/data submitted by M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR (HCF) and its trader, M/s Hyosung Corporation, Korea RP (Hyosung - Korea) was conducted at the premises of the companies in China PR and Korea RP, respectively, and detailed verification reports were issued to them with an opportunity to offer comments thereon.
47. The Authority verified the records of HCF in great detail. It was noted that HCF operates under the complete control of Hyosung - Korea, which is based in Korea RP and which is the ultimate shareholder of HCF. The Board of Directors comprises entirely of Korean citizens and there are no Chinese (government or otherwise) citizens on the Board of Directors of HCF. The negotiations for sales conditions with the Indian customers are done by Hyosung - Korea directly and orders are placed through a transparent SAP system to HCF. For domestic sales, HCF is authorized by Hyosung - Korea to negotiate sales conditions with Chinese customers. Key Raw materials are procured from unrelated companies. It was also noted that HCF's purchase prices for raw materials reflect the prices on the international market. It was also ascertained that utility consumption is based on

negotiated rates or determined by the suppliers universally for all users. Thus, there is no special or subsidized rate charged.

48. The Authority also examined whether or not there was any state intervention in the processes of HCF. It was found that the company, in line with the its Korean parent company's mandate, maintains Audit Reports in line with internationally accepted accounting principles, i.e., IFRS. This is done to ease consolidation of HCF's financial records into Hyosung's. The same were also scrutinized. The Authority also verified that the recruitment in HCF is done directly from the labour market or through internal referrals, within the framework of labor law in China PR.
49. HCF adopts commercial exchange rate as per the rates announced by the State Administration of Foreign Exchange on the first day of each month to transfer foreign currency transactions into reporting currency transactions. There are no restrictions on the use of HCF's export revenue.
50. The Authority also noted that HCF did not avail itself of any derogation or exemption under the Company Law, Labor Law, Accounting Law, Contract Law, Bankruptcy Law or Property Law of China PR. Finally, it was observed that the company is not subject to any restrictions on the distribution or repatriation of profits or capital invested.
51. Further, the Authority also verified the records of the trader, Hyosung - Korea.
52. Considering the above, the Authority holds that M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR and its trader, M/s Hyosung Corporation, Korea RP have provided information and sufficient evidence to prove that HCF is operating under market economy conditions and is, thus, entitled for Market Economy Treatment status.

**(ii) Market Economy Treatment for M/s. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd., China PR (JTNM)**

53. During the verification visit to China PR, JTNM requested the Authority that the company would like to withdraw its MET claims. Accordingly, Authority has accepted the request of JTMN and allowed them to withdraw the same. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with Para-7 of Annexure-I to the Rules as mentioned in following paragraphs.

**(iii) Normal Value for M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR (HCF) and M/s Hyosung Corporation, Korea RP (Hyosung)**

54. This producer/ exporter was found to be operating under the market economy conditions as explained above.
55. From the response filed by HCF, the Authority notes that HCF has exported only one PCN to India during POI. Accordingly, Authority has determined the normal value for the same PCN. It was noted that during the POI, HCF has sold \*\*\* MT of the comparable PCN in the domestic market. All sales in the domestic market were made to non-affiliated parties during the POI. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. It was noted that profitable transactions were less than 80%, accordingly, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value.
56. HCF has claimed adjustments on account of inland freight and credit expense from the domestic selling price. The Authority has allowed the adjustments for the same. Accordingly, weighted average normal value for HCF has been determined as \*\*\*US\$/MT.

**(iv) Normal Value for producers/ exporters from China PR other than HCF**

57. Since the MET status was finally claimed by only one producer in China PR (with M/s Jiangsu Taiji Industry New Materials Co. Ltd., China PR withdrawing their request for MET during the exporter verification visit of the



investigating team), as discussed above, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation with the exception as mentioned above and proceeds with Para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of all other producers/ exporters from China PR.

58. As per Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, normal value in China PR is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country, or the constructed value in a market economy third country, or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include reasonable profit margin.
59. In view of the above, the normal value for the subject products imported from China PR into India has been determined on “any other basis” by considering best available information with regard to cost of production and after reasonable additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. Accordingly, the normal value comes as under for each PCN for the POI.

PCN	Weighted Avg. CNV \$/MT
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
Average	***

## G.2 Determination of Export Price for producers and exporters in China PR

### (i) Export Price for M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR (HCF) and M/s Hyosung Corporation, Korea RP (Hyosung)

60. HCF has filed questionnaire response along with its related trader, Hyosung. HCF has exported \*\*\* MT of subject goods to India through its trader, Hyosung. HCF claimed adjustments on account of inland freight and port handling expense, ocean freight, ocean insurance, credit expense and bank charge. The same have been allowed, after due verification. The Authority has also verified the information provided by Hyosung and notes that the price at which Hyosung has sold the subject goods to India covers its SGA expenses and also gives a reasonable

profit margin to Hyosung. It is noted that such expenses and profit margin were also deducted from the export price to arrive at ex-factory export price for the producer-exporter, in line with the Authority's consistent practice. Accordingly, the weighted average export price has been determined for HCF- Hyosung as \*\*\* US\$/MT.

**(ii) Export Price for Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd., China PR (Guxiandao IF) and Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd., China PR (Guxiandao PDD)**

61. Guxiandao IF and Guxiandao PDD are both related producers of the subject goods and both have filed questionnaire responses. Guxiandao PDD was also involved in the job work processing of industrial yarns for Guxiandao IF during the POI. Adjustments were claimed on account of inland freight, port handling expense, ocean freight, ocean insurance, credit expense and bank charge. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for Guxiandao IF- Guxiandao PDD as \*\*\* US\$/MT.

**(iii) Export Price for M/s. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd., China PR (JTNM)**

62. JTNM filed the exporters questionnaire response informing that they have directly exported only 'High Modulus Low Shrinkage' yarn to India during the POI. Adjustments were claimed on account of inland freight, ocean freight, ocean insurance, credit expense and bank charge. However, with the decision of the Authority to exempt the HMLS yarn (of all deniers) from the scope of the PUC, the export price for JTNM has not been determined.

**(iv) Export Price for Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd., China PR (JHCF)**

63. From the response filed by JHCF, Authority notes that the company has exported the subject goods manufactured by itself to India directly. Adjustments were claimed on account of inland freight, ocean freight, ocean insurance, credit expense and bank charge. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for JHCF as \*\*\* US\$/MT.

**(v) Export Price for Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd., China PR (ZUIF) and Huzhou Unifull Industrial Fibre Limited., China PR (HUIF)**

64. From the response filed by ZUIF and HUIF, Authority notes that the companies are related producers of the subject goods. ZUIF and HUIF have both exported the subject goods through ZUIF. Adjustments were claimed on account of inland freight, port handling expense, commission, ocean freight, ocean insurance, credit expense and bank charge. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for ZUIF and HUIF as \*\*\* US\$/MT.

**(vi) Export Price for Oriental Industries (Suzhou) Limited (OTIZ) and M/s Oriental Textiles (Holding) Limited China PR (OTTI)**

65. From the response filed by OTIZ and OTTI, Authority notes OTIZ has exported the subject goods through OTTI. It was also noted by the Authority that OTIZ has exported some sample export shipments by Air. Authority has not taken into consideration these sample transactions for the purpose of calculation of export price. Adjustments were claimed on account of inland freight, port handling expense, ocean freight, ocean insurance and credit expense. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for OTIZ through OTTI as \*\*\* US\$/MT.
66. In this regard, the Authority deems it appropriate to address the submission by Oriental Industries (Suzhou) Ltd. regarding its direct exports. The claim put forward by Oriental Industries (Suzhou) Ltd. is not correct. The Authority notes that Oriental Industries (Suzhou) Ltd. has one transaction which has been exported directly by it, rather than through the trade channel. However, the same is not a commercial sale but rather a case of supply of sample. The same has been clearly admitted by Oriental Industries (Suzhou) Ltd. in its response. As noted above, all transactions pertaining to supplies of sample have been excluded from consideration, as these are not sales in

the ordinary course of trade. Accordingly, we reject Oriental Industries (Suzhou) Ltd.'s request to consider it a producer cum exporter in the duty table.

**(vii) Export Price for all other producers/exporters from China PR**

67. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, the Authority has determined export price as \*\*\* US\$/MT based on the responses of the cooperative producers / exporters.

**G.3 Determination of Dumping Margin for producers and exporters in China PR**

68. The export price to India has been compared with the normal value to determine the dumping margin. The dumping margin analysis has been done PCN wise. The dumping margin during the POI for all the exporters/producers from the subject country has been determined as shown in the Dumping Margin Table below.

**Dumping Margin Table**

Country	Producer	Exporter	Normal Value US\$/ MT	Net Export Price US\$/ MT	Dumping Margin US\$/ MT	Dumping Margin %	Dumping Margin (Range %)
China PR	Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Hyosung Corporation	***	***	***	***	Negative
China PR	1. Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd. 2. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.	Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd., China PR	***	***	***	***	15-25
China PR	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
China PR	1. Huzhou Unifull Industrial Fibre Limited. 2. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.	Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.	***	***	***	***	25-35
China PR	Oriental Industries (Suzhou) Ltd.	Oriental Textile (Holding) Ltd.	***	***	***	***	Negative
China PR	Any other combination.	Any other combination	***	***	***	***	45-55

69. It is seen that the dumping margins are significant and above the *de minimis* limits prescribed under the AD Rules in respect of the exports made by all the producers-exporters except Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd and Oriental Industries (Suzhou) Limited of the product under consideration from the subject country.

**H. Determination of Injury and Causal Link**

70. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
71. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.

Views of the producers/exporters, importers and other interested parties regarding the injury claims of domestic industry

72. The submissions made by the exporters/importers/other interested parties during the course of the investigation with regard to the injury claims of the domestic industry and considered relevant by the Authority are as follows:
- a. Failure on the part of the Petitioners to submit adequate evidence of injury and causation constitutes a violation of the requirements of Rule 5(3) of the Rules that the evidence presented be “sufficient” to justify the commencement of an investigation.
  - b. Economic parameters of the Petitioner, such as Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales, have improved over the period of injury and in the POI.
  - c. The data shows declines in capacity during 2015-16 and 2016-17. The reason for such reduction in capacity when the capacity utilization was at the historically high level during the POI is not explained. It cannot be said that imports caused any reduction in capacity.
  - d. Capacity utilization was at the highest level during the POI thus there were no injuries on this account. Similar increases are seen in production also ruling out any adverse effect on this parameter as well.
  - e. The Petitioners have acknowledged in the application that the capacity of the domestic industry is stable throughout the investigation period and there is an 11% increase in the production and capacity utilization of the domestic industry over the injury investigation period.
  - f. It is evident from a comparison of the production and sales figures that the production and sales moved in tandem with each other. If anything, the sales figures increased much more than production figures.
  - g. The decline in total sales is not attributable to an inability to sell in the domestic market but rather reflects increased captive consumption. It is evident that the “decline” in indexed points with respect to total sales of domestic industry is reflective of the Petitioners’ significant increase in captive consumption and limited increase in production.
  - h. It appears that the Petitioners are performing at optimum capacity utilization and therefore, unable to increase sales to meet the expanding market demand which has increased by 42%. At the same time, the Petitioners’

capacity has remained stagnant and captive consumption has increased substantially. Imports from the subject country are simply filling in the gap between the DI's supply and the Indian market's demand.

- i. Since figures of sales including and excluding captive consumption has not been provided, it is observed on the basis of simple average of the index numbers of the sales without captive consumption and captive consumption, that there is an increase of 41% in the sales of the domestic industry over the injury investigation period.
- j. The domestic industry has also not provided the details of the demand including captive consumption. Therefore, as the sales have increased significantly by 41%, the market share of the domestic industry will also show increase and there would be no injury to the domestic industry with respect to market share as well.
- k. The decline in indexed points with respect to total sales of domestic industry is reflective of the Petitioners' poor export performance.
- l. The injury claimed by the Petitioners is owing to their increased captive consumption and poor export performance. The exports made by the applicant producers have declined significantly by more than 74% over the injury investigation period.
- m. The injury claimed by the Petitioners is owing to the inter-se competition between the domestic producers. In this regard, the Annual Reports of SRF were cited.
- n. The domestic industry is historically in losses and these losses cannot be attributed to subject imports. Rather, the same is attributable to the inter-se competition amongst domestic producers.
- o. Petitioners' increased Capital Employed and the resultant increase in depreciation and interest costs, without any increase in fixed assets has contributed to its declining profits.
- p. It is also submitted that any increase in capital employed which related to the capacity expansion being undertaken by the Petitioners, for future commissioning, cannot and must not form the basis of the NIP calculation. We request the Authority to ensure that the same is not factored into the NIP constructed for the Petitioners.
- q. The claims pertaining to price undercutting and price depression as a result of alleged imports from China PR are mere statements. It is common industry knowledge that the raw materials, i.e., PTA and MEG / Polyester Chips determine the price of the subject goods and therefore, the fluctuations in the prices of the subject goods are because of raw material pricing. The raw material constitutes about 80-90% of the total production cost of HTPY. Thus, decline in the prices of the domestic industry is a result of the decline in raw material prices and not due to the alleged dumping from China PR.
- r. Mere existence of parallel pricing trends between subject imports and domestic prices per se does not constitute sufficient evidence to demonstrate the existence of price effect.
- s. The Petitioners have acknowledged in the application that there is an 11% increase in the productivity of the domestic industry over the injury investigation period.
- t. The domestic industry has cleverly provided the details of the average stock which in all fairness cannot provide any meaningful conclusion on injury as it is the closing stock that is to be examined as percentage of production and as well as sales of the domestic industry which will indicate that there is no injury to the domestic industry.
- u. The No. of employees of the domestic industry is stable throughout the investigation period and there is a 52% increase in the wages paid to the employees over the injury investigation period. Petitioners' wages have

increased without any increase in number of employees or commensurate increase in productivity. This has led to high costs without any improvement in productivity which has led to injury, if any.

- v. While total imports increased over the base year, the same must be seen in the light of imports by SRF itself and also by considering the fact that the DI did not supply crucial grades like HMLS and the users were compelled to import.
- w. The reason for the increase of imports from subject countries from 2013 to 2017 is not dumping, but the growth of the Indian market demands following the development of downstream industry.
- x. The trend of per unit profit of the Petitioners moved erratically and the movement in profitability is not comparable to movement in price of imports. Thus, it is evident that there were certain intrinsic other factors driving the profits and cause of such losses are not import price.
- y. When the import price increased in the base year, the profitability of the DI drastically improved from negative levels to positive. Thereafter, there was a slight change in import price between 2015-16 and POI, however, the Petitioners' losses more than doubled. Thus, there is no causality between the two.
- z. The negative profitability has increased in view of the increase in wages cost and as well as increase in interest and depreciation cost as the capital employed of the domestic industry increased by 12% over the injury investigation period indicating that there is no impact on the profitability of the domestic industry due to alleged subject imports.
- aa. Both Petitioners are multi-product companies and the subject product for both of them constitutes a very small share of the total revenue for them. Thus, the ability to raise capital investments is not a meaningful factor in the current investigation.
- bb. There is an increase in production, capacity utilization, sales, market share, wages, productivity etc. It indicates that there is no impact on the growth of the domestic industry.
- cc. Imports from Korea and Taiwan are above the 3% threshold. The price as such from these countries appears to be on the higher side viz. subject country. However, the comparison with NIP still needs to be checked.
- dd. The petitioners have claimed a return of 30% on gross fixed assets. The Authority should adopt actual profit earned by the Domestic Industry during a period when dumping was not alleged and not 22% ROCE. Adoption of 22% gives undue protection to the domestic industry. Reference was made to the *Bridgestone* and *Hyosung Corporation* Case. EC practice in this regard was also referred to.
- ee. A fair reading of the injury parameters in the Proforma IV A shows that the DI did not suffer any injury on account of alleged dumping.

#### **Views of the domestic industry**

73. The following are the submissions with regard to injury related issues made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:
- a. The imports have increased both in absolute terms, as well as in relation to production and consumption in India.
  - b. The imports have had a suppressing and depressing effect on the prices of the petitioning domestic industry.
  - c. The imports are undercutting the selling price and underselling the non-injurious price of the petitioning domestic industry.
  - d. The market share of the petitioning domestic industry has reduced.

- e. Much of the increase in Petitioners' production and capacity utilization is attributable to the increase in captive consumption by the domestic industry. If the production meant for captive consumption is removed, it would show that the production has been reducing since 2014-15, and in fact has reduced by 15% in the last two years.
- f. Furthermore, it was highlighted that while the increase in demand led to an increase in the sales of the petitioning domestic industry, such increase is nowhere commensurate with the increase in demand. The domestic industry has, therefore, lost out on potential sales due to the dumping of the subject goods.
- g. The inventories of the petitioning domestic industry have built up over the period.
- h. The profitability of the petitioning domestic industry has deteriorated significantly, and it is incurring losses.
- i. The cash profits of the petitioning domestic industry have declined, and its return is negative.
- j. The growth of the petitioning domestic industry in all profitability parameters is negative.
- k. Assuming for the sake of argument that Petitioners are functioning at optimum capacity, dumped imports are still causing injury to the domestic industry. The Petitioners would have no grievance if imports were merely feeding increased demand without eating into its market share. However, in the present case there is decline in market share and Petitioners have been forced to reduce their prices in order to retain its customers.
- l. The argument that increase in captive consumption has led to decreased profits is baseless. However, factually, increase in production on account of increased captive consumption would have helped the Petitioners to achieve better cost efficiency and improved profits if not for the injurious effects of dumping.
- m. In any case, for the purpose of captive consumption, goods are valued at cost plus 10% in line with the requirements of excise law. However, prices for external sales have been made below cost.
- n. Moreover, parameters relating to profitability relate exclusively to merchant sales in the domestic market. Thus, captive consumption has no impact on the same.
- o. The petitioners have segregated the data for domestic and export operations, and have provided the data relating to profits, cash profits, return on investment and other relevant parameters insofar as they relate to domestic operations only. The profitability parameters of the domestic industry, that is, profit / loss, cash profits and return on investment have shown a decline over the injury period.
- p. The claim that injury is caused due to inter-se competition is baseless. The imports account for the major share of the market to the tune of 60%. Thus, imports are the dominant market force in the market directing the price of the subject goods. It is inappropriate to attribute injury suffered by each constituent to the actions of the other.
- q. The reliance on SRF's Annual Report wherein it has been stated that the entry of a new player is likely to lead to squeezing of margins is without merit. Firstly, the sentence is merely an apprehension rather than a statement of fact.
- r. In any case, public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping has contributed injury to the domestic industry since the Annual Report highlight the profitability over one financial year while the investigation pertains to the trends over the injury period, the Annual Report pertains to company's overall operations and not just domestic operations and the Annual Report does not into reasons of dumping which the Authority is concerned with.

- s. The statement in the Annual report of the company is not with regard to product under consideration but the segment, that is, industrial yarn as a whole, whereas the current investigation is with regard to only certain types of industrial yarn.
- t. The depreciation and interest cost have reduced over the injury period. The depreciation and interest costs are affected by the ratio of allocation on the basis of domestic production, sales to export production, sales and show an increasing trend over the injury period. However, the cost per unit, based on Format CI, is not affected by such change in ratios and thus, better reflects trends of increase or decrease in total costs. The profit / loss per unit determined on the basis of such cost shows that the profitability of the domestic industry has declined and it has started earning losses.
- u. The claim of the interested parties regarding causal link between increasing imports and continued positive ROCE is baseless. There are several other factors, which would have an effect on the return earned by the domestic industry; including the price at which the imports have entered in the market, the share of imports in the market, whether the imports have eaten into the shares of the domestic industry, whether the imports have suppressed or depressed the prices of the domestic industry and so on.
- v. The market share of the petitioning domestic industry has fallen post 2014-15, and it has started incurring losses.
- w. The imports suppressed and depressed the prices of the domestic industry, owing to which the domestic industry has incurred significant losses in the period of investigation. It may be noted that while the price undercutting is 8%, the landed price of imports is actually 18% below the cost of production of the subject goods.
- x. The productivity of employees has increased over the period. From a productivity of 84 MT per employee, it has increased to 94 MT per employee. Similarly, the productivity per day has also shown an upward trend. Thus, the contention that there is no increase in productivity is incorrect.
- y. Insofar as the increase in wages is concerned, the increase is merely by 57% over a period of 4 years, which is not abnormal. In any case, wages comprise of only 4-5% of the cost of sales of the subject goods. Thus, the increase in wages would not have any material impact on the movement of cost or profits.
- z. The Petitioners agree with the argument of the interested parties in that the capital employed, insofar as it relates to capacity expansion should not be considered for determination of non-injurious price. However, data on record establishes that investment for capacity expansion is not included in the net fixed assets reported. The Authority has verified the same as well.
- aa. The decline in prices of the Petitioners is much beyond the decrease in cost on account of decline in price of raw materials and has clearly been caused by the dumped imports.
- bb. The imports have entered the Indian market at unduly low prices, forcing the Petitioners to slash its own prices and sell below cost. Despite the reduction in prices, the price undercutting is positive, which is presumably the reason why the market share of the petitioning domestic industry has reduced.
- cc. Regardless of whether market share is considered with or without including captive consumption, it would show that the market share of the petitioning domestic industry is lowest in the period of investigation, as compared to the rest of the injury period.
- dd. The ability of petitioning domestic industry to raise capital investments, insofar as the division producing the subject goods is concerned has been impaired.
- ee. As regard the claims for non-attribution analysis, none of the interested parties have brought forth any positive evidence, which would establish that the injury to the petitioning domestic industry is on account of any other factor. Thus, there is no reason for the Designated Authority to do a non-attribution analysis.



- ff. The Petitioners are unable to comprehend how any historical loss could have caused injury to the petitioning domestic industry in the period of investigation. The data relating to profit / loss, cash profits and return on investment is based solely on the revenue earned and costs incurred during the period of investigation. None of these factors is in any manner affected by any loss made in the past. To the understanding of the petitioning domestic industry, historical losses are only relevant for analysis of trends, and cannot be the cause of injury suffered by the petitioning domestic industry in the period of investigation.
- gg. On one hand the exporter has underlined the increase in production of the petitioning domestic industry, on the other hand it has claimed that decline in exports would have caused an increase in fixed costs per unit. When the production has increased, quite obviously the fixed costs per unit must have declined. Such claims of the interested parties are baseless.
- hh. It is clarified that there has been no change in the total plant capacity of the Petitioners. However, as both product under consideration and other types of yarn are made at the same plant in case of M/s Reliance Industries Limited, the adjusted capacity, insofar as it relates to capacity of the subject goods has been provided. The accuracy and adequacy of the data in this regard has already been verified by the Authority.
- ii. With respect to the claim pertaining to imports from Korea RP and Taiwan, there is no such requirement in the law that the other countries must be selling above the non-injurious price of the domestic industry, or else the causal link would not be established. In the present case, the subject imports have a hold over 60% of the market. Clearly, the price of the subject imports is the driving force in the market. By contrast, the imports from other countries, namely, Korea RP and Taiwan hold only 5% and 3% of the market only. More importantly, it would be seen that the landed price of the subject goods is much higher than the net sales realization of the petitioning domestic industry, and thus, such imports can neither undercut the prices of the Petitioners, nor could have had a suppressing effect. In fact, the landed price of the imports from Korea RP and Taiwan is much higher than the cost of production of the Petitioners.
- jj. There is no way to foresee as to what would be the effect of imposition of duty on import of downstream products such as dipped cords or braided yarns. It may be that the foreign producers of downstream dipped cords and braiding yarns do not have surplus capacities of these goods, and thus, they have no intention of dumping them in the market. Or perhaps, even if such goods are imported, they do not injure the domestic producers thereof. Thus, merely on the apprehension that the imports of dipped cords and braiding yarns may increase post imposition of anti-dumping duty is not enough to deny the petitioning domestic industry rightful protection from the dumped imports of product under consideration.
- kk. Claims that price undercutting is irrelevant when the performance of the domestic industry has improved are baseless. In the present case, in order to retain its customers, Petitioners reduced their selling price in order to compete with the cheap dumped imports. Thus, the imports have had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry is incurring losses, and its return on capital employed is negative. However, despite the petitioning domestic industry slashing its prices, the imports have undercut such prices, due to which the petitioning domestic industry has lost its market share.
- ll. The Authority has been consistently allowing a rate of return at 22% on capital employed for determination of non-injurious price, there is no basis for deviation from such practice. No evidence has been brought on record to establish that 22% ROCE is unjustified in the present case.

#### Examination of the issues by the Authority

74. The Authority has taken note of the submissions made by various interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties, including submissions made post-disclosure.
75. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the

effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

76. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of Antidumping rules states as under:

*(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments*

77. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and thereafter concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not.
78. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the interested parties in their submissions.

#### H.1 Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

##### *Assessment of Demand*

79. The demand of subject goods has been determined by adding the domestic sales of Indian producers of like product with the imports of the subject goods from all countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased over the injury period as can be seen in the table below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (2016-17)
Imports from China PR	MT	5903	7087	9092	13412
Dumped Imports	MT	4939	5719	7784	12241
Undumped Imports	MT	964	1368	1308	1171
Imports from other countries	MT	3768	1928	2105	1950
Domestic Sales of Petitioners	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>120</i>	<i>128</i>
Domestic Sales of other producers	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
<b>Total demand</b>	<b>MT</b>	<b>16470</b>	<b>17072</b>	<b>19104</b>	<b>23716</b>

##### *Import Volumes and Share of Subject country*

80. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject country has been analyzed as under:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (2016-17)
Dumped Imports from China PR	MT	4939	5719	7784	12241
Total Demand	MT	16470	17072	19104	23716
Production of DI	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	114	105	112
Dumped Chinese Imports relative to Indian consumption	%	30%	33%	41%	52%
Dumped Chinese Imports relative to DI production	%	36%	37%	54%	80%

81. Based on the foregoing data, the Authority notes as follows:

- Dumped Imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms from 4939 MT during 2013-14 to 12241 MT during POI.
- Dumped Imports from China PR in relation to domestic consumption / demand have increased, and are at a level of 52% during POI.
- Dumped Imports from China PR in relation to domestic production in India have increased and have reached a level of 80% during POI.

82. It is, thus, noted that the dumped imports of the PUC from the subject country have increased significantly, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

## H.2 Price Effect of the Imports on the Domestic Industry

83. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

*"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."*

84. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. Necessary adjustments have been made in the values to cater to the PUC considering the exclusions granted by the Authority.

### Price Undercutting

85. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (2016-17)
Landed Value	Rs./Kg	125.74	117.24	100.57	94.48
Domestic Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
	% of LV	***	***	***	***
	Range	0-5%	0-5%	0-10%	5-15%

86. The Authority notes from the above table that price undercutting exists. It is also noted that the price undercutting has been significant in the last two years. The price undercutting has increased over the years and it is significantly higher in the POI when compared to the base year.

#### *Price Underselling*

87. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports. Comparison of weighted average NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Particulars	Unit	POI (2016-17)
Landed Value	Rs./Kg	94.48
Non-Injurious Price (NIP)	Rs./Kg	***
Injury Margin	Rs./Kg	***
	USD/ MT	***
	%	***
	Range	10-20%

88. It is seen that the landed price of the subject goods from subject country were significantly lower than the NIP determined for the domestic industry.

#### *Price Suppression/Depression*

89. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	88	84	85
Domestic Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	91	83	80
Landed Value	Rs./Kg	125.74	117.24	100.57	94.48
	Indexed	100	93	80	75

90. Based on the foregoing data, it is noted that the Petitioners' cost of sales declined substantially over the period of injury and POI. However, in relation to the same, the Petitioners' selling price declined more steeply and remained below the cost of sales in the POI. The Authority also notes that the Petitioners' selling price follows

closely with the trend of the Landed Value of the subject imports. Thus, it appears that the Petitioners faced price suppression/ depression owing to the pricing trend of landed value.

91. It has been argued before this Authority that the decline in selling price of the Petitioners is in response to the decline in cost of sales owing to declined raw material prices. However, this does not appear to be the case when the selling price of the Petitioners declines more steeply than own costs. Rather, it is observed that even when the cost of sales increased in the POI, the selling price continued to decline in line with declining landed values.

### H.3 Economic Parameters of the Domestic Industry

92. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

### H.4 Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

93. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Installed Capacity (PUC+NPUC)	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Production (PUC+NPUC)	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>104</i>	<i>110</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>104</i>	<i>111</i>
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>105</i>	<i>112</i>
Domestic Sales of Petitioners	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>120</i>	<i>128</i>
Dumped Imports from China PR	MT	4,939	5,719	7,784	12,241

94. The Authority notes that the Petitioners' capacity utilization, sales and production have seen improvement over the period of injury and POI.

### H.5 Profitability

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Profit / (Loss)	Rs./Lakhs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>59</i>	<i>(141)</i>	<i>(346)</i>
Profit / (loss)	Rs./Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>49</i>	<i>(118)</i>	<i>(271)</i>

95. The Authority notes the following from the above table:

- a. The domestic industry's profitability has been adversely affected. The domestic industry has been in losses during the injury investigation period with the exception of the year 2014-15.
- b. It appears that domestic industry has not been able to recover its cost of sales or earn reasonable profits.

#### H.6 Return on capital employed

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
ROCE	%	***	***	***	***
	Range	(0-5)%	0-5%	(0-5)%	(0-5)%

96. The Authority notes that the domestic industry has not been able to earn an adequate return on capital employed throughout the injury investigation period.

#### H.7 Market Share

97. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Total demand	MT	16470	17072	19104	23716
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>116</i>	<i>144</i>
<b>Market Share of</b>					
- Petitioners	%	***	***	***	***
	Range	30-40%	35-45%	30-40%	25-35%
- Other Producers	%	***	***	***	***
	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
Share of Dumped imports from China PR	%	30%	33%	41%	52%
Share of Un-dumped imports from China PR	%	6%	8%	7%	5%
Share of imports from other countries	%	23%	11%	11%	8%

98. From above table, the Authority observes that the market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. Further, the Authority notes that market share of the dumped imports from the subject country has increased substantially over the injury period.

#### H.8 Inventories

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>136</i>	<i>146</i>
Closing Stock	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>124</i>	<i>133</i>	<i>125</i>
Average Inventory	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>134</i>	<i>135</i>

99. The Authority notes that the Domestic Industry is facing accumulated inventories. The levels of inventories have been increasing as compared to the base year. Due to increasing imports, the market share of the Domestic Industry has come down and the increased demand has been significantly captured by imports. As a result, the Domestic Industry is left with a situation of increasing inventory.

**H.9 Productivity of the domestic industry**

100. The Authority notes that employment level of the domestic industry has remained constant. Further, productivity per employee has improved. Therefore, this cannot be a cause of injury suffered by the domestic industry.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Productivity per Employee	MT/ Employee	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>105</i>	<i>112</i>

**H.10 Ability to raise capital investments**

101. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made significant investments in plant and machinery. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected.

**H.11 Level of dumping & dumping margin**

102. It is noted that imports from the subject country are entering into the country at dumped prices and that the margins of dumping are significant.

**H.12 Factors Affecting Domestic Prices**

103. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc., shows that the landed value of imported goods from the subject country is below the non-injurious price and selling price of the domestic industry, causing significant price under-cutting, price underselling and price suppression / depression in the Indian market. Thus, the primary factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from the subject country.
104. It is thus seen that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject country in absolute terms. The imports have increased significantly in relation to consumption and production of the product in India. Imports have thus increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price under-cutting and price under-selling. Low priced dumped imports have forced the domestic industry to fetch a market price which could not even cover its cost. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been affected during POI.

**H.13 Overall Analysis on Injury**

105. Having regard to the information on record and after examination of the performance of the Domestic Industry, the Authority notes that the dumped imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India. Import prices of the product have very steeply declined within the investigation period. The imports are resulting in price underselling in the market, and are preventing the Domestic Industry from charging its price to a level where the Domestic Industry can recover its cost of production and earn reasonable profits on the investment. The demand for the product increased significantly. However, dumped imports from China PR have taken the major share of increase in demand. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. The profitability has been negative throughout the injury investigation period because throughout the injury investigation period, imports have been coming at very low prices. Inventories increased significantly.

**H.14 Causal Link and Other Factors**

106. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been done as follows:

**(i) Imports from Third Country**

107. The imports from countries other than subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Moreover, the price at which goods are coming from other countries is much higher than the price at which goods are coming from subject country.

**(ii) Contraction in demand**

108. The demand for the subject goods has shown an increasing trend. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry. In fact, the domestic industry has not been able to increase its sale and market share commensurate to increase in demand.

**(iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

109. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**(iv) Developments in technology**

110. The technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

**(v) Changes in pattern of consumption**

111. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

**(vi) Export performance**

112. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In fact, though exports by the domestic industry have declined, the data assessment has been done on the basis of information pertaining to domestic sales alone. Thus, injury on account of domestic sales has been isolated and examined, to the extent possible.

**(vii) Performance of the domestic industry with respect to other products**

113. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only. The Authority has also considered the performance with respect to NPUC, and found that performance in those sectors is not adverse and therefore, there could not have been a spill-over of the same to the PUC.

**(viii) Productivity of the domestic industry**

114. The Authority notes that deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry. Rather, productivity per employee has seen an increasing trend.



**I. Facts establishing causal link**

115. Analysis of the dumped imports and the performance of the domestic industry over the injury period reveals facts stated hereunder:

- Dumped Imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms over the entire period of investigation.
- Dumped Imports of the subject goods from the subject country have increased relative to production and consumption in India.
- Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India.
- Capacity Utilization, Production and Sales of the Domestic Industry have improved over the period of injury and in the POI.
- Inventories of the Domestic Industry have been on the rise.
- There exists Price under-cutting and price suppression / depression due to low priced dumped imports coming in to India.
- The Domestic Industry's profitability has been adversely affected.

**J. Magnitude of Injury Margin**

116. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been determined Petitioner wise and accordingly weighted average NIP has been worked out. The weighted average NIP has been considered for comparing the landed price from the participating producer / exporters and non-cooperative parties for calculating injury margin.

117. The injury margin for the participating producers/exporters and non-cooperative parties is as under:

**Injury Margin**

Country	Producer	Exporter	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin Range %
China PR	Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Hyosung Corporation	***	***	***	***	Negative
China PR	1. Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd.  2. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.	Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd., China PR	***	***	***	***	10-20
China PR	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.	***	***	***	***	15-25
China PR	1. Huzhou Unifull Industrial Fibre Limited. 2. Zhejiang	Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30

Country	Producer	Exporter	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %	Injury Margin Range %
	Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.						
China PR	Oriental Industries (Suzhou) Ltd.	Oriental Textile (Holding) Ltd.	***	***	***	***	Negative
China PR	Any other combination	Any other combination	***	***	***	***	45-55

118. The level of dumping margins and injury margins as determined are significant except for Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. and Oriental Industries (Suzhou) Ltd.

**K. Indian Industry's Interest & Other Issues**

Views of the producers/exporters, importers and other interested parties regarding the injury claims of domestic industry

119. The submissions made by the exporters/importers/other interested parties during the course of the investigation with regard to the public interest and considered relevant by the Authority are as follows:

- The subject industry faces a substantial demand and supply gap and imposition of duty would be unduly burdensome on the domestic market to whom the Petitioners cannot fully supply.
- The Petitioners cater to a mere margin of the domestic demand, amounting to less than 50% of the demand. Thus, imposition of the duty would be unduly burdensome.
- The Petitioners, specifically SRF, is likely to increase its captive consumption leading to an aggravated demand-supply gap.
- The Petitioners are attempting to create a monopolistic, anti-competitive market where after they will be capable of maintaining product prices at high levels, which would be detrimental to economic development of the country.
- The Petitioners are prone to delays and disruptions in supply of the subject goods, thus making reliance on them quite impossible. There are several instances in past in which supplies from the Petitioners have been stopped due to various reasons.
- The Petitioners face various quality issues which has compelled users of the subject goods to rely on imported goods. Even the Petitioner (SRF) itself is an importer of the subject goods.

Views of the domestic industry

120. The following are the submissions with regard public interest made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:

- It is by now a well settled principle of law that demand-supply gap is not a ground for non-imposition of anti-dumping duty. The purpose of imposition of anti-dumping duty is to remove the unfair advantages gained by the exporters through dumping of the subject goods. The duty imposed only establishes fair competition and would not serve to restrict the availability of goods in the market, as there is no bar on imports. The consumers can nevertheless maintain multiple sources of supply. Therefore, there is no threat regarding the lack of supply of the subject goods in the Indian market due to imposition of anti-dumping duty.

- b. Moreover, RIL has undertaken major capacity expansion post period of investigation to the extent of 27,000 MT per annum, post which the issue of demand-supply gap would also be addressed.
- c. The domestic industry would never be in a position to create a monopolistic situation which would allow it to charge anti-competitive prices, as the imports from the subject countries and other countries would serve to act as a check to any such anti-competitive practice. In any case, where there is more than one producer, monopolistic conditions would not prevail in the market.
- d. The submission that there is irregular supply by the Petitioners is without merit. If the domestic industry had been unable to fulfill its orders, the sales of the domestic industry would have decreased. However, that has not been the case, and despite the imports coming in at unduly cheap prices, the domestic industry has been able to market its products, albeit at the cost of deteriorating profitability. This increase in sales would not have been possible in a situation where the consumers of the goods were not assured of timely delivery of the goods.

#### Examination of the Authority

- 121. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
- 122. As for the quality issues cited, the Authority finds that the importers would continue to be able to import the subject goods at fair prices and therefore, would not be left at the mercy of Petitioners in any case. Therefore, such claims are not reasonable.

#### L. Post Disclosure Statement Submissions by Interested Parties

Submissions made by the foreign producers/exporters, importers and other interested parties

- 123. The producers/exporters, importers and other interested parties in their post disclosure submissions have raised the following issues. For the sake of brevity, submissions made earlier and addressed in the disclosure statement are not being repeated.
  - a. With respect to PUC, certain interested parties have claimed that the testing criterion for yarns with HMLS properties merits correction for the sake of technical completeness and correctness. Accordingly, it is stated that the Authority may revise the definition of Dimensional Stability Index to read:
 

*“The Dimensional Stability Index is measured as the sum of elongation at 4cN/dtex (Tested as per ASTM D885) and hot air shrinkage at 177°C for 2 minutes at 0.05cN/dtex end load (Tested as per ASTM D4974).”*
  - b. With respect to PUC, certain interested parties have sought/ reiterated claims for exclusions of the following products:
    - i. Adhesive Activated Yarns having denier 1000 on the ground that the Petitioners’ are captive consumers of the same, are not supplying the same to the domestic market and Petitioners’ production and sale merit analysis;
    - ii. Regular High Tenacity Low Shrink (HTLS) yarn having 1000 deniers on the grounds that the Petitioners are captive consumers of the same and not merchant sellers of the particular goods;
    - iii. High Tenacity Yarns having denier more than 6000 on the ground that the Petitioners are incapable of production of these goods and they have been imported into India. Contrary to the

Authority's observation, flat yarn, i.e., untwisted yarn, having denier more than 6000 have been imported.

- c. Interested parties submitted that the criteria to be adopted for the determination for inclusion or exclusion of the captive domestic producer from the purview of the domestic industry is the production of the subject goods and not the capacity. It is reiterated that the examination of captive production by SRF is of significance in the current investigation as their major and substantial production of the subject goods is used for the captive consumption. Reference was also made to the Final Findings of the Authority in *Low Ash Met Coke from Australia and China PR (2016)*.
- d. The Authority may specify the breakup of SRF's imports under Advance License and Duty paid as compared to the production by SRF. It was also claimed that SRF failed to supply reasons that lead to such imports and the same needs examination. The Authority must consider SRF's importation including any imports under the Advance Authorization Scheme.
- e. The Authority must confirm whether the Petitioners' "production" being considered by the Authority is dedicated capacity for the manufacture of subject goods or whether it also includes capacity for the manufacture of other goods.
- f. Producers and exporters from China PR shall automatically obtain the market-economy status after 11<sup>th</sup> Dec. 2016. Accordingly, the Authority should not adopt the "surrogate country" practice in this case. After 11<sup>th</sup> Dec. 2016, the members of WTO shall automatically treat China PR as a "market economy". No additional information shall be needed to determine the market economy status of China PR.
- g. Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd., China PR requested that Normal Value may be constructed as per information reported by them in view of the fact that the period of 15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11<sup>th</sup> December 2016 in terms of para 15(d).
- h. Without prejudice to the above, Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd., China PR also requested that its normal value may be determined on the basis of the records of the Chinese producer who has been granted MET in the present investigation as it would be the most reasonable basis for the determination of normal value.
- i. The public version of Petition and the Disclosure Statement does not sufficiently disclose information especially regarding the differences among each companies' dumping margin and injury margin.
- j. Zhejiang Unifull and Huzhou Unifull's cost is in accordance with the market price of the raw material, and their price of the product concerned is consistent with the market price of the product concerned for export sales and domestic sales. Even the production process is similar to other producer / exporter in China PR. Thus, it is unclear why the dumping margin and injury margins for Zhejiang Unifull and Huzhou Unifull is much higher than other cooperating companies. In this regard, it has also been claimed that crucial data has been kept confidential and insufficiently summarized in the Disclosure Statement.
- k. The Authority has provided the names of producers/ exporters who have filed responses, however, the same does not mention the company Oriental Industries (Suzhou) Ltd. Instead, the company is mentioned under "*Other than such parties, comments were also received from the following parties, and have also been considered*". It is unclear how a producer/ exporter that did not file Questionnaire Response or MET Questionnaire has received negative margins.
- l. The DI has merely stated that there is a price undercutting and there is a price depression as a result of alleged imports from China PR. However, it is common industry knowledge that the price of the subject goods is mainly determined by the raw materials i.e., PTA & MEG / Polyester Chips and the subject goods prices fluctuate along with the fluctuation of the PTA & MEG / Polyester Chips prices. It is also common industry

knowledge that the cost of raw materials PTA & MEG / Polyester Chips constitutes about 80% to 90% of the total the production cost of High Tenacity Yarn. Therefore, whenever there is a decline in the prices of raw materials PTA & MEG / Polyester Chips, the price of the subject goods also declines and vice versa. This is precisely the situation in the current investigation, the decline in the prices of the domestic industry is as a result of the decline in the prices of raw materials PTA & MEG / Polyester Chips but not due to the alleged dumped imports from China PR.

- m. Mere existence of parallel pricing trends during injury investigation period between subject imports and the domestic prices does not, by itself, constitute sufficient evidence to demonstrate the existence of price effect. The Authority must consider the trends of raw material prices, global pricing trends and such other factors to determine *why* the pricing trends move in a certain manner. Reference was made to the WTO Appellate Body Report in *China-GOES*.
- n. The Authority has failed to record or disclose the data pertaining to the Petitioner's market share and therefore, an isolated consideration of just the price of imports and net sales price of the domestic producer would not be indicative of the injury or lack thereof to the Petitioners. Reliance was placed on the CESTAT's observations in *Bridgestone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority* (2011).
- o. Market Share of the Petitioners must be analysed in light of captive consumption. Specifically, sales, market share and demand including captive consumption should be established. The same would indicate lack of injury to the Petitioners.
- p. There is improvement in the economic parameters such as capacity, output and capacity utilization, sales without captive consumption has increased by 28% over the injury investigation period, productivity increased by 12% and overall growth.
- q. There is absence of injury on account of allegedly dumped imports evidenced by the increase in key volume parameters of the domestic industry such as production, sales, etc. despite positive undercutting and increased imports.
- r. PCN wise assessment of injury parameters, specifically the key profitability parameters, should be undertaken to account for the existence of inter-se types in the PUC.
- s. The Petitioners' number of employees is stable but wages have increased substantially. However, there is no assessment in this regard.
- t. The Petitioners' inventory should be assessed with respect to their production for objective analysis of injury.
- u. The Petitioners' negative profitability is due to increase in wages cost as well as increase in interest and depreciation cost as the capital employed of the domestic industry increased by 12% during the injury investigation period indicating that there is no impact on the profitability of the domestic industry due to alleged subject imports.
- v. The ability to raise capital investments is not a meaningful factor in the current investigation since the subject product constitutes very small share of the total revenue for the Petitioners who are multi-product companies.
- w. The Authority should adopt actual profit earned by the DI during a period when dumping was not alleged and not 22% ROCE. Basis of 22% ROCE designed in the year 1987, when all parameters like interest rate and corporate tax were different, cannot be termed as reasonable after 30 years in the year 2016. In 1987 the rate of interest was around 18% and corporate tax was 40%. Now both interest rate (around 10%) and corporate tax (30%) have come down. Therefore, it is submitted that by applying 22% ROCE, DGAD is giving undue protection to the Domestic Industry.
- x. With respect to causal link, interested parties have submitted that the non-attribution analysis is inadequate. In this regard, it is submitted that:

- i. The Authority has not considered the historical losses of the domestic industry and inter-se competition among the domestic producers, the decline in the prices of PTA and MEG / Polyester Chips and the poor export performance of the applicant producers.
  - ii. The Authority must examine the possibility of self-inflicted injury by virtue of SRF's imports.
  - iii. The Authority must examine the impact of significant increases in captive consumption of the Petitioners.
  - iv. The Authority must examine the impact of the significant decline of export sales of the Petitioners.
  - v. The Authority must consider the reasons for change in consumption/ sales patterns of the Petitioners- switching from merchant market to captive consumption and poor export performance.
  - vi. The Authority must consider the impact of inter-se competition between the domestic producers of the like article.
  - vii. The Authority must assess the impact of imports from Korea RP and Taiwan, both of which are more than *de minimis*.
  - viii. The increase in the wages quantum of the Petitioners' cost without any increase in number of employees or commensurate increase in productivity.
- y. Certain interested parties have sought for correction of name in the duty table. In this regard, it has been claimed that the following rectification may be introduced in the Final Findings:

<b>Incorrect Name recorded in Disclosure Statement</b>	<b>Corrected Name to be recorded in the Final Findings</b>
Oriental Industries Holding Ltd.	Oriental Textile (Holding) Limited
Hyosung Chemical Fibre (Jiaxing) Co. Ltd.	Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Corporation, Korea RP	Hyosung Corporation

- z. Oriental Industries (Suzhou) Limited has also directly exported the subject products to India rather than only through Oriental Textile (Holding) Limited. Therefore, the Authority may consider the inclusion of Oriental Industries (Suzhou) Limited as producer and exporter, rather than just producer in the duty tables.
- aa. In the recent time, the exporters have increased the prices of all articles. This shows that the Petitioners are capable of selling their goods independent of the pricing of the imports. It also shows that the DI is experiencing better health. The same must be duly considered. Levy of duty as % on the price will be detrimental to the user industry. The Authority must reconsider the imposition of any duties and must consider imposition of benchmark duties rather than fixed duties.
- bb. Implementation of anti-dumping measure will influence the Indian downstream industry negatively, with the demand on the rise. If the subject goods were suddenly blocked from the Indian market because of anti-dumping duty, Indian downstream industry will inevitably suffer from negative influence such as insufficient supply, much higher purchase price and lower profits or suffering loss.

Submissions made by the Domestic Industry:

124. The domestic industry, in its post disclosure submissions has submitted as follows. For the sake of brevity, comments made by the domestic industry, to the extent they are reiterations of the earlier submissions and already dealt with in the disclosure statement, have not been repeated hereunder:

- a. The Authority may kindly disclose the non-confidential version of the verification report of the exporters/producers from subject country. Where verification report has not been issued, Authority must disclose facts regarding cost of production, valuation of captive inputs, transactions between affiliated parties, completeness of the questionnaire response in the sense of value chain requirements, export price in view of vast variation in the import prices of different transactions, etc.
- b. Petitioners believe that the Authority directed exporters to file certain information to examine various issues and in case the exporters have filed any information in response, apart from the original questionnaire responses, then there is direct violation of Rule 7 of the AD Rules and trade notices of the Authority since no non-confidential versions were filed.
- c. The dumping margin determined for responding exporters are materially lower than the dumping margin determined by the petitioner and even negative for two exporters. The Petitioners are unable to advance their defence.
- d. The Authority must make available a copy of all the communications sent via mail or letter, to the opposing interested parties and replies filed by these interested parties. At least the non-confidential versions of the same must be disclosed.
- e. The Authority must disclose injury parameters to the Petitioners, since the same is based on the data submitted by the Petitioners themselves.
- f. The Authority should disclose the Normal Value since it is based on the domestic industry data (except for one exporter).
- g. The Petitioners have also claimed that, in the case of participating exporters, the disclosure of actual dumping margin does not mean disclosure of either normal value or export price.
- h. Determination of Constructed Normal Value which is based on domestic industry's cost of production should be disclosed as the normal value determined in the disclosure statement is materially lower than the calculations done by the petitioner and that too when the normal value is based on petitioner's data.
- i. Petitioners oppose exclusion of Adhesive Activated (AA) yarns with denier higher than 1000 and yarns with HMLS properties.
- j. Adhesive Activated (AA) yarns with denier higher than 1000 should have been included as the same is produced and small quantities of the same have been sold as well. Yarns, such as those having 2000 D are nothing but doubling of 1000 denier yarn. Therefore, 2000, 3000, and likewise other deniers fall under the same category. Reference was made to letter filed by the Petitioners earlier providing evidence of production of 730 MT AA yarns which had to be exported owing to lack of demand in the country.
- k. With respect to the exclusion of yarns with HMLS properties, the Petitioners have been approaching customers for selling HMLS yarn. However, customers did not respond or show interest. One of them responded stating that DI prices are too high.
- l. Petitioners also provided evidence of facilities for production and sales of HMLS and Regular High Tenacity and Low Shrinkage yarns.

- m. Petitioners provided evidence that comparison of the technical properties of Petitioners' products and that of Chinese suppliers Guxiandao and Unifull shows no difference between the same.
- n. Petitioners submitted that SRF produces HMLS for captive consumption as well as industrial application. However, the captive consumption of HMLS was less than 25% of installed capacity during the POI.
- o. Petitioners dispute the grant of MET to one of the exporters. In this regard, it submitted that merely because the company is not a Chinese company does not imply that it is entitled to MET. Reference was placed on the final findings of the Authority in *Digital Printing Plates* wherein MET was not granted to Kodak and Fuji.
- p. Additionally, Petitioners have raised claims regarding the deduction of SGA & Profit of related trader, Hyosung Corporation, from the export price calculated for Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
- q. As the NIP has been determined on the basis of the data of the domestic industry, petitioner requests disclosure of detailed break up of NIP determined to enable the petitioner to provide comments on the same.
- r. Petitioners find huge difference and reduction in the net fixed assets considered for determination of capital employed as reported by petitioners and the amounts considered in the disclosure statement. Such *suo moto* reduction is inappropriate, unjustified and prejudicial.
- s. The Petitioners had made submissions regarding the working vide email dated 04/05/2018, however, the same has nowhere been discussed or considered in the Disclosure Statement.
- t. Domestic industry submits that the form of anti-dumping duty should be fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty).
- u. Petitioners request the Authority to reaffirm its findings as established in the Disclosure Statement with respect to standing of the domestic industry, injury analysis and analysis pertaining to causal link and non-attribution.

#### **Examination of the Authority**

125. The Authority notes that most of the submissions by parties are of repetitive nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above deal with all such arguments of the interested parties including Domestic Industry. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.
- a. The Authority has considered the interested parties' submission pertaining to the testing criterion for yarns with HMLS properties. Accordingly, the correction has been incorporated under the assessment for "Product Under Consideration".
  - b. In the disclosure statement, the Authority had not considered the exclusion for yarns having denier more than 6000, on the understanding that such yarns are actually twisted yarns. In the post disclosure comments, interested parties have brought evidence to the notice of the Authority regarding imports of flat/untwisted yarns having denier more than 6000. In light of the same, and the absence of Petitioner's production or sales of the said goods, the Authority has reassessed this issue and recorded its observations under "Product Under Consideration".
  - c. The Authority has considered the interested parties' submissions pertaining to the exclusion of high tenacity low shrinkage yarn having denier 1000 and Adhesive Activated Yarn having denier 1000. Even though the claims for such exclusion were raised for the first time at such a belated stage, the Authority has assessed the same. The Authority finds that the Petitioners are producing and selling such yarns and therefore, the claims raised by the interested parties pertaining to exclusion of AA yarns having denier equal to 1000 and High Tenacity Low Shrinkage Yarn having denier equal to 1000 are rejected.



- d. While conducting injury assessment, the Authority has considered the Petitioners PUC as well as NPUC production for ascertaining capacity utilization.
- e. The interested parties' submissions pertaining to market economy treatment of China PR are reiterations of the same submissions made earlier during the course of the investigation. The same have been assessed by the Authority in detail under the appropriate paragraphs.
- f. Jiangsu Hengli's request for computation of normal value based on the normal value for the producer which has been granted MET is without merit. The Authority has constructed normal value for all participants who have not claimed MET in terms of the consistent practices of the Designated Authority. Moreover, it is noted that the producer / exporter who has been granted MET is a supplier of only one PCN, therefore, their normal value could not have been utilized as a reasonable standard for other producers / exporters who have exported a mix of various PCNs.
- g. Zhejiang Unifull and Huzhou Unifull raised certain queries pertaining to the reasons why there was substantial difference between the dumping margin and injury margin determined *qua* them and other participating producers. In this regard, the Authority has considered PCN wise information for computing the dumping margin and injury margin, based on actual information submitted and verified for each of the participants.
- h. The Authority notes that Questionnaire responses were duly filed by Oriental Industries (Suzhou) Ltd. and its trader, Oriental Textile (Holding) Ltd. The dumping margin and injury margin for these companies has been determined based on their Questionnaire responses.
- i. The Authority notes that submissions pertaining to the assessment of price suppression and depression and the comparison of price trends vis-à-vis pricing trends of raw materials PTA and MEG have been considered by the Authority in its assessment of "*price suppression/depression*". It is noted that the Petitioners experienced steeper decline in selling price as compared to cost of sales (which includes raw material prices). The Authority notes that there is price suppression in the present case.
- j. The Authority notes the interested parties' submissions regarding non-disclosure of the market share of the Petitioners. Such a submission is misplaced. The Authority has provided the market share of the Petitioners as a narrow range, sufficient to allow comprehension of the trends as well as the assessment of the Authority.
- k. The Authority notes the suggestion to conduct PCN wise injury assessment. The Authority has conducted PCN wise assessment of dumping margin and injury margin, in line with the consistent practice of the Authority. Beyond this, there is no requirement to conduct a PCN wise assessment of injury parameters.
- l. The Authority notes that various submissions have been raised in reiteration of arguments made with respect to the assessment of injury parameters. The same had already been addressed in the disclosure statement. The assessment with respect to these claims is under "Determination of Injury and Causal Link".
- m. With respect to claims regarding the consideration of a lower return on capital employed (ROCE), the Authority notes that ROCE has been considered as 22% for determination of NIP in line with the consistent practice of the Authority.
- n. With respect to non-attribution claims reiterated by the interested parties at the post-disclosure stage, the Authority has duly considered the Petitioners data to determine whether there is self-inflicted injury by virtue of SRF's imports. However, the same are marginal and did not contribute to the losses and injury suffered by the Petitioners.
- o. The Authority considered the reasons for significant increase in captive consumption of the Petitioners. It was noted that the same, if anything, has contributed to the stability in the Petitioners' profitability parameters rather than cause any injury. In light of declining sales, the Petitioners' increased captive consumption appears to be reasonable.

- p. The Authority notes that the Petitioners' injury is not attributable to inter-se competition between the domestic producers of the like article. It is noted that the product portfolio of the Petitioners is distinct from each other to a substantial degree and therefore, the injury suffered across the board cannot be attributed to performance of the other petitioner.
- q. The Authority notes that the name of certain producers/ exporter had been incorrectly recorded in the duty table. This was inadvertent and the same has been rectified in the present findings.
- r. Oriental Industries (Suzhou) Limited has claimed that it is a producer- cum-exporter. However, such a claim is incorrect. The Authority has assessed the same under "Export Price for Oriental Industries (Suzhou) Limited (OTIZ) and M/s Oriental Textiles (Holding) Limited China PR".
- s. With respect to the claims of interested parties regarding the increase in export prices recently, it is noted that the dumping margin and injury margin are based on data pertaining to the period of investigation. The increase in export prices subsequent to the period of investigation cannot be considered for the purposes of the present investigation.
- t. With respect to the claim pertaining to public interest and injury of the downstream industry, the Authority reiterates that imposition of duties do not act as a barrier to trade. Rather, it is targeted towards unfair trade practices of certain producers and exporters and serves to even the playing field between foreign producers and suppliers on the one hand and the domestic producers and suppliers on the other.
- u. Certain claims have also been raised by various interested parties and the Petitioners that excessive confidentiality has been exercised in the issue of Disclosure Statement itself. Such claims are baseless. The Authority has provided all information considered to be non-confidential. Moreover, indexed figures have been provided with respect to confidential information, wherever necessary.
- v. With respect to the Petitioners' request for disclosure of communications with exporters, verification reports and information filed post-original questionnaire response stage, it is noted that there is no legitimacy to this request. The Authority notes that such documents contain confidential information of the exporters and such report is not disclosed by the Authority in any anti-dumping investigation. Moreover, even the documents collected from the Petitioners as well as the verification report of the Petitioners are considered to be confidential and the same are not supplied to other parties to the investigation.
- w. The data filed by the producers/ exporters and by the Petitioners as rectification during verification does not change the data in effect such as to alter the non-confidential versions filed. Moreover, the Authority has sought establishment of certain claims, which has been done through supporting documentation provided by the interested parties, including the Petitioners. Summarization of such data is not possible and therefore, no NCVs were sought or filed.
- x. The Petitioners have sought for disclosure of the dumping margin. In this regard, the Authority notes that the dumping margin cannot be disclosed. This is in line with the consistent practice of the Authority.
- y. With respect to the Petitioners' opposition relating to exclusion of AA yarns having denier more than 1000 and yarns having HMLS properties, the Authority has examined the same in detail under "Product under Consideration". In addition, the Petitioners' evidence supplied regarding manufacture of Adhesive Activated Yarns by them, it is noted that the same includes AA yarns having denier equal to and also more than 1000. However, it is not the case that all Adhesive Activated yarns have been excluded from the scope of the product under consideration. Rather, consideration has been given to the fact that the Petitioners are producers and suppliers of AA yarn having denier equal to 1000 and the same have not been excluded from the scope of the product under consideration.
- z. With respect to the Petitioners' opposition to the grant of market economy treatment merely because the company is not a "Chinese" company, the Authority notes that the Petitioners are misguided. The Authority has conducted a detailed assessment of the producer and exporter claiming MET. The assessment in this

regard is contained under “Market Economy Treatment for M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR and M/s Hyosung Corporation, Korea RP”. The Authority also notes that assessment for the grant of MET is done on a case to case basis and therefore, would vary depending upon the factual matrix present in each scenario.

- aa. The Authority notes that the export price for Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. has been considered after due adjustments, including the reduction of SG&A expenses and profits of the related trader, Hyosung Corporation.

#### **M. Recommendations**

126. The essential facts gathered by the Authority during the course of the investigation, and as established by the Authority on the basis of information received from various sources were duly disclosed in the Disclosure Statement, in order to enable the various interested parties to offer their comments on these facts gathered by the Designated Authority. Accordingly, comments were received and have been considered over the course of the present findings.
127. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the Domestic Industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends anti-dumping duty on imports of subject goods from subject country in the form and manner described hereunder.
128. With regard to duty structure, taking into account the factual matrix of the case and having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties, it is deemed appropriate to recommend fixed form of anti-dumping duty denominated in US\$. Further, having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury for a period of five (5) years, so as to address the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from China PR:

**Duty Table**

SN	Heading/ Sub heading	Description of Goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount of duty	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5402.2090*	High Tenacity Polyester Yarns excluding yarns having denier below 1000 and above 6000, Twisted yarns, Coloured yarns, Adhesive Activated yarns with denier higher than 1000 and Yarns with HMLS properties.	China PR	China PR	Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Hyosung Corporation	NIL	MT/US\$
2.	- do -	- do -	China PR	China PR	1)Zhejiang Guxiandao Industrial	Zhejiang Guxiandao Industrial	174	MT/US\$

SN	Heading/ Sub heading	Description of Goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount of duty	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Fibre Co., Ltd. 2) Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.	Fibre Co., Ltd.		
3.	- do -	- do -	China PR	China PR	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.	234	MT/US\$
4.	- do -	- do -	China PR	China PR	1) Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. 2) Huzhou Unifull Industrial Fibre Limited.,	Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.	316	MT/US\$
5.	- do -	- do -	China PR	China PR	Oriental Industries (Suzhou) Ltd	Oriental Textile (Holding) Ltd	NIL	MT/US\$
6.	- do -	- do -	China PR	China PR	Any combination other than S. No. 1 to 5		528	MT/US\$
7.	- do -	- do -	China PR	Any	Any	Any	528	MT/US\$
8.	- do -	- do -	Any	China PR	Any	Any	528	MT/US\$

*\* Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC*

129. *An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.*

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority